हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

24 मार्च, 2006

खण्ड–2, अंक–6

अधिकृत विवरण

विषय सूची

शुक्रवार, 24 मार्च, 2000

पृष्ठ संख्या

तारांकित प्रश्न एवं उतर	(6) 1
बाक आउट	(6) 19
नियम 45 (1) के अधीन सदन की भेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(6) 20
सचिव द्वारा घोषणा	(6) 32
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव–	6(22)
गुडगांव में प्रदूषण संबधी वाक आउट	(6) 23
वक्तव्य–	(6) 24
उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी विजली मंत्री द्वारा नियम 16 के अधीन प्रस्ताव	(6) 26
विधान समा की समितियों की रिपोर्ट्स प्रस्तुत करना–	(6) 27
(1) आश्वासन समिति	
खिलाड़ियों को बधाई	(6) 27

विधान सभा की समितियों की रिपोर्ट्स प्रस्तुत करना (पुनरारम्भ)	(6) 27
(2) अनुसूचित जातियों/जनजातियों तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति	
(3) लोक लेखा समिति	
(4) लोक उपक्रम समिति	
सदन की मेज पर रखे गए कागज पत्र	(6) 29
विधान कार्य	(6) 28
दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (नं. 1) बिल 2006 दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (नं. 2) बिल, 2006	
अति विशिष्ट व्यक्ति का स्वागत	(6) 62
दि हरियाणा .एप्रोप्रिएशन (नं. 2) बिल, 2006 (पुनरारम्भ)	
बैठक का समय बढाना	(6) 66
दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (नं. 2) बिल, 2000 (पुनरारम्भ)	
श्रीमती सोनिया गांधी के त्यागपत्र सम्बन्धी संकल्प	(6)70
विधान कार्य (पुनरारम्भ)	(6)73

दि हरियाणा स्टेट लैजिस्लेचर (प्रिवैंशन आफ बिसक्वालिफिकेशन) अमैंडमैंट बिल 2006	
बैठक का समय बढ़ाना	(6)74
विधान कार्य	(6)76
दि हरियाणा स्टेट लैजिस्लैचर (प्रिवैंशन आफ डिसक्वालिफिकेशन) अमैंडमैंट बिल, 2006 (पुनरारम्भ)	
दि हरियाणा म्यूनिसिपल कार्पोरेशन (अमैंडमैंट) बिल, 2006	
दि इंडियन स्टैम्प (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 2006	
दि हरियाणा म्यूनिसिपल (अमेडर्मट) बिल, 2006	
गुरु जम्भैश्वर यूनिवर्सिटर हिसार (अमैंडमैंट) बिल, 2006	
दि हरियाणा कोआप्रेटिव सोसायटीज(अमैंडमैंट) बिल, 2006	
बैठक का समय बढ़ाना	(6) 84
विधान कार्य	(6) 84
दि हरियाणा कोआप्रटिब सोसायटीज (अमैंडमैंट) बिल, 2006 (पूनरारम्भ)	
धान्वाद देना	(6)85

हरियाणा विधान सभा

शुक्रवार, 24 मार्च, 2006

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (डॉ० रघुवीर सिंह कादियान) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्षः ऑनरेबल मैम्बर्ज, अब सवाल जवाब होंगे।

Irregularities in Selection of S.S. Masters and School Cadre Lecturers

***351 .Shri Karan Singh Dalal:** Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) whether the state government has received any complaint in regard to the irregularities committed in the selection of S.S. Masters and School Cadre lecturers during the last five years, if so, the details thereof and ;

(b) whether any enquiry has been conducted in this regard; if so, the action taken thereon ?

Education Minister (Sh. Phool Chand Mullana): (a & b), Yes, Sir.

Some persons had challenged the selection of some candidates, who were given appointment in 2004-05 to the post of Social Studies Master before the High Court. Based on

the direction of the High Court, the Inquiry Officer has been appointed to enquire into the allegations. Vigilance Department, Hisar is also enquiring into some complaints regarding the selection of handicapped category of masters' category. Reports from both the inquiries are awaited.

श्री कर्ण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जवाब में भी यह बात मानी है कि पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में इस सिलैक्शन को चेलैंज किया गया है। इसके अलावा हैंडीकैप्ट टीचर की कैटेगरी की भी इनके पास शिकायत है। अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री जी को इस बारे में मालूम है कि श्री संजीव कुमार, आई०ए०एस० ने जे०बी०टी० के सिलैक्यान को सुप्रीम कोर्ट में चेलैंज किया है उन्होंने उस रिट पैटीशन में भी यह इल्जाम लगाया है कि जिस प्रकार पिछली सरकार ने जे०बी०टी० की सिलैक्यान की मैरिट को बदला था उसी प्रकार स्कूल लैक्चरर्ज और एस०एस० मास्टर्ज की जो मैरिट लिस्ट बनी थी, उसको भी बाद में उस सरकार द्वारा बदला गया था और नई लिस्ट तैयार की गई थी? क्या ये इस बारे में कोई जांच कराने के लिए विचार करेंगे?

श्री फूल चन्द मुलानाः अध्यक्ष महोदय, यह मामला एस०एस० मास्टर्ज के सिलैक्यान से संबंधित है, इस बारे में जांच चल रही है। अगर दूसरे सिलैक्शन के बारे में कोई कम्पलेंट आयेगी तो उसकी भी सरकार से जांच करवायेंगे।

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, नये सिरे से तो शिकायत का इसमें इसलिए औचित्य नहीं बनता क्योंकि इसके बारे में रिट पैटीशन में पहले ही श्री संजीव कुमार जी ने जिक्र किया हुआ है। उस रिट पैटीशन की कापी सरकार मंगा ले और इस बारे में कार्यवाही कर ले अगर सरकार को कापी नहीं मिलती है तो यह मैं दे दूंगा। उन्होंने अपनी रिट पैटीशन में कैटेगोरिकली यह कहा है कि पिछली सरकार के समय में जो एस०एस० मास्टर्ज, स्कूल लैक्चरर्ज का और जे०बी०टी० का मैरिट पर सिलैव्यान हुआ था उसकी मैरिट लिस्ट को जबरदस्ती बाद में पूरी तरह से बदल दिया था।

Mr. Speaker: Dalal Sahib, ask your supplementary.

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि जो चौटाला साहब के खिलाफ सी०बी० आई ० को जांच करने के लिए सरकार ने सिफारिश की है और सी०बी० आई० ने जांच शुरू कर भी दी है तो क्या एस०एस० मास्टर्ज और स्कूल लैक्चरर्ज के सिलैक्शन की लिस्ट की जाँच को भी सी०बी० आई० को सौंपने पर सरकार विचार करेगी?

Shri Phool Chand Mullana: Speaker Sir, Hon'ble Member has said that a Writ Petition has been filed by Mr. Sanjeev Kumar. Now, this is subjudice matter. Whatever the decision of the Court will be, that will be implemented and so far as CBI enquiry is concerned, that has got a separate

reference.

श्री राधेश्याम शर्मा अमरः अध्यक्ष महोदय, इस बारे में सारा हाउस जानता है कि रिपोर्ट आ चुकी है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि सरकार को उस रिपोर्ट को सुओ मोटो लागू करने में क्या परेशानी है?

श्री फूल चन्द मुलानाः अध्यक्ष महोदय, इस बारे में जो शिकायत सरकार को मिली है उसकी जांच चल रही है। जो डिपार्टमैंटल जाँच चल रही है उसकी रिपोर्ट एक महीने में आनी एक्सपैक्टिड है जो विजीलैंस वाली रिपोर्ट है That report is expected within a month. It will take some time. Some persons have been arrested in this regard. Whatever further complaints will be received, those will be enquired into.

श्री एस०एस० सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने जवाब में दो बातें बताई हैं। एक तो कहा कि हाई कोर्ट के कहने पर इन्क्वायरी शुरू कर रखी है और दूसरा बताया कि हिसार में विजीलैंस ने इन्वैस्टीगेशन शुरू कर रखी है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इन्होंने जो इन्क्वायरी आफिसर मुकर्रर किए हैं वे कौन हैं। कौन से महीने में उनको इन्क्वायरी आफिसर मुकर्रर किया गया था और इस समय यह केस किस स्टेज पर है। केस का रजिस्ट्रेशन विजीलैंस डिपार्टमैंट में कौन सी तारीख को हुआ है और अब किस स्टेज पर है। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मैं मंत्री जी से यह भी पूछना चाहता हूँ कि इस

सिलैक्शन के दौरान एक डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन आफिसर की डैथ हो गई थी जो भी उसने लिखा था वह बदला गया और उसके झूठे साईन उसके मरने के बाद किए गए। क्या इस तरह की बात मंत्री जी की नॉलेज में है। यदि है तो क्या मंत्री जी जिस किसी ने भी ऐसा किया है उनके खिलाफ क्रिमीनल केस दर्ज करवायेंगे?

श्री फूल चन्द मुलानाः अध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय साथी ने पूछा है कि इसकी दो इन्क्वायरी अलग–अलग क्यों चल रही हैं। मैं इनको बताना चाहूँगा कि विजीलैंस और डिपार्टमैंटल दो इन्स्पायरीज चल रही हैं। एक इन्स्पायरी तो regarding appointment of 1279 S.S. Masters है ड्समें से 33 आदमियों की सिलैक्यान हाई कोर्ट में चौलेंज की गई और हाई कोर्ट ने आदेश दिए कि हम 6 महीने में इन्क्वायरी रिपोर्ट सबमिट करें। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने अभी बताया है कि एक महीने में इनकी इन्क्वायरी रिपोर्ट आ जायेगी। जहां तक मेरे साथी ने इन्क्वायरी आफिसर के बारे में पूछा है मैं बताना चाहूँगा कि श्री के०के० खण्डेलवाल, आई०ए०एस०, स्पैशल सेक्रेटरी को अक्तूबर, 2005 में इन्कवायरी आफिसर मुकर्रर किया गया है। दूसरी इन्क्वायरी जो हैंडीकैड टीचर सिलैक्ट किए गए हैं उनके बारे में चल रही है। उसमें आरोप यह है जो हैंडीकैप्ट कैंडीडेट लगाये गये हैं वे हैंडीकैड नहीं हैं। फर्जी सर्टीफिकेट लगाकर लगाए गए हैं and that matter is with the Vigilance Department. अध्यक्ष महोदय, इनका केस जो दर्ज हुआ है जैसा माननीय सदस्य ने पूछा है वह

7–10–2005 को अंडर सैक्शन 218,409, 420,467,468,471, 120 बी आई.पी.सी. के तहत दर्ज हुआ है। दूसरा मेरे साथी ने पूछा है कि सिलैक्शन के दौरान किसी डी०ई०ओ० की डैथ हो गई। So, during the time of selection that matter will also come up. इस इन्क्वायरी में वह भी दिखवा लेंगे कि कोई ऐसा वाक्य हुआ है।

श्री एस०एस० सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, इन्क्वायरी होते एक साल हो गया उसका अंत कब होगा?

श्री फूल चन्द मुलाना: अध्यक्ष महोदय, हम जल्दी ही करवायेंगे।

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने कहा है कि सी०बी०आई० पहले से ही सुप्रीम कोर्ट के कहने पर जे०बी०टी० की सिलैक्शन के बारे में इन्क्वायरी कर रही है। क्या वे एस०एस० टीचर्स की सिलैक्यान के बारे में भी सी०बी०आई० से इन्क्वायरी करवायेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सी०बी०आई० की इन्क्वायरी के दायरे में जे०बी०टी० टीचर्स को किया है तो क्या स्कूल लैक्चरार और एस०एस० टीचर्स की इन्कवायरी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश नहीं किए? मंत्री जी ने माना भी है कि इस सिलैक्शन में बेकायदगिया हुई हैं। जो हमारे शिक्षित युवक थे उनका सिलैक्शन नहीं किया गया। जो सिफारशी टट्टू थे, और वे हरियाणा प्रदेश से बाहर के रहने वाले थे, उनके सर्टीफिकेट भी नकली थे उनसे

रिश्वत लेकर उनका सिलैक्शन कर लिया गया और शिक्षा संस्थानों पर जान–बूझकर थोप दिया गया। इसलिए मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या मंत्री जी एस०एस० टीचर्स और स्कूल लैक्चरार वाले सिलैक्शन की भी सी०बी०आई० से इन्क्वायरी करवायेंगे?

श्री फूल चन्द मुलानाः अध्यक्ष महोदय, अभी एक केस में डिपार्टमैंटल इन्क्वायरी हो रही है और एक केस में विजीलैंस इन्क्वायरी हो रही है। सरकार ने अभी ऐसा कोई केस सी०बी० आई० को रैफर नहीं किया है। अभी जो इकायरीज पहले से चल रही हैं उनकी रिपोर्ट आ जाये उसके बाद इस पर कार्यवाही की जाएगी।

Polluting of Environment by Crushers

***400 Shri Naresh Yadav:** Will the Minister for Environment be pleased to state—

(a) whether it is in the knowledge of the Government that the crushers set up in the village Dholera, Bigopur, Jainpur, Nizampur & in the Tehsil Mahendergarh are causing danger to the environment ; and

(b) if so, what steps are being taken by the Government to keep the environment free of pollution ?

Power Minister (Sh. Vinod Kumar Sharma): A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Yes, sir.

(b) Several steps have been taken and are being taken to control Environmental Pollution in the areas referred to:-

(1) Haryana State Pollution Control Board has got closed 10 stone crusher units operating in the area under section 31-A of the Air Act of 1981 as were violating various provisions of the said Act.

(2) Show Cause Notices under the Air Act have been issued to 26 crusher units for ensuring improvement in their Air Pollution Control System.

(3) Government and the Board have started a programme for raising and enhancing technical knowledge of stone crushers. Two technical workshops are proposed to be organised in Bhiwani and Mahendergarh District in the next few weeks.

(4) Air Pollution Testing equipment are proposed to be installed in major stone crusher areas.

(5) To ensure full running of APCM while the stone crushing machinery is in operation, the system of interlocking the APCM with main equipment is being implemented.

श्री नरेश यादवः अध्यक्ष जी माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि 26 क्रशर्ज को वायु प्रदूषण के बारे में कारण बताओ नोटिस भी दिए गए हैं। क्रशरों की धूल मिट्टी की वजह से पिछली पूरी फसल चौपट हो गई और लोगों को टी०बी० की बीमारी की शिकायत हो गई। महेन्द्रगढ़ तहसील और नारनौल

तहसील का वाटर लैवल ऑलरेडी 1200 से 1400 फुट नीचे चला गया है निजामपुर, डौनपुर धोलेडा, बीगोपुर आदि ऐसे गाँव हैं जिनमें क्रशर लगे हुए हैं वहां पर एक–एक क्रशर पर पानी की बड़ी भारी जरूरत है। बार–बार शिकायत करने के बावजूद भी वहां पर कोई कार्यवाही नहीं हुई लेकिन जब विधान सभा में क्वैश्चन लगा तो प्रशासन भाग दौड़ करने में लगा है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि किसानों का जो नुकसान हुआ है क्या उसकी भरपाई क्रशर वाले करेंगे या सरकार करेगी और जो लोग बीमार हो गए हैं क्या सरकार ने उनके इलाज के लिये कोई प्रावधान किया है?

श्री विनोद कुमार शर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं अपने माननीय साथी को यह बताना चाहूँगा कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि किसानों के नुकसान की भरपाई क्रशर वालों से करवाई जा सके लेकिन जो लोग बीमार हुए हैं अगर माननीय साथी उनके बारे में लिखकर भेजेंगे कि क्रशर द्वारा वायु प्रदूषण की वजह से कौन लोग बीमार हुये हैं तो सरकार की तरफ से उनका ध्यान रखा जायेगा।

श्रीमती अनिता यादव: अध्यक्ष महोदय, जो कुण्ड का क्षेत्र है वहां पर खनन का काम होता है और वहां से स्लेट पत्थर एक्सपोर्ट भी होता है। पत्थर कटने के बाद जो उसका वेस्ट मैटीरियल है वह बड़ी दूर तक के एरिया में फैला हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जब वहां पर गए थे तो हमने उनको

वह दिखाया भी था। लोभ के कारण उसकी खुदाई भी बहुत गहराई तक जा रही है और वह पानी की तह तक पहुंच गई है। वहां पर पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा हो रहा है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूँ कि क्या सरकार इस समस्या के समाधान के बारे में कुछ करेगी?

श्री विनोद कुमार शर्मा: स्पीकर सर, मैं माननीय सदस्या से कहना चाहूँगा कि यह सवाल खनन विभाग से सम्बन्धित है यह एनवायर्नमैंट से सम्बन्धित नहीं है अगर खनन की वजह से एनवायर्नमैंट में पोल्यूशन हो रहा है तो हम उसकी जांच करवा लेंगे।

श्री भूपेन्द्र चौधरी: अध्यक्ष महोदय, क्रशर जोन सरकार ने बंद कर दिया था लेकिन अभी भी इललिगल स्टोन क्रशिंग हो रही है। जैसे कि नौरंगपुर गुड़गांव में भी हमने देखा है कि वहां पर अभी भी क्रशर्ज चल रहे हैं। क्या मंत्री जी बताएंगे कि उन क्रशर्ज को कब तक बंद करने की कार्यवाही करेंगे और सरकार ने अभी तक उनके खिलाफ क्या ऐक्शन लिया है?

श्री विनोद कुमार शर्मा: स्पीकर सर, माननीय सदस्य का कन्सर्न पोल्यूशन के बारे में है और इसके बारे में सरकार भी बहुत जागरुक है। हमने अभी माननीय सदस्य को बताया है कि हमने ऑलमोस्ट स्टोन क्रशर्ज को बंद करवा दिया है लेकिन जो स्टोन क्रशर्ज ऐसी किन्हीं जगहों पर काम कर रहे हैं उनके कलोजर का

नोटिस दिया गया है। 8 स्टोन क्रशर्ज ऐसे हैं जिनको शो काज नोटिस फार कलोजर दिया गया है 118 स्टोन क्रशर्ज ऐसे हैं जिनको शो काज नोटिस दिए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट महेन्द्रगढ़ में पोल्युशन कण्ट्रोल मैयर्ज इनएडिक्वेट हैं उनको पूरा किया जाएगा। मैं यह बात सदन के सामने रखना चाहता हूँ कि किसी भी हालत में पोल्यूशन को लाजिमी तौर पर कंट्रोल किया जाएगा और यह भी निश्चत किया जाएगा कि किसी एरिया को इस तरह का नुकसान स्टोन क्रशर्ज चलने की वजह से न हो। पोल्यूशन नियंत्रण के लिए जो भी मैयर्ज लेने चाहिएं या जो कार्य करने चाहिएं उसके लिए सरकार कार्यवाही करेगी ताकि पर्यावरण के कारण लोगों को कोई नुकसान न हो।

श्री रणबीर सिंह महेन्द्राः स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इन्होंने अपनी रिप्लाई में कहा है– Air pollution testing equipments are proposed to be installed in major stone crusher areas. क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस को इन्सटाल करने में कितना समय लगाएंगे और क्या यह आईडैंटीफाई किया गया है कि इसके लिए कौन–कौन कसूरवार हैं?

श्री विनोद कुमार शर्माः अध्यक्ष महोदय, हम फरीदाबाद में टैस्टिंग इक्वीपमैंट लगाने जा रहे हैं और एक इक्यीपमैंट पर 7 हजार रुपये का खर्चा आएगा। हम गुड़गांव मैं भी जहां– जहां पर

स्टोन क्रशर्ज लगे हुए हैं उनके बारे में पता करके वहां–वहां पर यह इक्यीपमैंट लगवाने की कोशिश करेंगे।

श्री नरेश यादवः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जवाब में कहा है कि हम सावधानी बरतेंगे। लेकिन मैं मंत्री जी को बताना चाहूँगा कि हमारे यहां पर पीने के पानी की बहुत दिक्कत है और वहां पर स्टोन क्रशर्ज वाले स्टोन्ज को पानी से धो रहे हैं। इस तरह से उनके द्वारा वहां पर पानी की वेस्टेज की जा रही है। आगे गर्मियों का मौसम आ रहा है और वहां पर अभी से पीने के पानी की दिक्कत है। क्या मंत्री जी ऐसी व्यवस्था करेगे कि जो पानी स्टोन क्रशर्ज वालों द्वारा बर्बाद किया जा रहा है वह बंद हो और नहरों द्वारा उस एरिया के छोर तक पानी पहुंचाने का बंदोबस्त करवाएंगे ताकि आने वाले समय में लोगों को पीने का पानी मिल सके।

श्री विनोद कुमार शर्माः अध्यक्ष महोदय, अगर इनके एरिया में नहरों द्वारा आखिरी छोर तक पानी नहीं पहुंच रहा है तो हम नहरी मंत्री जी से गुजारिश करेंगे कि वे इनकी सहायता करें।

श्री राधेश्याम शर्मा अमरः स्पीकर साहब यह जो स्टोन क्रशर हैं इन क्रशर्ज के लिए नारनौल क्षेत्र में दोहन और कृष्णावती नदी से बजरी निकाली जाती है। उस बजरी से पर्यावरण का डचल नुक्सान हो रहा है। जब वे बजरी की धुलाई करते हैं तो जो फालतू बजरी होती है उसको क्रशर्ज वाले वहीं पर जगह–जगह

फैंक देते हैं जिसकी वजह से सारे के सारे नये पौधे दब गाए हैं। (विघन) इराके अलावा जो वे बजरी धोते हैं उसका पानी जमीन में पीने के पानी को नीचे कर देता है। जिसकी वजह से उस एरिए में जो टयूबवैल्ज लगे हुए हैं वे सारे के सारे फेल हो गए हैं। स्पीकर सर, मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि वहां पर सारे के सारे क्रशर्ज इललिगल हैं और वे तुरंत बंद होने चाहिए जोकि पर्यावरण का बहुत नुकसान कर रहे हैं।

श्री विनोद कुमार शर्मा: अध्यक्ष महोदय, वहां पर जो भी इललिगल क्रशर्ज होंगे उनको बंद करने के, लिए नोटिस दिया जाएगा और कानून के तहत वहां पर कार्यवाही करवाएंगे।

Construction of an International Vegetable Mandi

***366. Shri Dharam Pal Singh Malik:** Will the Minister for Agriculture be pleased to state whether agriculture land about 400 acres for setting up of International Vegetable Market in village Rai, district Sonepat has been acquired during the period from 1991 to 1996; if so, what is the present position thereof ?

Agriculture Minister (Sardar H.S. Chatha): The Government of Haryana had acquired land measuring 559 acres, 4 Kanals & 16 Marlas to set up a Modern Vegetable Complex at Rai during the period 1994 to 1998. In January 2001, the proposal was dropped and the said land was transferred to the HSIDC for developing an Industrial Estate. However, a fresh proposal for setting up a Modern Terminal Fruit & Vegetable Market in Sonepat District is under

consideration of the Government.

Ch. Dharam Pal Singh Malik: Mr. Speaker Sir, with the reply of the Hon'ble Minister, my question has become sandwich. The question was concerned with the Department of Agriculture. Why the reply has been reffered to the Industries Minister? Now, it has become very difficult, how to come out of this question. The Industries Minister is not here. Actually on the demand of the farmers, this vegetable market was established. सोनीपत का एरिया ऐसा है जहां बहुत स्माल होल्डींग्ज हैं। वहां पर एक–एक और दो–दो एकड़ के जमींदार हैं और उनकी बहबूदी के लिए वे वहां पर फल और फूल लगाएंगे तथा वे फल और फूल इन्टरनैशनल मार्किट में जाएंगे। यह बहुत बड़ा प्रोजैक्ट था। दिल्ली के जो आऊटसट की हुई इन्डस्ट्रीज जोकि लोगों ने घरों में लगाई हुई थी उन्हें फायदा देने के आधार पर यहां ट्रांसफर कर दिया गया था। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि क्या कारण थे जो इस प्रोजैक्ट को बदलकर एच०एस०आई०डी०सी० को दे दिया।

सरदार एच०एस० चट्ठा: स्पीकर सर, इस मंडी को चालू करने के लिए बहुत कोशिश की गई और बहुत मीटिंग्ज भी की गई। टैंडर्ज भी काल हुए हैं लेकिन अलटीमेटली गवर्नमैंट ऑफ इडिया इसमें ड्राप आउट कर गयी। उन्दोंने यह भी कह दिया कि हमें यह नहीं बनानी है और हमें इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना and it was not possible for the State but only to go ahead. In addition to this राई के साथ ही दिल्ली मार्केटिंग बोर्ड ने एक

मंडी बनाने के लिए 50 एकड़ जमीन और ऐक्वायर कर ली इसलिए इसके न बनने का एक कारण यह भी था। इसमें एक फैक्टर यह भी था कि उनकी मार्किट फीस एक परसैंट है जबकि हमारे यहां पर मार्किट फीस चार परसैंट है। इन बातों को देखकर ही यह स्कीम ड्राप हुई। स्पीकर सर, इसके बनने का एक कारण और भी था कि वर्ष 2000 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि दिल्ली से इंडस्ट्रीज उठाई जाएं। उस समय हरियाणा सरकार ने यह सोचा कि अगर यह इंडस्ट्रीज हरियाणा में आ जाएं तो हरियाणा की बहुत बेहतरी होगी। इस चीज को सामने रखते हुए यह जमीन एच०एसआई०डी०सी० को ट्रांसफर कर दी गई है।

चौ० धर्मपाल सिंह मलिकः स्पीकर सर, मंत्री जी ने जवाब दिया है कि इस मंडी के न बनने के दो कारण थे इसलिए इस प्रोजैक्ट को बदल दिया गया। एक कारण तो यह था कि दिल्ली की सरकार ने इनको इसकी परमीशन नहीं दी कि यह वेजीटेबल मार्किट एस्टबलिश कर सकें। लेकिन स्पीकर सर, मैं समझता हूँ कि ऐसा कानून में कोई प्रावधान नहीं है कि हमें अपने प्रदेश में वेजीटेबल्ज मार्किट एस्टेबलिश करने के लिए किसी दूसरे प्रदेश सै परमीशन लेनी पड़े ऐसा कानून में कोई प्रावधान नहीं है। स्पीकर सर, इस मंडी का न बनने का असली बेसिक कारण यह था कि उस समय की सरकार ने दिल्ली के दबाव में आकर यह काम नहीं किया क्योंकि उस समय दिल्ली की आउस्टीज, छोटी–छोटी

फैक्ट्रीज हरियाणा में आना चाहती थीं। मंत्री जी ने इसका जो जवाब दिया है उसमें कहा है कि –

"However a fresh proposal or setting up a modern terminal fruit and vegetable market in Sonepat district is under consideration of the Government."

स्पीकर साहब, उस समय ऐसे कौन से हालात थे जिनके कारण इस मंडी को बनाने की मंजूरी नहीं मिली और अब ऐसे क्या हालात हो गये कि आज यह अंडर कसीड़ेशन हो गई है। आज यह कौन सी जगह पर बनायी जाएगी और इसका काम किस स्टेज पर है, जमीन ऐक्वायर हुई है या नहीं हुई और कब तक इस मंडी को ऐस्टेबलिश कर दिया जाएगा?

सरदार एच०एस० चट्ठाः स्पीकर सर, भारत सरकार ने आठ साईट्स की पहचान इस तरह की मंडी बनाने के लिए की हैं जिसमें राई भी है और चण्डीगढ़ भी है। हमारी वहां पर इंटरनैशनल स्टैंडर्ड की मार्किट बनाने की योजना है। हमारी इस बारे में बात चल रही है। परमात्मा करें कि यह काम सिरे चढ़ जाए। हम इसको इंडिया की बेस्ट मंडी बनाने की कोशिश कर रहे है।

श्री कर्ण सिंह दलालः स्पीकर सर, धर्मपाल मलिक साहब ने एक अच्छा सवाल सदन में उठाया है और मंत्रो जी ने जैसे अपने जबाव में बताया है तो क्या माननीय मंत्री जी सदन को यह आश्वासन देंगे क्योंकि दिल्ली के प्रदूषण को यह इंडस्ट्रीज बहुत

ज्यादा खराब करती थी लेकिन उन कारखानों को हरियाणा में बसाने के लिए पिछली सरकार ने इन इंडस्ट्रीज वालों से मोटी रिश्वत लेकर कायदे कानून को ताक पर रखकर हरियाणा प्रदेश के हितों पर कुठाराघात किया है। क्या सरकार इसका कोई जांच करवाएगी और क्या इस राई की जमीन को जो उन्होंने एच०एस०आई०डी०सी० को दे दी, के तमाम केस की भी विजीलैंस डिपार्टमैंट से इंक्वायरी करवाएंगे। क्या मंत्री जी सदन को इस बारे में आश्वासन देंगे?

सरदार एच०एस० चट्ठाः स्पीकर सर, विजीलैंस डिपार्टमैंट से इसकी जांच करवाने की जरूरत नहीं है। इस जमीन में से 370 एकड़ जमीन इंडस्ट्रीज में जाएगी, 116 एकड़ जमीन फूड प्रोसैसिंग के लिए दी जाएगी, 17 एकड़ जमीन कोल्ड चौन कफ्लैक्स के लिए दी जाएगी तथा इंडस्ट्रियल फूड प्रोसैसिंग टैक्नोलाजी के लिए 56 एकड़ जमीन देने का केस अभी पैंडिंग है, यह जमीन इंडस्ट्रीज डिपार्टमैंट के पास है वह इसका इस्तेमाल करेंगे।

श्री एस०एस० सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, वह जमीन सब्जी मंडी एस्टेबलिश करने के लिए ली गई थी उस समय कहा गया था कि वहां सिर्फ वेजीटेबल मार्केट बनानी है। यह काफी मल्टी परपज प्रोजैक्ट था। इसमें प्रोसैसिंग, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टिंग और बैंकिंग जैसी सुविधाएं देकर इसकी इंटरनैशनल मार्केट के लिए हवाई अड्डे तक उस मंडी को लिंक करने की योजना थी

ताकि हरियाणा के किसान जो सब्जी ग्रोअर हैं और जिनकी होल्डिंग थोड़ी छोटी है, उनको इसका लाभ मिल सके। इस जमीन को सरकार कैसे एच०एस०आई०डी०सी० को दे सकती है? मैं चाहूँगा कि मंत्री जी इस बारे में अपना जवाब दें क्योंकि यह जमीन ली तो गई थी वेजीटेबल ग्रोअर्ज के बेनिफिट के लिए लेकिन उसको बाद में इंडस्ट्रीज के लिए ट्रांसफर कर दिया। क्या देहली का कूड़ा उठाने के लिए हरियाणा ही रह गया है? देहली की पोज्यूटिड इंडस्ट्रीज को हरियाणा में लगाने की बात पिछली सरकार ने की थी लेकिन यह पिछली सरकार का भ्रष्टाचार का मुद्दा था इसलिए ही वह इस तरह की बात करते थे। क्या उस जमीन को दोबारा से एच०एस०आई०डी०सी० से वापिस लेकर वेजीटेबल मार्किट बनाने की जो ओरीजिनल योजना थी, उसको सरकार लाग करेगी?

सरदार एच०एस० चट्ठा: स्पीकर सर, ऐसी कोई बात नहीं है कि हम दिल्ली का कूड़ा कर्कट उठाने के लिए हरियाणा में बैठे हुए हैं। एक अच्छी योजना इण्डस्ट्रीज विभाग के पास आई और इण्डस्ट्रीज विभाग ने उस योजना को एक्सैप्ट किया। इण्डस्ट्रीज विभाग के हिसाब से ही कारखाने लगे हैं। जहां तक फूड प्रोसैसिंग की बात है, अभी कुछ दिन पहले केन्द्र के एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब ने एक मीटिंग बुलाई थी, उस मीटिंग में मुझे भी जाने का मौका मिला। गवर्नमैंट ऑफ इण्डिया इस बारे में काफी सीरियस है कि राई के अन्दर वर्ल्ड की एक टॉप क्लास

वेजीटेबल मार्किट बनाई जाए ताकि उस इलाके के लोगों को सब्जी मण्डी में अपनी सब्जियां लाकर बेचने का और उनको एक्सपोर्ट करने का मौका मिल सके। जो बात माननीय सदस्य ने कही है, ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि 56 एकड़ जमीन अभी भी सब्जी मण्डी के लिए इण्डस्ट्रीज विभाग के पास है। यह जमीन फूड प्रोसैसिंग इन्क्रीज्यूट के लिए इस्तेमाल की जाएगी।

Providing of Amenities in Schools

***456. Dr. Sushil Indora:** Will the Minister for Education be pleased to state whether the Govt. has made proper arrangement of drinking water, toilets, desks for sitting of the students and other facilities in all schools of the State; if so, the details thereof ?

Education Minister (Sh. Phool Chand Mullana): Yes Sir. Necessary arrangement of drinking water and toilet facilities is available in all Government Schools. In some identified schools where tap water supply or hand pump is not available, necessary action is being taken to provide tap/hand pump supply. All Government Primary Schools are likely to be provided desks during the current financial year. Most of the High Schools and Senior Secondary Schools would also be provided with desks during this finacial year and the balance will be covered during 2006-07.

डॉ० सुशील इन्दौरा: स्पीकर सर, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने बताया कि कुछ इन्तजाम इन्होंने जरूर किए हैं। लेकिन आजकल के सर्वे के हिसाब से स्वास्थ्य की दृष्टि से ग्राउंड वाटर

पीने के काबिल नहीं है इसलिए उसको रिजैक्ट किया गया है। That is a polluted water इस पानी का स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। इस बारे में मंत्री जी ने रिप्लाई में भी कहा है कि–

"In some identified schools where tap supply or hand pump is not available, necessary action is being taken to provide tap/hand pump supply".

Mr. Speaker: Indora ji, there is no need of background. Please ask your supplementary. आपका सवाल क्या है?

डॉ० सुशील इन्दौराः अध्यक्ष महोदय, मैं सवाल पर ही आ रहा हूँ।

श्री अध्यक्षः आप अपनी सप्लीमैंटरी पूछिये। आप तो भाषण देंने लग गये हैं। अपना सवाल पूछिये। जिस तरह सवाल पूछा है इसी प्रकार दूसरा सवाल पूछिये।

डॉ० सुशील इन्दौराः अध्यक्ष मोहदय, मैं सवाल पर ही आ रहा हूँ।

श्री अध्यक्षः आप अपना सवाल पूछिए इसकी बैकग्राउंड देने की जरूरत नहीं है। आप तो सीजण्ड पार्लियामेंटर्रियन हैं इसलिए आपको सभी कुछ मालूम है भाषण देने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह कोई पोलिटिकल स्टेज नहीं है। आप अपना सवाल

पूछिए। Indora ji, in this manner, you are snatching the rights of other Members. Please ask your supplementary.

10.00 बजे

डॉ० सुशील इन्दौरा: अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री जी टायलैट्स की बात कर रहे हैं कुछ असुविधा की वजह से टायलैट्स सुचारू रूप से नहीं चल रहे हैं और कई स्कूलों में पीने के पानी की भी प्रोपर व्यवस्था नहीं है। क्या सरकार हर सरकारी स्कूल में पीने के लिए टैप वाटर का प्रबन्ध करेगी और टायलैट्स ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं उनको ठीक करवाया जाएगा?

श्री फुल चन्द मुलाना: अध्यक्ष महोदय, जहां तक मेरे माननीय साथी इन्दौरा जी सभी सरकारी स्कूलों में टैप वाटर देने की बात कर रहे हैं इस बारे में मैं इनको बताना चाहूँगा कि हमारे प्रदेश में अभी भी 2975 गाँव ऐसे हैं जहां पर पीने के पानी का प्रैशर टैप में इतना तेज नहीं है जिसके कारण स्कूलों में टैप वाटर नहीं पहुँचाए जा सकते। पानी का प्रैशर तेज करने के लिए हमने पब्लिक हैल्थ विभाग को लिखकर भेजा है ताकि हर स्कूल में टैप वाटर उपलब्ध करवाया जा सके और बच्चों को स्वच्छ पीने का पानी मिल मके। अध्यक्ष महोदय जहां तक टायलैट्स का सवाल मेरे साथी ने किया है, मैं इनको बताना चाहूँगा कि टायलैट्स का प्रबन्ध हमने हर स्कूल में किया है और लड़कियों के लिए हमारी सरकार कुछ अलग से टायलैट्स का प्रबन्ध करने जा रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहूँगा और कल भी मैंने

बोलते हुए बताया था कि चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की सरकार जहाँ शिक्षा की तरफ विशेष ध्यान दे रही है वहीं बच्चों के स्कूल और टायलैट्स की तरफ भी विशेष ध्यान दे रही है। जिस समय विपक्ष के साथियों की सरकार थी उस समय 2003–04 और 2004– 05 में सिर्फ 937 और 912 टायलैट्स सरकारी स्कूलों में बनाये गये थे। हमने केवल पिछले एक साल के दौरान 2354 टायलैट्स बनाये हैं। इसके अतिरिक्त पीने के पानी को सुविधा हमने पिछले एक साल के दौरान 1835 स्कूलों में दी है। अध्यक्ष महोदय, अग्ने वाले साल में क्यूँ। 31 मार्च के बाद प्रारम्भ होगा उसमें टोटल सैनीटशन प्रोग्राम के तहत ये सुविधाएं तकरीबन हम सभी स्कूलों में उपलब्ध करवाएंगे।

श्री रणबीर सिंह महेन्द्राः अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से जी जी से पूछना चाहता हूँ जैसा कि मंत्री जी ने अपने रिप्लाई में कहा है कि–

"Necessary arrangement of drinking water and toilet facilities is available in all Government Schools." मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि गर्वनमैंट हाई स्कूल रानीला में पीने के पानी का कोई प्रबन्ध नहीं है। The information given is wrong.

श्री फूल चन्द मुलानाः अध्यक्ष महोदय, मैं मेरे माननीय साथी को बताना चाहूँगा कि किसी स्कूल में पीने के लिए टैप वाटर का प्रबन्ध है, किसी में हैंडपम्प वाटर का प्रबन्ध है। यदि किसी स्कूल में ये दोनों तरह के प्रबन्ध नही हैं तो वहाँ पर मटकों

का प्रबन्ध कर रखा है। ऐसा प्रदेश में कोई स्कूल नहीं है जहां पीने के पानी का प्रबन्ध नहीं है।

डॉ० सुशील इन्दौराः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि सरकार ने दावा किया था कि ये हर स्कूल में डयूल डैस्क उपलब्ध करवाएंगे और किसी भी स्कूल में बच्चे चटाई पर बैठकर पेपर नहीं देंगे। हमें कई स्कूलों से शिकायत आई है कि उनमें डयूल डैस्क उपलब्ध नहीं करवाये गये हैं, बच्चे चटाई पर बैठकर पढ़ाई करते हैं। क्या सरकार ने ऐसे स्कूल आईडेंटीफाई किए हैं? जिनमें डमूल डैस्क नहीं हैं और उनमें सरकार आने वाले वित्त वर्ष मे उपलब्ध करवाने जा रही है। इसका पूरा विवरण हमें विस्तार से बताया जाये।

श्री फूल चन्द मुलानाः अध्यक्ष महोदय, मैं मेरे माननीय साथी को बताना चाहूँगा कि पिछली सरकार के पाँच साल के कार्यकाल के दौरान वर्ष 2000 से लेकर 2005 तक 10.15 करोड़ रुपये के डयूल डैस्क खरीदे गये थे और हमारी सरकार के एक साल के, कार्यकाल के दौरान 14.72 करोड़ रुपये के डयूल डैस्क खरीदे गए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं मेरे साथी को बताना चाहूँगा कि आने वाले वित्त वर्ष के दौरान जो 31 मार्च के बाद शुरू होगा उसमें सभी सरकारी प्राईमरी स्कूलों में डयूल डैस्क उपलब्ध करवा दिए जाएंगे।

श्री सोमवीर सिंहः अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ जैसा कि इन्होंने कहा कि टायलैट्स का प्रबन्ध हर सरकारी स्कूल में है। मेरे हल्के के गाँव सीहरवा में सरकारी हाई स्कूल है। 15 दिन पहले मैं वहां गया था। उस स्कूल में कहीं पर भी टायलैट्स का प्रबन्ध नहीं है। क्या मंत्री जी मौके पर इंस्पैक्शन करवाने के बाद यह जानकारी दे रहे हैं कि सभी स्कूलो में टायलैट्स का प्रबन्ध है या रिकॉर्ड के हिसाब से बता रहे हैं। क्योंकि अभी भी मेरे हल्के के बहुत से स्कूल ऐसे हैं जिनमें टायलैट्स का कोई प्रबन्ध नहीं है। कृपा करके मंत्री जी कन्फर्म करके बतायें, रिकार्ड के आधार पर न बतायें।

श्री फूल चन्द मुलानाः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल किया है उसकी जांच अवश्य करवा लेंगे और अगर कहीं पर शौचालय है या इसके बारे में कोई गलत इन्फ्रर्मेशन है तो उसको देखकर उसका प्रबंध करवाएंगे।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंहः अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में सरकार बहुत चिन्तित है और बजट प्रोविजन में भी पिछले साल और इस साल शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के काफी प्रयास किए गए हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से एक सवाल का जवाब चाहता हूँ। कई दूसरे माननीय सदस्यों ने कहा है और मंत्री जी ने जवाब भी दिया है। पीने का पानी है या और दूसरी सुविधाएं हैं इनकी परिभाषा क्या है? मंत्री जी ने शौचालयों की फैसिलिटी के बारे में बताया है। मुझे याद है कि वर्ष 2000 में

ए०जी ० की रिपोर्ट में जिक्र था। उनकी एक टैस्ट चौक की रिपोर्ट आई थी जिसमें तकरीबन अढ़ाई हजार स्कूलों को चौक किया गया था और उन अढ़ाई हजार स्कूलों में से 1500– 1700 के करीब ऐसे स्कूल थे जहां पर शौचालय और पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। अध्यक्ष महोदय, जवाब में मंत्री जी बता रहे हैं कि यह फेसिलिटीज सभी स्कूलों में उपलब्ध है। मेरी जो जानकारी है उसके मुताबिक तकरीबन आधे स्कूल नहीं तो कम से कम 40 परसैंट स्कूल्ज ऐसे हैं जहां शौचालयों की सुविधा विद इन दि परमिसिज नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूँगा कि क्या वे इस बात की जांच करवाएंगे कि किन– किन स्कूलों में शौचालय हैं या किनमें नहीं हैं?

श्री फूल चन्द मुलानाः अध्यक्ष महोदय, माननीय चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंह जी ने जिस रिपोर्ट का हवाला दिया है वह बहुत पुरानी रिपोर्ट है। मौजूदा हालात में तकरीबन हमने सभी स्कूलों में टायलैट्स का प्रबन्ध किया हुआ है। जहां पर पीने के पानी की फैसिलिटी नहीं है वहां पर भी पानी की फैसिलिटी हो जाएगी। जहां पर ये सुविधाएं हैं लेकिन उनमें सुधार करने की आवश्यकता है वहां हम सुधार कर रहे हैं। इसकी जांच दोबारा करवा ली जाएगी और अगर कहीं पर कोई कमी पाई गई तो उसको ठीक करवा दिया जाएगा।

प्रो० दिनेश कौशिकः स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से यह पुछना चाहूँगा कि जिन

सुविधाओं के बारे में इन्होंने यहां पर कहा है और सदन को बताया है क्या प्राईवेट स्कूलों में और गवर्नमैंट स्कूलों में दी जा रही सुविधाओं में कुछ अंतर है? सिंगल फेयर पर ट्रांसपोर्ट में मात्र सरकारी स्कूलों के बच्चों को ही ले जाते है लेकिन प्राईवेट स्कूलों के बच्चों को इस बारे में जो सुविधा थी उसको वापिस ले लिया गया है और 60 रुपये प्रति सीट पर मन्ध का एक लैटर वहां पर गया है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार इसके बारे में कुछ सोच रही है?

श्री फूल चन्द मुलानाः अध्यक्ष महोदय, इसके लिये ये अलग से नोटिस दे दें इनको जवाब मिल जाएगा।

आई०जी० शेर सिंहः अध्यक्ष महोदय, शौचालय तथा पीने के पानी की फैसिलिटीज सभी स्कूलों में जरूर अवेलेबल करवाई जानी चाहिएं और ज्यादातर जगहों पर ये सुविधाएं उपलब्ध करवाई भी गई हैं लेकिन आमतौर पर यह देखा गया है कि इसके साथ जो एलॉयड स्टाफ है वह उपलब्ध नहीं है। टायलैटस तो बने हुये हैं लेकिन वहां पर सफाई कर्मचारी नहीं हैं और वे टायलैट्स गंदगी से सड़ रहे हैं। क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इस तरह का जो एलॉयड स्टाफ है उसको कब तक भर्ती किया जाएगा?

श्री फूल चन्द मुलानाः अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा ही रैलेवैन्ट सवाल है। हमारे मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने

निर्णय लिया है कि क्लास– 4 इम्पलाईज की भर्ती शीघ्र ही की जाएगी। यह भर्ती होने के बाद इस समस्या का समाधान हो सकेगा।

परिवहन मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला): अध्यक्ष महोदय, मैं हाउस की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा खासतौर से गरीब और आम आदमी को यह सुविधा मिले इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने 239 करोड़ रुपये का रूरल सैनिटेशन प्रौजेक्ट बनाकर भारत सरकार को भेजा हुआ है जिसमें स्कूलों के टायलैट्स भी शामिल हैं। जहां कहीं पर ऐसे स्टॉफ की कमी होगी वहां पर यह सुविधा प्रोवाईड करवाई जाएगी। इस प्रोजैक्ट के मंजूर होने पर दूसरे लोगों को भी यह सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। भारत सरकार से शीघ्र ही इसकी अनुमति ले ली जाएगी।

Rice Shoots

***382. Shri Tejendra Pal Singh Mann:** Will the Minister for Irrigation be pleased to state whether it is a fact that the processing fee for sanctioning of temporary rice shoots is not being returned to those farmers whose shoots have not been sanctioned; if so, the reasons thereof ?

Revenue Minister (Capt. Ajay Singh Yadav): Yes Sir. The deposit of processing fee is not an entitlement for sanction of rice shoot. It is a charge for processing the case. Therefore, it has been provided in the Rice Shoot Policy that the application fee so deposited will not be refunded.

श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मानः स्पीकर सर, अस्थाई राईस सूट्स की स्वीकृति के बाद किसानों से प्रोसैसिंग फीस जमा करवाई जाती है। हमारे इलाके में पैडी की क्रॉप होती है। किसान बहुत गरीब हैं और उसको राईसशूट लगाना पड़ता है। मैं माननीय मंत्री जी से सिर्फ यह जानना चाहता हूँ कि क्या कोई ऐसा प्रावधान कर सकते हैं कि गरीब किसान के जो प्रोसैसिंग फीस के 500– 700 रुपये रह जाते हैं वह जिनके सईस शूट्स स्वीकृत नहीं हुए उसको वापिस हो जाएं। गरीब किसान जगह जगह घूमता रहता है। मैं चाहता हूँ कि दो तीन महीने में वे पैसे उसको वापिस कर दें या अगले साल में ऐडजस्ट कर दें। जब सरकार इतनी उदारता दिखा रही है तो उस गरीब किसान ने सरकार का क्या बिगाड़ा है कि उसको उसका पैसा वापिस न किया जाए?

कैप्टन अजय सिंह यादवः .अध्यक्ष महोदय, यह जो सईस शट्स हैं ये टैम्परेरी बेसिज पर स्वीकृत किये जाते हैं। depending upon the availability of the water जहां तक इस सवाल का ताल्लुक है, मैं इनको बताना चाहूँगा कि पिछली सरकार ने प्रोसैसिंग फीस का पैसा बड़ा दिया था इसके लिये पहले जो पैसा लिया जाता था वह बहुत कम था। पालिसी के मुताबिक फीस का जो पैसा एक बार ले लेते हैं वह रिफण्ड नहीं किया जाता है।

श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मानः अध्यक्ष महोदय, इस पालिसी को बदलने के लिए ही तो हम कह रहे हैं। इस काम के लिए जो स्टॉफ है यह तो परमानैंट है। चाहे वह पटवारी है या कानूनगो हैं

ये वही लोग हैं। इसमें कोई डाक वगैरह का भी खर्च अलग से नहीं लगता और इसके लिये किसी और चोज का भी कोई खर्चा नहीं है। किसान खुद चल कर इनके आफिस में जाता है और वे लोग तो वहीं पर बैठे रहते हैं, इसमें अलग से क्या खर्चा है? अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार इसके बारे में विचार करते हुए उस पैसे को वापिस करने का कोई प्रावधान करेगी?

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2005 के दौरान तकरीबन 3002 ऐप्लीकेशन्ज हमारे पास आई थीं जिनमें से 244 को राईस शूट नहीं दिए थे क्योंकि यह डिपेंड करता है कि हैड से नहर में जो पानी डिस्चार्ज होता है अगर वह 10% से ज्यादा हो तो वहां पर सईस शूट नहीं दिया जाता है इसमें दिक्कत यह आ रही है कि केवल 244 ऐप्लीकेशन्ज हैं जिनको हम सईस कस की स्वीकृति नहीं दे पाए यह बहुत थोड़ा नम्बर है। अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी ने उनके पैसे रिफण्ड करने की बात कही है, हम इसके बारे में अधिकारियों से बात करके इस पर विचार करने की कोशिश करेंगे।

श्री आनन्द सिंह डांगीः अध्यक्ष महोदय, सवाल एक ही है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि जो सईस शूट के लिए प्रोसैसिंग फीस जमा करवायी जाती है और किसानों को इसके कनैक्शन नहीं दिए जाते हैं तो क्या उनकी प्रोसैसिंग फीस वापिस

की जाएगी अगर किसानों को कनैक्शन नहीं दिए जाते हैं तो डिपार्टमैंट को वह पैसा रखने का कोई हक नहीं है।

कैप्टन अजय सिंह यादव अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय साथी को बताना चाहूँगा कि वह पैसा रिफण्ड करने की बात हो नहीं सकती है। इस बारे में जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने अपनी चिंता जाहिर की है तो मैं इस बारे में अपने अधिकारियों से बात करने की कोशिश करूँगा कि हम यह प्रोसैसिंग फीस वापिस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं।

श्री आनन्द सिंह डांगी: अध्यक्ष महोदय, हमको उनकी प्रोसैसिंग फीस रखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उन किसानों को सईस शट्स का कनेक्शन दिया ही नहीं गया है। जिस चीज के लिए इन्होंने पैसा लिया है और वह चीज किसानों की दी ही नहीं है तो यह पैसा किस चीज का ले रहे हैं?

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, यह प्रोसैसिंग फीस है और यह वापिस नहीं की जाती है।

श्री आनन्द सिंह डांगी: अध्यक्ष महोदय, इस बारे में मंत्री जी को सोचना चाहिए। जिस किसान को कनैक्शन नहीं दिया जाता है, मोरी नहीं लगाई जाती है तो उसको उसका पैसा वापिस मिलना ही चाहिए।

श्री अध्यक्ष: डांगी जी, मंत्री कैं।। ने बता दिया है कि यह प्रोसैसिंग फीस एं। और यह वापिस नहीं हो सकती है।

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, अगर हम इस तरह से पैसे वापिस करने लग जाएंगे तो हमारे पास रिफण्ड के लिए एप्लीकेशन्ज की लाईन लग जाएगी। हम तो इसी काम के लिए ही रह जाएंगे। अध्यक्ष महोदय जहां तक कनैक्शन देने की बात है, तो यह तो पानी की अवेलेबिलिटी पर डिपैंड करता है जहां पर पानी –होगा वहीं पर हम कनैक्शन देंगे और जहां पर पानी ही नहीं होगा तो वहां पर कनैक्शन देने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। हम 30 जून तक एप्लीकेशंज लेते हैं और 15 जुलाई से 15 सितम्बर तक राइस शूट्स के टैम्परेरी कनैक्शन देते हैं। जहां तक पैसे देने की बात है, हमारे पास एप्लीकेशंज का ढेर लग जाएगा और हम कब तक रिफण्ड करते रहेंगे। यह प्रैक्टिकल बात नहीं है।

श्रीमती अनीता यादवः अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न इस प्रश्न से हटकर है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहूँगी कि मेरे हल्के में एक रामपुरी माईनर है जहां पर जोतावाली से झडोती को रास्ता है उस जगह पर पुल बना हुआ है, वह पुल जगह–जगह से टूट गया है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कह दिया था कि यह सैपरेट प्रश्न है और मंत्री भै। चाहेंगे तो इसका जवाब दे देंगे। क्या मंत्री जी, उस माईनर पर जो पुल बना हुआ है उसकी रिपेयर करवाएंगे और वह माईनर भी जगह–जगह से टुटी पड़ी है क्या उसको भी रिपेयर करवाने का कष्ट करेंगे?

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, ये इस बारे में अलग से लिखकर दे दें। इसके बारे में जवाब दे दिया जाएगा।

श्रीमती अनीता यादवः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूँगी कि अगर प्रोसैसिंग फीस वापिस नहीं दी जाती है तो किसानों से राईस शूटस के कनैक्शज के लिए ज्यादा एप्लीकेशंज क्यों ली जाती हैं 1 .आप उतनी एप्लीकेशंज लें जितने राईस शूट आपने सैंक्शन कर रखे हों। पिछली सरकार ने जाते–जाते इतने राईस शूट सैंक्शन कर दिए थे कि जब सरकार ने इस बारे में केस चलाया तो वे किसान कोर्ट से स्टे लेकर आ गए थे। इसके अलावा जहां पर पानी नहीं पहुँच रहा है वहां पर कनेक्शन देने के लिए एप्लीकेशंज क्यों ली जाती है?

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, टैम्परेरी सईस सूट का अगर तीन साल तक लगातार किसी को कनैक्शन दे दिया जाए तो वह ट्रेडिशनल सईस सूट बन जाते हैं। इसके अलावा अगर कहीं हैड पर पानी नहीं पहुँच रहा है तो वहां पर हम कनैक्शन नहीं देते हैं अगर कहीं पर पानी चोरी करते हुए किसान पकड़ा जाए तो हम उसके ट्रैडिशनल सईस सूट को कैंसिल ही कर देते हैं। लेकिन अगर किसी भी सईस शूट को हम कैंसिल करेंगे तो वह उसकी शिकायत कर सकता है। उन्होंने बताया कि पिछली सरकार में ऐसा होता था अगर यह बात ठीक है और यदि इस प्रकार की शिकायतें हैं तो हम उनको एग्जामिन करवा लेंगे। अध्यक्ष महोदय, एक सदस्य ने एक और चिन्ता व्यक्त की है और

फ्रोसैसिंग फीस का पैसा रिफण्ड करने की बात कही। हम इसको भी एग्जामिन करवा लेंगे। अगर इस प्रकार का कोई रिलीफ देने की बात होगी तो उसको भी देख लेंगे।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा): अध्यक्ष महोदय, यह मामला सभी साथियों ने उठाया है हम इसको एग्जामिन करवा लेंगे और अगर ऐसी कोई बात होगी तो उसको करा देंगे।

Construction of Railway Over Bridge

***467. Shri Bhupinder Chaudhary:** Will the Minister for P.W.D. (B&R) be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a railway over bridge at Haily Mandi railway crossing in Pataudi Constituency; and

(b) if so, upto what time the aforesaid proposal is likely to be materialized ?

Power Minister (Sh. Vinod Kumar Sharma):

(a) Yes, Sir. The proposal has been approved.

(b) The construction work is expected to commence soon.

श्री भूपेन्द्र चौधरी: अध्यक्ष महोदय, यह बात तो हम काफी दिनों से सुनते आ रहे हैं कि हेली मंडी रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज बनाने का काम अंडर कंसीड़ेशन है और जल्दी ही

शुरू हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, वहां दिल्ली रेलवे लाइन पर काफी ट्रैफिक बढ़ गया है जिसकी वजह से वहां पर आधे–आधे घंटे ट्रैफिक बंद रहता है। मैं मत्रो जी से यह जानना चाहता हूँ कि कब तक यह .ओवर ब्रिज बना दिया जाएगा?

Sh. Vinod Kumar Sharma: Mr. Speaker Sir, DNIT for construction of approaches of ROB will be approved by the Department by May, 2006 and tenders will also be floated during May, 2006. Efforts would be made to allot the work by June, 2006. It will take 12 months to complete the work after its allotment. Roughly we can say that efforts will be made to complete the work within 18 months.

श्री जय सिंह राणाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि प्रदेश में कुल कितने नये ओवर ब्रिज बनाने के लिए मंजूर किए गए हैं और कितने ओवर ब्रिज ऐसे हैं जिन पर अभी तक कार्य शुरू नहीं हुआ है तथा कब तक उन पर काम शुरू करवा दिया जाएगा?

श्री विनोद कुमार शर्माः अध्यक्ष महोदय, मुझे यह बताते हुये खुशी होती है कि आज की मौजूदा सरकार जिसके मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा हैं, ने 88 ओवर ब्रिज बनाने के लिए अपने प्लान रखे हैं। इतने ओवर ब्रिजिज कभी भी किसी सरकार ने किसी भी समय में अपने प्लान में नहीं लिए हैं। इनमें 9 ब्रिज ऐसे हैं जो एपूव हो चुके हैं जिनके टैंडर्ज मई, 2006 तक फ्लोट कर दिए जाएंगे। इसके अलावा 18 रेलवे ओवर ब्रिज की

एडमिनिस्ट्रेटिव ऐप्रूवल दी गयी हैं। इसी तरह से जो ओवर ब्रिज स्टेट रोडज पर बनाने के लिये आईडैटीफाई किये गये हैं उनकी संख्या 35 है। इसी तरह से नैशनल हाई वे पर बनने वाले रेलवे ओवर ब्रिज की संख्या 17 है। स्पीकर सर, मैं सदन को बताना चाहूँगा कि करीब–करीब 500 करोड़ रुपये का खर्चा इन पर आने वाला है। लोगों की असुविधा को देखते हुए ताकि उन्हें रेलवे क्रासिंग से न निकलना पड़े, इस सरकार ने इतने पैसे का प्रावधान इनको बनाने के लिए किया है।

श्री नरेश यादवः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि हमारे दक्षिणी हरियाणा में खासतौर से रिवाड़ी में नारनौल रोड पर अहीर कॉलेज के सामने आदरणीय बीरेन्द्र सिंह के रामपुरा हाउस के सामने जो रेलवे क्रासिंग है उसका ओवर ब्रिज कब तक सरकार बना देगी?

श्री विनोद कुमार शर्माः रिवाड़ी नारनौल रोड पर रेलवे ओवर ब्रिज का वर्क प्रोग्रेस में है और जल्दी ही यह ब्रिज बन जाएगा।

डॉ० शिवशंकर भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम सै मंत्री जो सै जानना चाहता हूँ कि भिवानी–तोशाम रोड का जो रेलवे पुल है, वह कब तक पूरा हो जाएगा?

श्री विनोद कुमार शर्मा अध्यक्ष महोदय माननीय सदस्य को इस बारे में लिखित रूप में जवाब भेज दिया जायेगा।

डॉ० सीता रामः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि सिरसा–डबवाली रोड का जो रेलवे पुल है वह कब तक पूरा हो जायेगा?

श्री विनोद कुमार शर्माः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को इस बारे में लिखित रूप में जवाब भेज दिया जायेगा।

श्री धर्मबीर गाबाः स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को कहना चाहूँगा कि अगर ये पूरी लिस्ट को हाउस में पढ़ देते हैं कि कौन से रेलवे पुल नॉन प्रियोरिटी पर हैं और कौन से 18 प्रियोरिटी पर हैं तो सभी माननीय सदस्यों को मालूम हो जाता और सबकी तसल्ली हो जाती? ऐसी मेरी माननीय मंत्री जी से रिक्वैस्ट है।

श्री अध्यक्षः गाबा साहब, आप मंत्री जी से लिस्ट ले लें।

Developing of Sector-19 in Sirsa

***350. Shri Karan Singh Dalal:** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the status of acquisition of the land for developing a residential sector-19 in Sirsa on Fatehabad road, and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government for granting colonization licence to some private colonisers for the land under acquisition in (a) above?

Transport Minister (Sh. Randeep Singh Surjewala):

(a) 407.41 acres of land has been acquired by HUDA for the development of residential Sector-19 at Sirsa.

(b) One private Developer in collaboration with the land owners has applied for grant of licence to develop a residential colony on the land measuring 138.45 acres approx. in Sector-19. However, the same is under consideration.

श्री कर्ण सिह दलाल: अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार के दौरान जैसा उनका तरीका हुआ करता था कि उस समय के मुख्यमंत्री और उनके बेटे किसानों की जमीन को प्राईवेट बिल्डर्ज को दिलवाने के लिये पहले उस जमीन को एक्वायर करने की प्रोसिडिंग्ज लगवाया करते थे और उसके बाद बिल्डर्ज के माध्यम से उस जमीन और प्रोपर्टी का सौदा खुद किया करते थे। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार इस बारे में विजिलैंस की जांच कराने को तैयार हैं ? इस सैक्टर की जमीन को पिछली सरकार ने लोगों को डरा धमका कर पहले एक्विजिशन की प्रोसिडंग्ज करवाई और बाद में उस जमीन की सौदेबाजी की और अब इस जमीन का लाईसैंस लेना चाहते हैं। क्या मंत्री जो यह आश्वासन देंगे कि इन बिल्डर्ज की दरखास्त पर कोई फैसला करने से पहले इस बारे में जांच करायेंगे? इस प्रकार के स्कैण्डल्ज पिछली सरकार ने जगह–जगह किये हैं, अपने गुह क्षेत्र सिरसा में भी उन्होंने लोगों को नहीं बखत। क्या इसकी

जांच सी०बी०आई० या विजिलैंस से कराने के लिये सरकार तैयार है?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, अगर किसी व्यक्ति विशेष जिसने दरखास्त दी है उसके बारे में माननीय सदस्य लिखकर भिजवा दें तो मैं सदन को आश्वासन देता हूँ कि हम उसके बारे में अवश्य जांच करायेंगे। लेकिन यदि किसी की दरखास्त गलत पायी जाती है तो उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे।

श्री कर्ण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया है उसके लिये में उनका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपके माध्यम में मैत्री जी से यह भी आश्वासन लेना चाहता हूँ कि जिस जमीन को डिवैल्प करने के लिये बिल्डर्ज लाइसैंस मांग रहे हैं कृपया वे उस जमीन का नाम भी बतायें। अगर इनमें गोपाल काण्डा नाम का कोई बिल्डर्ज है तो यह वही व्यक्ति है जिसने सिरसा की बिजली विभाग की बेशकीमती जमीन पर जबरदस्ती कब्जा किया था लेकिन उसकी गिरफ्तारी आज तक नहीं हुई है। क्या यह वही व्यक्ति है जो आज इस जमीन के लिए वहां पर कालोनी डिवैल्प करने के लिँए लाईसैंस मांग रहा है? अगर इस व्यक्ति के खिलाफ कोई आपराधिक मामले बनते हैं तो क्या उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी?

श्री रणदीप सिंह सूरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, एम०डी०एल०आर० रियलटर्स प्राईवेट लिमिटिड ने लाईसैंस के लिए

दरखास्त दी है। आप जानते हैं कि दरखास्त देने का अख्तियार तो किसी भी व्यक्ति को है लेकिन उसको माने या न माने यह सरकार का अख्तियार है। जिस व्यक्ति ने दरखास्त दी है उसका नाम गोपाल गोयल है। गोपाल काण्डा नहीं है अगर यह एक ही व्यक्ति है तो इस बात की जानकारी मुझे नहीं है। जहां तक बिजली विभाग की जमीन के बारे में माननीय सदस्य ने कहा है वे इस बारे में बिजली मंत्री जी को या माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखकर भेज दें, सरकार उसके बारे में अवश्य जांच करायेगी।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंहः अध्यक्ष महोदय, हुड्डा अपने सारे खर्चे निकाल कर नो प्रोफिट नो लोस पर प्लाट देता है और जो प्राईवेट कालोनाईजर भूमि अधिग्रहण करके कालोनी काटते हैं वे प्रोफिट में बेचते हैं। वे मुनाफा कमाने के लिए काम करते हैं। प्राईवेट कालोनाईजर जहां पर कालोनी काटने के लिए लाईसैंस के लिये अप्लाई करता है वहां पर किसान की एक एकड़ जमीन एक–एक करोड़ रुपये में बिकती है। इस बारे में मैं मंत्री जी से यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि यदि कोई कालोनाईजर लाईसैंस के लिये अप्लाई करता है तो या तो उसे लाईसैंस न दिया जाये यदि दिया जाये तो इस शर्त पर दिया जाये कि उसे जो प्रोफिट हो उसमें किसान को भी हिस्सेदार बनाया जाये।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय साथी की जानकारी के लिये और सदन की जानकारी के लिये बताना चाहूँगा कि चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की सरकार में हुडा

रिहायशी सैक्टर के लिये जो जमीन एक्वायर करेगा उसमें अब की बार 35 प्रतिशत इकोनोमिकली वीकर सैक्शन के लिये आरक्षण रखा गया है जोकि हरियाणा के इतिहास में पहली बार हुआ है। उसमें से आधा हिस्सा हाउसिंग बोर्ड को दिया जाएगा जो गरीब आदमियों के लिये छोटे–छोटे मकान बनाकर देगा और आधे में से छोटे–छोटे प्लाट हुडा देगा। (विघ्न)

डॉ० सुशील इन्दौराः अध्यक्ष महोदय हम.......

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, अब इनको याद आ गया, पहले नहीं आया। अब ये कान पकड़कर मुर्गा बनें। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सुशील इन्दौराः अध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्य मंत्री अपना व्यवहार ठीक करें। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: You have no right to cry like a jackal in the House. Mind your behaviour. (Interruption & Noise)

(इस समय इण्डियन नेशनल लोकदल के सदन में उपस्थित सभी सदस्य सदन के वैल में आ गये)

श्री नरेश यादवः स्पीकर साहब, आप इनको इनकी सीट्स पर बैठाएं। मेरा बहुत ही महत्वूर्ण प्रश्न लगा हुआ है। (शोर)....

डॉ० सुशील इन्दौराः अध्यक्ष महोदय,......... (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सीता राम: अध्यक्ष महोदय,........... (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: You are crossing the limit. Now, please take your seat. आप सभी अपनी–अपनी सीटों पर जाकर बोलें।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, मैं गरीब आदमियों के हक की बात बता रहा था। ये लोग गरीब आदमियों के हक की बात भी नहीं सुनना चाहते। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सुशील इन्दौरा: अध्यक्ष महोदय, ... (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: Indora ji, Please take your seat. I warn you. Nothing to be recorded. (Interruptions). Please take your seat. (Interruptions).

डॉ० सुशील इन्दौरा: अध्यक्ष महोदय, .अं...ऊ (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: Indora ji, Please take your seat.

डॉ० सुशील इन्दौरा: अध्यक्ष महोदय, ... (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: Indora ji, I warn you. Please take your seat.

डॉ० सीता राम: अध्यक्ष महोदय, ... (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: Sita Ram ji, Please take your seat. Nothing to be recorded.

डॉ० सीता राम: अध्यक्ष महोदय, ... (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: Please take your seat. आपने कोई बात कहनी है तो आप अपनी सीट पर जाकर कहें। (शोर एवं व्यवधान) डॉ० इन्दौरा जी, आप भी अपनी सीट पर जायें। (शोर एवं व्यवधान)। Sita Ram ji, I warn you. (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सुशील इन्दौरा: अध्यक्ष महोदय, ... (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सीता राम: अध्यक्ष महोदय, ... (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: If you have any grievance, you may please ask. Please take your seat. Sita Ram ji, maintain the decorum of the House.

श्री बलवंत सिंह: अध्यक्ष महोदय, ... (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: Balwant Singh ji, Please take your seat. Please understand the seriousness of the House. You are

snatching the rights of the other Members. Nothing to be recorded.

डॉ० सुशील इन्दौरा: अध्यक्ष महोदय, '''''मै (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सीता राम: अध्यक्ष महोदय, ... (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: डॉ० सीता राम जी, मैं किसी को शह नहीं दे रहा हूँ। If you do not have confidence in the Chair, you may go from the House. You have no right to waste the time of the House. If you want to say something, please go to your seat.

वाक–आउट

डॉ० सीता राम: अध्यक्ष महोदय, ... (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सुशील इन्दौरा: अध्यक्ष महोदय, परिवहन मंत्री का आचरण हमारे प्रति ठीक नहीं है। इसलिए ऐज ऐ प्रोटैस्ट हम सदन से वाक–आउट करते हैं।

(इस समय सदन में उपस्थित इण्डियन नैशनल लोकदल के सभी सदस्य सदन से वाक आउट कर गये।)

Mr. Speaker: Now, the question hour is over.

नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Construction of Bus-stand Nangal Chaudhary

***411. Shri Naresh Yadav:** Will the Minister for Transport be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a Bus-stand at Nangal Chaudhary in district Mahendergarh; and

(b) if so, upto what time it is likely to be constructed ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः

(क) नहीं, श्रीमान जी।

(ख) उपरोक्त (क) के मध्यनजर प्रश्न ही पैदा नहों होता।

Number of Heavy Industries located in Sonepat District

***367. Shri Dharam Pal Singh Malik:** Will the Minister for Finance be pleased to state—

(a) what is the number of Heavy industries located in Sonepat district with the details of their products and the number of employees working in the each industry on permanent and ad hoc basis; and

(b) what is the Industry-wise number of cases of

employees are pending in the Labour Courts or Civil Courts in the State with the reasons thereof and the stages of the cases ?

वित्त मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह):

(क) जिला सोनीपत में कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत 875 कारखाने पंजीकृत हैं जिनमें 44755 श्रमिक कार्यरत हैं। इस अधिनियम के अन्तर्गत संस्था के पंजीकरण के समय उद्योगों का विभेदीकरण नहीं किया जाता। इसलिये भारी उद्योगों से सम्बन्धित संख्या उपलब्ध नहीं है।

(ख) श्रम न्यायालय लम्बित केसों की संख्या उद्योग वार एवं स्तर वार नहीं रखते। इस समय राज्य के 7 श्रम न्यायालयों में औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 के अन्तर्गत 13०65 रैफेन्स तथा इस अधिनियम की धारा 33 (ग) 2 के अन्तर्गत 3210 प्रार्थना–पत्र जिनका कुल योग 16275 बनता है, लम्बित हैं।

Construction of MLAs' Flats

***383. Shri Tejendra Pal Singh Mann:** Will the Minister for PWD (B&R) be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct new MLAs' flats, if so, up to what time the said flats are likely to be constructed alongwith location thereof ?

बिजली मंत्री (श्री विनोद कुमार शर्मा): हाँ श्रीमान जी। राज्य सरकार की एक योजना चण्डीगढ़ में 27 नं० एम०एल०ए० फ्लैट बनाने के लिये विचाराधीन है। राज्य सरकार ने संघीय प्रशासन चण्डीगढ़ से अनुरोध किया है कि वह इस उद्देश्य के लिये विशेष–तौर पर उत्तरी सैक्टरों में भूमि आबंटित करे। चण्डीगढ़ संघीय प्रशासन द्वारा भूमि आबंटन के बाद ही निर्माण कार्य आरम्भ किया जाएगा।

Declaration of Pataudi and Farukhnagar as Sub-Division

***470. Shri Bhupinder Chaudhary:** Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to declare Pataudi and Farukhnagar as Sub-Division; and

(b) if so, up to what time the proposal is likely to be Materialized?

राजस्व मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव):

(क) नहीं, श्रीमान जी, फरुखनगर को उप मण्डल बनाने का सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। जहां तक पटौदी को उप मण्डल बनाने का सम्बन्ध है, प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(ख) पटौदी को उप मण्डल घोषित करने की समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती क्योंकि अन्तिम अधिसूचना परिसीमन आयोग, भारत सरकार, निर्वाचन सदन, अशोका रोड, नई दिल्ली की रोक हटने उपरान्त जारी की जा सकती है।

Withdrawal of HRDF Amount

***453. Dr. Sushil Indora:** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether the present Govt. has withdrawn the HRDF amount which was to be spent on various schemes during the current financial year the sanction to which was accorded by previous govt; if so, the district-wise details thereof; and

(b) the names of the schemes and manner in which the amount referred to part (a) above was utilized togetherwith the detail thereof ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा): नहीं, श्री मान जी,

(क) सभी चल रहे कार्य, केवल उनको छोड़कर जो कार्य जिला स्तर पर दिनांक 1.4.2005 तक शुरू नहीं किये गये, को सरकार द्वारा दी गई स्वीकृति के अनुसार पूर्ण करवाया जा रहा है तथा बोर्ड की हिदायतों अनुसार बकाया किस्तें जारी की जा रही हैं। (ख) हरियाणा ग्रामीण विकास निधि से राज्य में विभिन्न विकास कार्यों के लिये स्थानीय आवश्कताओं के अनुसार राशि खर्च की जा रही है।

सचिव द्वारा घोषणा

Mr. Speaker: Now, the Secretary will make an announcement.

Secretary: I have to inform the House that the Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Amendment and Validation) Bill, 2005, which was passed by the Haryana Legislative Assembly during the Session held in December, 2005, has been assented to by the Governor.

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव–

गुड़गांव में प्रदूषण संबंधी

Mr. Speaker: Hon'ble Members, I have received a calling attention motion No. 9 from Shri Dharam Bir Gauba, regarding the pollution in Gurgaon. Similarly, Calling Attention Notice No. 10 has also been received from Dr. Sushil Indora and Dr. Sita Ram, MLA, which has been bracketed with Calling Attention Notice of Shri Dharam Bir Gauba, MLA. I admit it. Shri Dharam Bir Gauba MLA may read his notice. Dr. Shushil Kumar Indora and Dr. Sita Ram, MLAs, who have given notice can also raise supplementaries.

Shri Dharam Bir Gauba: Sir, I want to draw the kind attention of this august House towards and urgent matter of public importance that as per report of the Central Pollution Control Board, the level of nitrogen oxide in Gurgaon areas has been found to be three times of national average. This has made Gurgaon the most polluted city in India in terms of nitrogen oxide contents. This may lead to cancer of

lungs. According to Dr. B. Sen gupta the Member Secretary of CPCB, it is an alarming situation. The population of Gurgaon is about twelve lacs plus eight lacs floating population. On account of it, there is risk of lives of twenty lacs people. I will request the Government of Haryana to explain the steps to be taken in this regard and save the people of Gurgaon from this menace.

Dr. Sushil Indora & Dr. Sita Ram, want to draw the attention of this august House towards a matter of urgent public importance that the increasing pollution due to the Nitrogen Oxide may cause adverse effect on the health of people of National Capital Region of Haryana State particularly in Gurgaon. The Maruti, D.L.F. and other big malls have installed heavy generator sets (2 Lac K.V.A.) to meet out the shortage of the electricity in which the pollution control units have not been installed. It pollutes the environment. Hence, it is a matter of urgent public importance.

Therefore, they request the Government to make a statement on the floor of the House for prevention of pollution.

Mr. Speaker: Now, the Environment Minister will make the statement.

डॉ० सुशील इन्दौरा: अध्यक्ष महोदय, ...

श्री अध्यक्ष: डॉ० साहब, आप बैठें। (विघ्न एवं शोर) यह कोई तरीका नहीं है आप सभी लोग अपनी–अपनी सीटों पर बैठें। (विघन एवं शोर)

डॉ० सीता राम: अध्यक्ष महोदय, ...

श्री अध्यक्षः डॉ० साहब, आप लोग को–आपरेट करें। (विघन एवं शोर) आपका यह व्यवहार ठीक नहीं है। Nothing to be recorded. आप अपनी–अपनी सीटों पर बैठें। (विष्य एवं शोर)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, इन लोगों से कहिए कि ये लोग अपने व्यवहार को ठीक करें और तहजीब सीख कर आएं। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, पहले इन लोगों को पार्लियामैंट प्रैक्टिस की ट्रेनिंग लेनी चाहिए और कुछ तहजीब सीखनी चाहिए। (विघ्न एवं शोर) अध्यक्ष महोदय, आप इनकी क्लास लगवाएं या इन्हें कहें कि ये अपना व्यवहार ठीक करें और सीखकर आएं कि सदन में कैसे व्यवहार किया जाता है। (विघ्न एवं शोर)

वाक–आउट

डॉ० सुशील इन्दौराः अध्यक्ष महोदय, परिवहन मंत्री जी का बोलने का तरीका ठीक नहीं है और इनका हमारे साथ . बिहेवियर भी ठीक नहीं है। आप हमें एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा उठाने की इजाजत नहीं दे रहे हैं इसलिए हम इसके विरोध में सदन का बहिष्कार करते हैं।

(इस समय इण्डियन नैशनल लोकदल कैं सदन में उपस्थित सभी सदस्य वाक आउट कर गए।)

श्री राम कुमार गौतमः स्पीकर साहब, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। डॉ० सीता राम जी पहले पाँच साल एम०एल०ए० रह

चुके हैं। इनका वैल्फेयर बजट जो एस०सीज० और बी०सीज० के लिए तीन करोड़ रुपये था उसको एक करोड़ रुपये कर दिया गया है। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि मैंने समझा था कि ये लोग कन्स्ट्रक्टिव ओपोजीशन करेंगे। हम भी विरोधी पक्ष के आदमी हैं। जिस आदमी ने एक करोड़ के बजट को 80 करोड़ रुपये कर दिया उस आदमी के खिलाफ तो ये लोग बगावत करते हैं। जिस व्यक्ति ने तीन करोड़ रुपये से इनका बजट एक करोड़ रुपये करके इनका बीज मार दिया उसके खिलाफ ये पाँच साल चुस्के भी नहीं। जब मण्डल कमीशन बना था तो गरीब बछड़े की खोर में थोड़ा सा चारा डाला था लेकिन जिस आदमी ने उस चारे को खाने के लिए साण्ड और झोटे छोड़ दिए उसके खिलाफ ये लोग एक हर्फ भी नहीं बोले। (विघ्न)

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा): अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा पिछले सैशन में भी मैंने एक बात कही थी। आपको भी याद होगा उस समय आप भी इस सदन के मैम्बर थे और मैं विपक्ष का नेता था। जो भाई आज बाहर गए हैं जब इन लोगों की सरकार थी तो आप जब भी कोई बात उठाते थे तो आपको हाउस से बाहर कर दिया जाता था। हमारे बाहर जाने के बाद हाउस की कुण्डी लगा दी जाती थी ताकि हम हाउस के अन्दर न आ सकें। मैंने पिछली बार भी आपसे निवेदन किया था कि ये लोग ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं कि आपको यहां पर कुण्डी लगानी पड़ेगी ताकि ये लोग हाउस से बाहर न भागें। जब

कोई बात आती है तो ये लोग सदन से बाहर भाग जाते हैं और हाउस में कोई पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं, अपना कोई योगदान नहीं करते हैं, कोई सुझाव नहीं देते हैं। आगे से अगर ये लोग ऐसा प्रयास करें तो आपसे निवेदन है कि हाउस की कुण्डी अन्दर से लगवाने की कृपा करें ताकि ये लोग बाहर न भाग सकें।

Mr. Speaker: Certainly, it is very serious matter. They have submitted their Calling Attention Motion pertaining to this problem. I have accepted their Calling Attention Motion and now they have staged a walk out. They are not serious about it.

वक्तव्य–

उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी बिजली मंत्री द्वारा–

Mr. Speaker: Now, the Environment Minister will give the reply.

बिजली मंत्री (श्री विनोद कुमार शर्मा): अध्यक्ष महोदय, हमारे अपोजीशन के साथी सदन से उठकर चले गये हैं। उन्होंने सदन में एक कालिंग अटैंशन मोशन रिगार्डिंग एयर पोल्यूशन दिया था। लेकिन वे यहां सदन में साऊंड पोल्यूशन पैदा करके चले गए हैं। वे सदन के वातावरण को खराब करके गए हैं जिस वजह से सदन का समय बर्बाद हुआ है। The report that Nitrogen Oxide level in the Gurgaon area is very high, is based on a one-day survey conducted by Central Pollution Control Board (CPCB) on 7.12.2005. This survey was conducted using a mobile

laboratory, which collected samples of air at one location only, near the commercial areas. This is pertinent to mention that the way the samples were collected and mobile vehicle was used, that methodology' was not correct. it is scientifically recognized that one time, sampling conducted at one location cannot be generalized for the entire area. CPCB has subsequently stated that detailed monitoring at different locations is necessary to ascertain the actual values of Nitrogen Oxide in the Ambient Air of Gurgaon or any other area. Moreover, such a monitoring is required to be done over a prolonged period for getting the correct results. The Haryana State Pollution Control Board (HSPCB) has Air Quality Monitoring Stations at Gurgaon at two locations. In addition, similar monitoring stations are operating in five industrial units located at different locations. The stations have consistently shown that Nitrogen Oxide presence in Gurgaon is ranging between only 10-51 micro grams per cubic meter. This data covers the period from January 2006 to mid March 2006. As such, it would be clear that Nitrogen Oxide levels in Gurgaon area are perfectly safe and are not alarming as alleged. It is misleading to State that the present level of Nitrogen Oxide in Gurgaon would cause cancer. The data obtained from the Health Department indicates that there are no reported cases of cancer of the lungs in Gurgaon area for the last 3 years including the current year. There is no cause for any health alarming related whatsoever. The fact is that on an average Gurgaon continue to enjoy a much better ambient quality of air than Delhi.

The State Government is fully conscious of its responsibilty to provide a healthy and pollution free

environment to the people of Gurgaon and the entire State. The HSPCB has acted to reduce the generation of Nitrogen Oxide at the source by issuing clear directions to all large establishments like shopping malls, residential buildings, industrial units etc. which operate diesel and CNG based power generators to reduce emissions to below the prescribed standards. 67 establishments using generating sets have been issued Show Cause Notices under the Air Act of 1981. If these units do not reduce Nitrogen Oxide emissions, within a prescribed period, closure of the unit or prosecution would follow. The board is proposing to install an automatic Air Quality Monitoring Station which gives pollution data continously, at a cost of rupees sixty lass at Faridabad, to be followed by Gurgaon. To control vehicular pollution the following steps are being taken as a part of the Ambient Air Quality Improvement Action Plan being implemented Faridabad. Efforts will be made to replicate these steps in Gurgaon and other cities of NCR. (a) Introduction of Euro-4 norms, which set high standard of vehicular pollution. (b) Improvement of fuel quality. (c) Phasing out 15 years old commercial vehicles. (d) Preventon adulteration in retail outlets. (e) Encouraging public transport. It is expected that with the construction of the eight lanes highway in Gurgaon, the express highway and other fast moving roads, the vehicular pollution would reduce due to faster movement of traffic.

Further, large construction projects are being cleared environmentally only if they commit to keep 20 % of their area under green belt.

In all public hearing for environmental clearance of construction projects, the condition for maintaining low Nitrogen Oxides emissions from generators is being prescribed. The State Government would like to be assured that Gurgaon is and will remain a clear and healthy city with one of the best living environment in India.

श्री धर्मबीर गाबाः अध्यक्ष महोदय, आनरेबल मिनिस्टर साहब ने यह तो बताया नहीं कि गुडगांव के अंदर पोल्यूशन के काजिज क्या हैं। सैंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट में कहा गया है कि गुड़गांव के अंदर नाइट्रोजन आक्साईड का लैवल नेशनल लैवल से तीन गुणा ज्यादा है। क्या सरकार के नॉलेज में यह बात है कि यह मामला अंडर कसीड़ेशन में है। क्या सरकार गुड़गांव में पूरी बिजली सप्लाई करेगी ताकि जैनरेटर आदि से वहां पर फैलने वाली नाईट्रोजन गैस हमेशा के लिए खत्म हो जाए।

श्री विनोद कुमार शर्माः स्पीकर सर, जैसे सबको मालूम है कि हरियाणा में जितनी बिजली को हमें जरूरत हैं उतनी बिजली हमारे पास नही है। सोईग सीजन खासकर पैडी सीजन के समय हमारी सरकार का फैसला है कि किसी भी किसान की खड़ी फसल बिजली के बगैर सूखनी नहीं चाहिए पानी की किल्लत नहीं होनी चाहिए। किसी भी किसान को पानी की किल्लत की वजह से फसल लगाने का मौका नहीं मिलना चाहिए। स्पीकर सर, किसानों को पानी की दिक्कत न हो, इसको देखते हुए ही हमारी सरकार

की कोशिश रही है कि किसानों को जब भी जितनी बिजली की जरूरत हो और जितनी भी बिजली उनको उपलब्ध करवायी जा सकती हो, वह करवायी जाए। ऐसे माहौल में अगर हम इंडस्ट्रीज वालों के जैनरेटर बंद कर देंगे तो टोटल हरियाणा में इण्डस्ट्रीज पर इसका असर पडेगा और हमारी इण्डस्ट्रीज इसको सह नहीं पाएंगी।

श्री धर्मबीर गाबा: अध्यक्ष महोदय, मेरा कहने का यह मतलब नहीं था कि किसानों को बिजली देना बंद कर दें। मेरा कहने का मतलब यह था कि इण्डस्ट्रीज के लिए बिजली देने के लिए कुछ घंटे मुकर्रर कर दें। पी०सी०ए० की रिपोर्ट इन्होंने देखी होगी। मारुति के अंदर जो जैनरेटर बिजली सप्लाई के लिए चलता है, उससे काफी मात्रा में नाईट्रोजन गैस गुड़गांव के अंदर फैलती है। स्पीकर साहब, मेरी मंत्री जी से अर्ज है कि जो मारुति जैनरेटर से बिजली पैदा करती है उससे बहुत ज्यादा नाईट्रोजन गैस पैदा होती है क्या मंत्री जी मारुति उद्योग वालों को इस बारे में कुछ कहेंगे या नहीं?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा): अध्यक्ष महोदय, मैं गाबा साहब की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा और जैसे मंत्री जी ने भी बताया है 1 आने वाले तीन साल के अंदर गुड़गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए रोडज को चौड़ा करने के लिए हुडा 700 करोड़ रुपये लगाने जा रहा है। इसी तरह से गुड़गांव को ग्रीन बनाने के लिए भी अलग स्कीम सरकार द्वारा

चलायी जा रही है। इसी तरह से गुड़गांव के लिए हम सी०एन०जी० बसिज भी खरीदने जा रहे हैं ताकि वहां पर प्रदूषण कम हो।

नियम 16 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker: Hon'ble Members, nov, the Parliamentary Affairs Minister will move the Motion under Rule 16.

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to move—

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine die.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine die.

श्री राम कुमार गौतम (नारनौंद): अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि पंजाब विधान सभा का सैशन चालीस दिन चला है। जब हम यहां पर सारे इशूज डिसकस नहीं कर सकते तो सैशन बुलाने का क्या फायदा है। कम से कम सैशन का इतना समय तो जरूर रखा जाए कि यहां पर सारी बातें जो हम कहना चाहते हैं, कह सकें और उन पर सदन में खुलकर चर्चा कर सकें।

श्री अध्यक्षः गौतम साहब, बजट पर आप 35 मिनटस बोले हैं और अब एप्रोप्रिएशन बिल पर आप खुलकर बोल लें, हमें कोई दिक्कत नहीं है।

श्री राम कुमार गौतमः ठीक है सर।

Mr. Speaker: Question is—

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine die.

The motion was carried.

विधान सभा की समितियों की रिपोर्टस प्रस्तुत करना

(1) आश्वासन समिति

Mr. Speaker: Hon'ble Members, Now Shri Sukhbir Singh Rohat, Chairperson, Committee on Government Assurances will present the Thirty Fifth Report of the Committee on Government Assurances for the year 2005-2006.

श्री सुखबीर सिंह रोहटः अध्यक्ष महोदय, मै वर्ष 2005—20ç6 के लिए आश्वासन समिति की 35वी रिपोर्ट को सादर प्रस्तुत करता हूँ।

खिलाडियों को बधाई

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा): अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माननीय सदस्यों के सामने एक हर्ष की बात की एनाउसमेंट करना चाहता हूँ। मैलबोर्न के कॉमनवैल्थ गेम्ज में जो

हमारे हरियाणा के खिलाड़ी गये हैं उनकी परफोर्मेस बहुत अच्छी रही है। जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि कुमारी सीमा अन्तिल ने एथैलेटिक्स में सिल्वर मंडल जीता है इसलिए उसको सरकार ने 5 लाख रुपये देने की घोषणा की है। इसी तरह से श्री जितेन्द्र कुमार ने बोक्सिंग में ब्रोन्ज मैडल जीता है उसको भी सरकार ने 3 लाख रुपये देने की घोषणा की है। हमारी लड़कियों की हॉकी की टीम भी फाईनल में पहुँच गई है। इनमें पाँच लड़कियाँ कुमारी राजविन्द्र कौर, कुमारी जसविन्द्र कौर, कुमारी सुरेन्द्र कौर, कुमारी रजनी बाला और कुमारी ममता खरब हरियाणा प्रदेश की हैं और बोक्सिंग में बिजेन्द्र कुमार और अखिल कुमार भी फाईनल में पहुँच गये हैं।

विधान सभा की समितियों की रिपोर्ट्स प्रस्तुत करना (पुनरारम्भ)

(2) अनुसूचित जातियों, जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति

Mr. Speaker: Hon'ble Members, Now Shri Udai Bhan, Chairperson, Committee on the Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes will present the Twenty Ninth Report of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes for the year 20052006.

Shri Udai Bhan (Chairperson, Committee on Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes): Sir, I beg to present the Twenty Ninth Report of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes for the year 2005-

2006.

(3) लोक लेखा समिति

Mr. Speaker: Now, Shri S.S. Surjewala, Chairperson, Committee on Public Accounts will present the Fifty Eighth Report of the Committee on Public Accounts for the year 2005-2006 on the Report of the Comptroller and Auditor General of India for the years ended 31st March, 1999 (Revenue Receipts) and 31st March, 2000 (Civil and Revenue Receipts).

Shri S.S. Surjewala (Chairperson, Committee on Public Accounts): Sir, I beg to present the Fifty Eighth Report of the Committee on Public Accounts for the year 2005-2006 on the Report of the Comptroller and Auditor General of India for the years ended 31st March, 1999 (Revenue Receipts) and 31st March, 2000 (Civil and Revenue Receipts).

(4) लोक उपक्रम समिति

Mr. Speaker: Now, Shri Shadi Lal Batra, Chairperson, Committee on Public Undertakings, will present the Fifty Second Report of the Committee on Public Undertaking for the year 2005-2006 on the Reports of the Comptroller and Auditor General of India for the years 1999-2000, 2000-2001 & 2001-2002 (Commercial).

Shri Shadi Lal Batra (Chairperson, Committee on Public Undertakings): Sir, I beg to present the Fifty Second Report of the Committee on Public Undertakings for the year 2005-2006 on the Reports of the Comptroller and Auditor

General of India for the years 1999-2000, 2000-2001 & 2001-2002 (Commercial).

सदन की मेज पर रखे गये कागज–पत्र

Mr. Speaker: Now, the Parliamentary Affairs Minister, will lay papers on the Table of the House.

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to lay on the Table—

The 5th Annual Report of Dakshin Haryana Bijli Vitran Nigam Limited for the year 2003-2004, as required under Section 619-A(3)(b) of the Companies Act, 1956.

The 5th Annual Report of Uttar Haryana Bijli Vitran Nigam Limited for the year 2003-2004, as required under Section 619-A(3)(b) of the Companies Act, 1956.

The Annual Report of Haryana Police Housing Corporation Limited for the year 2002-2003, as required under Section 619-A(3)(b) of the Companies Act, 1956.

The Annual Statement of Accounts of Haryana Urban Development Authority for the years 2000-2001 to 2002-2003, as required under Section 19-A(3) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971.

The 7th Annual Report of Haryana Vidyut Prasaran Nigam Limited for the year 2003-2004, as required under Section 619-A(3)(b) of the Companies Act, 1956.

विधान कार्य

दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (नं० 1) बिल, 2006

Mr. Speaker: Now, the Finance Minister will introduce the Haryana Appropriation (No. I) Bill, 2006 and will also move the motion for its consideration.

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir. I beg to introduce the Haryana Appropriation (No. 1) Bill, 2006.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Appropriation (No. 1) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Haryana Appropriation (No. 1) Bill be taken into consideration at once.

श्री राम कुमार गौतम (नारनौंद): स्पीकर सर, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया। मैं आपके माध्यम से कुछ बातें इस सदन की जानकारी में लाना चाहता हूँ जो बहुत गम्भीर बातें हैं। कल तीन नॉन आफिशियल बिल आये थे।

राजस्व मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव): अध्यक्ष महोदय, मैं सदन की जानकारी के लिये बताना चाहूँगा कि बहुत से सदस्यों ने सईस शट्स की प्रोसैसिंग फीस के बारे में चिंता व्यक्त की थी, हम 50 प्रतिशत अमाउंट उन किसानों को वापिस कर देंगे।

श्री राम कुमार गौतमः अध्यक्ष महोदय, मैं तो मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि पूरा पैसा वापिस मिलना चाहिए था। लेकिन ठीक है, कुछ नहीं से तो कुछ दिया वह अच्छा है। अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ गम्भीर बातों की तरफ सदन का ध्यान दिलाना चाहूँगा जो बजट पर बोलते वक्त मैं नहीं कह पाया था। इस समय किसानों की फसल मण्डियों में आने वाली है और मैंने सुना है कि भारत सरकार दूसरे देशों से 95० रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूँ का आयात करेगी। अगर भारत सरकार ने ऐसा किया ते हमारे देश के किसान तबाह हो जाएंगे। हमारे प्रदेश में किसानों को गेहूँ का 640 रुपये प्रति क्विंटल का भाव दिया जा रहा है और भारत सरकार बाहर से 950 रुपये प्रति क्यिंटल के हिसाब से गेहूँ का आयात क्यों कर रही है। मैं हमारे प्रदेश के सभी कांग्रेस भाइयों से प्रार्थना करूँगा क्योंकि हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है आप सभी श्रीमती सोनिया गांधी जी से मिलकर, प्रधानमंत्री जी से मिलकर अपील करें कि गेहूँ का आयात करके यह जघन्य अपराध न करें। जितना भी गेहूँ उनको चाहिए वह हमारे यहां मिल जाएगा। अध्यक्ष महोदय, गैहूं का आयात होगा तो हमारे देश के किसान बर्बाद हो जाएंगे और किसान बर्बाद हो गये तो देश भी बर्बाद हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब से केन्द्र में कांग्रेस की सरकार बनी है तब से मंहगाई दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ रही है। हर मामले में कमर तोड मंहगाई हो गई है। जिस समय किसानों की फसल तैयार होती है उस समय हर फसल कम रेट पर बिकती है और उसके थोड़े दिन

बाद हर चीज के रेट आसमान को छू जाते हैं। गेहूँ के आटे के भाव 12 रुपये किलो तक हो जाते हैं। चीनी, गुड, गैस सिलेंडर आदि के दाम बहुत बढ़ रहे हैं। जिस समय केन्द्र मैं वाजपेयी जी की सरकार की उस समय गैस सिलेंडर हर गली में मिलते थे लेकिन पता नहीं आज वह सिलेंडर कहा चले गए। बुकिंग करवाने के हफ्ते बाद भी गैस सिलेंडर नहीं मिलते। हर तरफ काला बाजारी हो रही है। मेरी कांग्रेस पार्टी के नेताओं से अपील है कि वे सोनिया गांधी जी के दरबार में जायें और कहें कि जो कालाबाजारी करने वाले हैं उनको सख्त दण्ड दिया जाये ताकि आम आदमी सुख की साँस ले सके। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं एक बात मुख्यमंत्री जी के नोटिस में लाना चाहूँगा जो लोगों के धार्मिक सैंटीमैंट्स से जुड़ी हुई है। गुड़गांव में जब से शीतला माता का मंदिर बना है तब से उस मंदिर में अखण्ड ज्योति जलती आ रही थी लेकिन अब वह बंद है। यह वहां के लोगों की धार्मिक आस्था का मामला है इसलिये मैं हुड्डा साहब से प्रार्थना करूँगा कि वे डी०सी० को आदेश दें कि उस मंदिर में अखण्ड ज्योति जलवाई जाये। लोग तो कहते हैं कि हुड्डा साहब को तो इस तरह की बातों का पता नहीं होगा। इस तरह की बातें लोकल प्रशासन की निगाह में होती हैं। अध्यक्ष महोदय, अब मैं लेबर पालिसी के बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूँ। मेरे से पहले भाई कर्ण सिंह दलाल ने भी इस बारे में चर्चा की है। मैं इस बारे में कहना चाहूँगा, खासतौर से हमारे वित्त मंत्री महोदय जी से क्योंकि ये लेबर मिनिस्टर भी हैं, हमारे भाई भी हैं, बहुत ही अफसोस की

बात है कि लेबर के मिनिमम वेजिज 2480 रुपये हैं और वह भी किसी फैक्टरी में लागू नहीं हैं। हर फैक्टरी में मजदूरों की एक्सपलॉयटेशन है ओर वे मजदूर हमारे ही बच्चे हैं। इसीलिए हरियाणा के 90% बच्चे वहां पर काम नहीं कर रहे हैं। हमारे हरियाणा के करीब 10% बच्चे ही वहां पर काम कर रहे हैं। लेबर क्लास की बड़ी भारी एक्सपलॉयटेशन हो रही है। वे भी हमारे बच्चे ही हैं इसलिये सरकार से मेरा यह निवेदन है कि सरकार को सख्त कार्यवाही करनी चाहिए और जो कम से कम मिनिमम वेजिज आपने रखे हैं वे जरूर पूरे उनको दिलवाएं। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने जो मिनिमम वेजिज 2480 रुपये रखा है वह भी बहुत कम है, कम से कम तीन हजार रुपये मिनिमम वेजिज होने चाहिएं और उन वेजिज को सख्ती से लागू करना चाहिए। एक आदमी एक फैक्टरी लगाता है और चार पांच साल में ही उसकी 4 या 5 फैक्टरियां बन जाती हैं और वह मालोमाल हो जाता है। जितने भी उद्योगपतियों ने दिल्ली से हरियाणा में आकर कारखाने लगाए हैं वे सारे मालोमाल हो गए हैं। करोडोपति और अरबोंपति हो गए हैं लेकिन वह बेचारा मजदूर शाम को रोटी के लिए भी तरसता है। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मेरी आपके माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी तथा वित्तमंत्री जी से यह प्रार्थना है कि वे इस तरफ गौर फरमाएं। अध्यक्ष महोदय, सरकार किसानों के लिए भी सोचे। जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार आई है तब से इस सरकार ने किसानों का बुरा हाल करके रख दिया है। सिर्फ मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने शूगरकेन का 135 रुपये क्विंटल का

भाव किसान को दिया है। जो भाई ईख की खेती करते हैं उनके लिए सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। इसके लिए मैं इनको बधाई देता हूँ। इसके अलावा इस सरकार ने जितने भी फैसले किए हैं वे किसान के हित में नहीं हैं। (विघन) देखिए मैं जो भी बात कहूँगा वह ठीक बात ही कहूँगा और सही बात कहे बगैर रहूँगा नहीं। पिछले डेढ़ साल में इस सरकार ने जमींदार को मारा है। यह किसानों की स्टेट है इसलिए आप उनको समझिये और किसान मार न करें। वाजपेयी जी के समय में कितने प्यारे भाव थे कपास का भाव, गेहूँ का भाव हर चीज का उचित रेट किसान को मिला था और किसान मालामाल हो गया था लेकिन यह सरकार आने के बाद किसान पर जितना गण्डासा चला है उसकी कोई हद नहीं 1 अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से हमारे नेता और सरकार में जो मीनिंगफुल कांग्रेसी भाई हैं उनसे मेरा कहना है कि कम से कम किसान पर गण्डासा न चलाओ और किसान को उसकी उपज का अच्छा भाव दिलाओ तथा इस मंहगाई को काबू करो।

श्री एस०एस० सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, मेरा ज्वायंट ऑफ ऑर्डर है। हमारे आदरणीय पंडित जी बहुत अच्छे इन्सान हैं और हाउस में भी ये बड़ा कंट्रीब्यूशन करते हैं। तकरीबन 6– 7 दिन से यह सैशन चल रहा है। पिछले दिनों में इन्होंने जितने भी ध्यान दिए हैं उनमें सरकार ने जो किसानों के हित के फैसले किए हैं उनके लिए सरकार की तारीफ की है। सरकार ने किसानों के 1600 करोड़ रुपये के बिजली के बिल माफ किये हैं, किसान की

जमीन के अधिग्रहण की एमाउंट सरकार ने बहुत ज्यादा कर दी है। आज खेती की जमीन का कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई है शायद ये आज सारी बातें भूल गए हैं। यह सारा कुछ भूलकर एक नया चौप्टर, एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं वाजपेयी जी की तरीफ करने का। अध्यक्ष महोदय, वाजपेयी जी ने तो किसानों को बिलकुल खत्म ही कर दिया था। अगर दिल्ली में और यहां पर कांग्रेस का राज नहीं आता तो आज किसान उजड़ कर कहीं दूसरे प्रांत में चला जाता। (विघ्न)

11.00 बजे

श्री राम कुमार गौतमः अध्यक्ष महोदय, हम तो जो बात है वह खुद कहेंगे और जो बात कहेंगे वह मीनिगफुल होगी। मुख्यमंत्री जी ने जो बात सही की है हमने तो उसके लिए उनकी तारीफ की है और आज भी हम उनकी तारीफ करते हैं। उन्होंने जितने भी अच्छे फैसले लिए हैं मैंने उन सभी की तारीफ की है और जो कमियां हैं उनके बारे में मैं इसलिए ध्यान दिला रहा हूँ कि अगर ये आज कण्ट्रोल नहीं करेंगे तो इनका हाल भी अगले गेडे में हमारे वाला होगा कि दो मैम्बर ही आ पाएंगे। इसलिए मैं इनको यह कहना चाहता हूँ कि समय रहते ये संभल जायें। अध्यक्ष महोदय, सरकार के कई डिपार्टमैंट्स और कारपोरेशन्ज हैं। कारपोरेशन्ज के बारे में तो मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है कि उनमें एक्स–ग्रेशिया की कोई सुविधा है या नहीं है। बात समय की सीमा की है कि इस समय तक एक्स–ग्रेशिया का बेनिफिट देना है। अभी

जो एक्स–ग्रेशिया की पालिसी बनी है कि पाँच लाख रुपये एक्स–ग्रेशिया वाले भाई को दिये जाएंगे लेकिन उनो सर्विस नहीं मिलेगी। मैं इस बात के लिए मुख्यमंत्री जी तथा उनके सहयोगी भाई बीरेन्द्र सिंह का भी धन्यवाद करता हूँ और उनकी तारीफ करता हूँ। रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने being a Parliamentary Affairs Minister announce किया था। सरकार का यह फैसला बहुत ही अच्छा है लेकिन समय सीमा किसलिए लगाई। जिसका बाप वर्ष 2000 में मर गया उसका क्या गुनाह है, उस पर एक्स–ग्रेशिया की स्कीम को करें और जिसका जो भी जब भी मरा है उसको पाँच लाख रुपये दें या उसको नौकरी दे दो। आप इस पालिसी को सभी बोर्ड और कारपोरेशंज में लागू करें। अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के में एक उदय भान बाल्मीकि बच्चे की मृत्यु हो गई थी और चार साल से उसकी पत्नी जिसका नाम अंग्रेजो है उसको आज तक कुछ नहीं मिला है। विभाग वाले कहते हैं कि कानून में कोई प्रावधान नहीं है। हुड्डा साहब, आप ऐसे कानून को बदल दो और 2003–04 से इसको सभी बोर्डज और कारपोरेशंज में लाग करो। अगर आप ऐसा करते हैं तो लोग आपके गीत गाएंगे। इसके साथ मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप इसको मैंडेटरी कर दें कि जहां कहीं भी ओलावृष्टि होती है तो उसी गाँव का पटवारी जाकर 15 दिन के अंदर– अंदर चौक करे कि किस की कितनी फसल नष्ट हुई है और उसको मौके पर ही मुआवजा दे दिया जाए। अगर पटवारी इसमें बदमाशी करे कि जिसका नुकसान नहीं हुआ है उसका नाम लिख ले और जिसका

नुकसान हुआ है उसका नाम न लिखे तो उसको सीधा ही डिसमिस कर दिया जाए। मंत्री जी ऐसा करना आज की तारीख में बहुत ही जरूरी है। अध्यक्ष महोदय, एक बात और है जिसके बारे में सदन में काफी सदस्यों ने जिक्र किया है। यह जो बी०पी०एल० के कार्डज का मामला है यह बहुत ही जरूरी मामला है। अगर आप अभी भी चौक करेंगे तो 100 में से 90 कार्डज आपको गलत ही मिलेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहता हूँ कि गाँवों के बच्चों के साथ किसी सीनियर आफिसर की ड्यूटी लगाएं और वह सर्वे करके एक नई लिस्ट तैयार करे चाहे इन कार्डज को बनाने में एक महीने की और देरी क्यों न हो जाए। अभी तो सभी खागड और मोलड उसमें भर रखे हैं, बेचारी बछडिया तो मरी पड़ी हैं।

अध्यक्ष महोदय, एक बात और कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। हाल में सरकार ने हुडा के माध्यम से जो प्लाट निकाले हैं उसमें सारे बैंकों ने फाईनैंस किया है जिसकी वजह से वे बैंक मालामाल हो गए हैं और हुडा भी मालामाल हो गया है। लेकिन हमारे जो कोऑपरेटिव बैंक हैं वे मालामाल नहीं हुए हैं। वे इसलिए नहीं हुए हैं क्योंकि उनको इस स्कीम में शामिल नहीं किया गया था। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि इस्में हमें अपने कोऑपरेटिव बैंकों को भी उसमें शामिल करना चाहिए ताकि हमारे बैंक भी मालामाल हों और हमारे बच्चों को भी उसमें काम मिल सके।

अध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने पानीपत थर्मल पॉवर प्लांट के नाम से चौधरी देवीलाल जी का नाम हटा दिया है और उसका नाम कुछ और रख दिया है। इसका मुझे बहुत दुःख है। जिस बात का अंदेशा मुझे था वही आपने किया है कहीं इन्दिरा जी के नाम से और कहीं राजीव गांधी जी के नाम से स्कीमों का नाम रखा है। मेरा आपसे मार्मिक निवेदन है कि आप नाम बदलें तो हिसाब से बदलें। आप महान नेताओं के नाम से नाम बदलें। अब पिछली सरकार ने जगह– जगह बुत लगा दिए थे और जब सुबह बच्चा उठता था तो डर जाता था कि क्या आ गया। अगर आपको नाम बदलना है तो शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, राम सिंह, असफातुला खाँ सुभाष चन्द्र बोस, गुरु गोबिन्द सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु रविदास, कबीरदास, चौधरी चरण सिंह जैसों के नाम से बदलो। अपने दादा चौधरी मातूराम जी के नाम से बदल दो, मैं विरोध पक्ष का आदमी होने के बावजूद यह कह रहा हूँ। आप ऐसा करो तो, कोई इसका विरोध नहीं कर सकता। वे फ्रीडम फाईटर्ज थे उनके नाम से आप ऐसा कर दो। स्वामी दयानंद सरस्वती के नाम से बदल दो, स्वामी विवेकानंद के नाम से बदल दो, ऋषि वाल्मिकी के नाम से बदल दो, रानी लक्ष्मी बाई के नाम से बदल दो, मंगल पाण्डे के नाम से बदल दो, वीर सावरकर के नाम से बदल दो, महात्मा गाँधी के नाम से बदल दो, सरदार बल्लभ भाई पटेल के नाम से बदल दो, लोकमान्य तिलक के नाम से बदल दो, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के नाम से बदल दो, लाला लाजपतराय के नाम से बदल दो, भामाशाह के नाम से बदल

दो या बंदा बहादुर के नाम से बदल दो, हमें इन नामों पर कोई एतराज नहीं है। हरियाणा की 80 परसैंट जनता इस बात के लिए आपकी सराहना करेगी और कहेगी कि इन्होंने यह बहुत अच्छा काम किया है। ऐसा करने पर बेशक हमारे भी नेता अगर क्रिटीसाइज करते हों तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं है आप हिसाब से नाम रखो। आपको इन महान लोगों के नाम पर योजनाओं के नाम रखने चाहिएं। अगर आप सिर्फ राजीव गांधी, इंदिरा गांधी फलाना गांधी के नाम से इनके नाम बदलोगे तो फिर रोला तो पड़ ही जाएगा। लोग फिर यह भी कहेंगे कि ये लोग भी उसी चाल पर चल पड़े हैं जिस चाल पर पिछली सरकार चला करती थी।

राजस्व मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव): अध्यक्ष महोदय, जो ये राजीव गांधी के नो में इस तरह की बात का रहे हैं यह अम्मी बात नटी है। इनको ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिएं। इंदिरा गांधी ने देश के हित के लिए शहादत दी है।

श्री अध्यक्ष: गौतम साहब, आप टोपिक पुर ही बोलें।

श्री राम कुमार गौतम: अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह कह रहा हूँ कि हिसाब से नाम बदलो। मैं कब कहता हूँ कि राजीव गांधी देश का ..... था। राजीव गांधी के नाम से भी एक आधा नाम बदल दो लेकिन अगर सारी योजनाओं के नाम उनके नाम पर रखोगे तो यह ठीक नहीं है।

श्री अध्यक्षः जो गौतम साहब ने अनपार्लियामैंट शब्द कहा है उसको डिलीट कर दिया जाए।

श्री राम कुमार गौतमः अध्यक्ष महोदय, हमारी जो बात समझ में आयी वह हमने कह दी और जो बात इनको समझ में आये वह ये कह दें।

श्री अध्यक्षः गौतम साहब, आप ऐप्रोप्रिएशन बिल पर ही बोलें। (विघन) आप टोपिक पर ही बोलें।

वित्त मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह): स्पीकर साहब, राम कुमार गौतम जी ने एक लम्बी फैहरिस्त बताई कि इन आदमियों के नाम से संस्थाओं के नाम होने चाहिएं। जब देवीलाल जी के नाम से अनेक संस्थाएं बन रही थी तो उस समय ये भी सरकार में साझीदार थे। क्या कभी इन्होंने इस चीज का ऐतराज किया? हम यह भी मानते हैं कि अगर पाँच जगह, सात जगह, दस जगह या बीस जगहों पर देवीलाल जी की याद में कुछ बनता तो कोई बात नहीं थी लेकिन दूसरे भी जौ शहीद हुए हैं जिनका राष्ट्र निर्माण मैं योगदान है, उनके नाम से भी कुछ बनाते तो किसी को कोई ऐतराज नहीं था। हमें आज भी इस बात का कोई ऐतराज नहीं है लेकिन जिस तरीके से गौतम साहब कह रहे हैं तो ये हमें बताएं कि क्या आज तक के इतिहास में देश आजाद होने के बाद राजीव गांधी और इंदिरा गांधी से बड़ी कोई कुर्बानी ऐसी है जो इनके नेता ने दी हो? यह इनकी मानसिकता ही है कि वीर सावरकर को

तो यह महान योद्धा बताते हैं लेकिन राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के नाम पर इनको एतराज होता है। यह इनकी मानसिकता का ही प्रतीक है। इसलिये भारतीय जनता पार्टी से देश प्रेमी लोगों को कोई सहानुभूति नहीं है क्योंकि इनका किसी प्रकार से योगदान नहीं है।

श्री राम कुमार गौतमः स्पीकर साहब, मैं इनकी बात का जवाब दे देता हूँ।

श्री अध्यक्षः आप जवाब न दें बल्कि आप एप्रोप्रिएशन बिल पर ही बोले।

श्री राम कुमार गौतमः स्पीकर साहब, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि राजीव गांधी का नाम न रखो। मेरा कहना यह है कि सिर्फ राजीव गांधी के नाम से ही योजनाओं के नाम न रखो। मैं राजीव गांधी जी को क्रिटीसाईज नहीं कर रहा हूँ।

श्री बीरेन्द्र सिंहः आप बताएं कि राजीव गांधी जी के नाम से हमें कितने नाम रखे हैं? आप तो ऐसे ही कहने के लिए इस तरह की बात कह रहे हो।

श्री राम कुमार गौतमः स्पीकर साहब, मैं तो सुझाव दे रहा हूँ और आगे के लिए इनको आगाह कर रहा हूँ ताकि ये जो योजनाओं के नाम रख रहे हैं वह बच जाएं और जो अपमान चौटाला साहब ने करवाया है वह इनका न हो। स्पीकर साहब, मैंने तो उन भाईयों को भी कहा है कि भले आदमियों, तुम आदमी

सारे अच्छे हो लेकिन नेता गलत पकड़ रखा है। अध्यक्ष महोदय, जो आदमी एस०सीज० और बी०सीज० की शक्ल देखकर राजी न हो, जो कभी सपने में भी देखकर उनसे चिढ़ता हो तो वह इन लोगों का क्या भला कर सकेगा? यह तो भला हो संविधान बनाने वालों का जिनकी वजह से हम सब यहां पर बैठे हैं। अगर संविधान ने आरक्षण न दिया होता तो चौटाला इनकी खाल खिंचवा देता।

Mr. Speaker: Gautam Sahib, please come on the topic. You are speaking on the Appropriation Bill.

श्री राम कुमार गौतम: अध्यक्ष महोदय, मैंने बजट पर बोलते हुए अपनी सारी बातें बताई थीं और मैं समझता हूँ कि अगर उन सभी बातों पर गौर कर लिया जाये तो इस स्टेट का कल्याण हो जायेगा और आप लोगों का भी कल्याण हो जायेगा।

Mr. Speaker: Hon'ble Members, who could not participate iii the Discussion on Budget Estimates those Members should be given opportunity. Please co-operate with me. Now, Sh. Subhash Chaudhary will speak.

श्री सुभाष चौधरी (जगाधरी): स्पीकर सर, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। स्पीकर सर, मैं इण्डस्ट्रीज से संबंधित डिमांड पर अपने विचार प्रकट करना चाहता हूँ। मैं मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूँ कि प्रदेश के चहुँमुखी विकास के लिए सरकार ने जो प्रयास किए हैं वे बहुत बेहतरीन हैं हरियाणा की तरक्की के

लिए हैं। सरकार ने प्रदेश के अंदर इण्डस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए जो उद्योग नीति बनाई है उस उद्योग नीति के लागू होने से पूरे हरियाणा में एक उद्योग क्रांति आ जायेगी इससे हरियाणा के हर वर्ग को इसका लाभ पहुँचेगा। जहां पूरे हरियाणा में इण्डस्ट्रीज लगाने के किए सरकार वचनबद्ध है वहीं मैं सरकार का ध्यान अपनी कान्सटीच्यूंसी के शहर जगाधरी की ओर दिलाना चाहता हूँ। यह शहर पूरे देश में एक मशहूर इण्डस्ट्रियल टाऊन है लेकिन आज उस शहर की इण्डस्ट्रीज की हालत बहुत खराब हो चुकी है। सारी इण्डस्ट्रीज बर्बादी के कगार पर खड़ी हुई है। उसका कारण यह है कि दूसरे प्रदेशों में इण्डस्ट्रीज को बहुत भारी बैनीफिट मिल रहा है लेकिन हमारे प्रदेश के अंदर वह बैनीफिट न होने की वजह से इण्डस्ट्रीज बर्बादी के कगार पर खड़ी हुई सैं। मैं सरकार से अनुरोध करूँगा कि जगाधरी शहर की इण्डस्ट्रीज की बर्बादी से बचाने के लिए जिस प्रकार दूसरे प्रदेशों में इण्डस्ट्रीज को सहूलियतें दे रखी हैं उसी तर्ज पर सेल्ज टैक्स में 4 प्रतिशत की बजाए ऐक प्रतिशत की सहूलियत अगर सरकार दे देती है तो इससे इण्डस्ट्रीज को लाभ मिलेगा। मैं सरकार को इस बारे में विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अभी तक जो सेल्ज टैक्स की प्राप्ति जगाधरी की इण्डस्ट्रीज से होती है उसमें किसी प्रकार की गिरावट नहीं आने देंगे। अब मैं एग्रीकल्चर के बारे में कहना चाहूँगा। सरकार ने किसान की तरक्की और एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए पूरे प्रदेश के लिए प्रयास किए हैं। मैं इस ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री जी ने पूएर प्रदेश के अंदर एक

नाम स्थापित किया कि हरियाणा में शूगरकेन का भाव हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा है। इस सिलसिले में मैं सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूँ कि शूगरकेन की एक वैरायटी है सी०ओ०जे० 8436। पंजाब, उत्तरांचल और अपी० के अंदर अरली वैराययई के हिसाब से इसका भाव 13० रुपये प्रति क्विंटल है लेकिन हरियाणा के अंदर इस वैरायटी को भी कैटेगरी में रखा हुआ है जबकि इसको हाई क्लास शुगर यील्डिंग वैरायटी में गिना जाता है 1 मेरा सरकार से अनुरोध है कि यदि हरियाणा में भी इस वैरायटी को अरली वैरायटी में डाला जाये तो इस वैरायटी का लाभ किसानों तक ज्यादा पहुँचेगा। स्पीकर सर, एशिया में यमुनानगर प्लाईवुड इण्डस्ट्रीज का सबसे बड़ा शहर है और उस इण्डस्ट्री का जो री मैटीरियल है वह सफेदा और पापुलर प्लांट हैं। इन प्लांट्स का भाव सरकारें बदलने के साथ–साथ ऊपर–नीचे होता रहता है। मैं हमारे मुख्यमंत्री जी को बधाई दूँगा कि हमारी सरकार बनने के बाद सफेदा और पापुलर प्लांट्स का रेट 4.50 रुपये प्रति क्विंटल दिया गया है जबकि पिछली सरकार के समय में 1.50 रुपये प्रति क्विंटल से अधिक भाव नहीं दिया गया। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूँगा कि सरकारें बदलने के साथ इन प्लांट्स का रेट अधिक ऊपर–नीचे न हो इसलिए इन प्लांट्स को एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में शामिल किया जाये। अब होता क्या है कि इन प्लांट्स को बेचते वक्त कमीशन एजैंट्स को 6 प्रतिशत कमीशन देना पड़ता है इसलिए मैं चाहता हूँ कि इनमें ऐसा प्रावधान किया जाये कि किसानों को कमीशन न देना पड़े

इसलिए इनका स्पोर्ट प्राईस फिक्स किया जाये और इन्हें एग्रीकल्वर प्रोड्यूस में शामिल किया जाये। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार किसानों की भलाई के लिए बहुत से कार्य कर रही है। मेरे हल्के के मुस्तफाबाद शहर में एक प्राईवेट अनाज मण्डी है जिसमें 2.50 लाख क्यिंटल जीरी आती है और एक लाख क्यिंटल गेहूँ आता है। वहां पर कोई सरकारी अनाज मण्डी नहीं है जिसके कारण किसानों को बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूँगा कि मुस्तफाबाद में एक अनाज मण्डी बनवाई जाये ताकि वहां के किसानों का मनोबल बड़े और उन्हें सुविधा भी हो। अध्यक्ष महोदय, अर्बन डिवैल्पमैंट के लिए बहुत पैसा दिया गया है। बहुत अच्छी बात है। मैं मुख्यमंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूँगा कि पिछले बजट सैशन में वित्त मंत्री जी ने on the floor of the House assurance दिया था कि जो भी नगरपालिकाओं का पैसा किसी सरकारी महकमें की तरफ होगा, चाहे पुलिस महकमा हो या दूसरे महकमे डो, वह पैसा नगरपालिकाओं को जल्दी ही दिलवाया जायेगा। नगरपालिका जगाधरी के अंदर पुलिस कम्पलैक्स बना था जिसके डिवैल्पमैंट के 1.82 करोड़ रुपये विभाग की तरफ बकाया हैं। उसके अलावा डिस्ट्रिकट जेल कम्पलैक्स बन रहा है उसके भी डिवैल्पमैंट चार्जिज 292 करोड़ रुपये पुलिस विभाग की तरफ बकाया है। वित्त मंत्री जी ने पिछले बजट सैशन में आश्वासन दिया था उसके बावजूद भी यह पैसा अभी तक नहीं मिला है। मेरा मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि यह पैसा जल्दी से जल्दी नगरपालिका जगाधरी को

दिलवाया जाये ताकि वहां विकास हो सके और वे अपनी दिक्कतें दूर कर सकें। अध्यक्ष महोदय, अब मैं इण्डस्ट्रीज के बारे में जिक्र करना चाहूँगा कि पूरे हरियाणा के अंदर ओद्योगिक क्रांति आ रही है। आई०एम०टी० मानेसर की तर्ज पर प्रदेश में रोहतक, खारखौदा और फरीदाबाद में तीन आई०एम०टी० और बनाये जा रहे हैं। मेरा मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि यमुनानगर इण्डस्ट्रियल एरिया है वहां पर भी एक आई०एम०टी० स्थापित किया जाये ताकि वहां पर इण्डस्ट्री में तरक्की हो और लोगों को रोजगार मिले।

श्री बचन सिंह आर्य (सफीदों): अध्यक्ष महोदय, बजट में दक्षिणी हरियाणा के सदस्यों की तरफ विशेष गौर किया गया है और मध्य हरियाणा की तरफ भी गौर किया गया है जिसमें बेरी, नरवाना, झज्जर और सफीदों क्षेत्र आते हैं इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। कई दिन से बजट सैशन चल रहा है जिसमें हमने बजट पर भी चर्चा की और शहीदों को भी हमने नमन किया है। इसके अतिरिक्त कई बिलों पर भी चर्चा हुई है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, 17 मार्च को बजट पेश हुआ था और इस एक साल की सरकार की अनेकों उपलब्धियों का जिक्र उसमें आया है। मैं इससे सहमत हूँ। एक वर्ष में हरियाणा सरकार ने जो उपलब्धियां प्राप्त की हैं वे सराहनीय हैं। विरोधी पक्ष के लोग केवल विरोध करने के लिए इसका विरोध करते रहे हैं मगर सत्य बात यह है कि बहुत ही सुन्दर बजट हमारे आदरणीय वित्त मंत्री

जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा प्रदेश को दिया है। यह भी सही है कि पिछले काफी लम्बे समय करीब 8–9 वर्ष तक हरियाणा प्रदेश की जनता ने बड़ा दुःख और दर्द सहन किया है। आदरणीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा तथा हरियाणा सरकार ने भयमुक्त प्रशासन हरियाणा प्रदेश को दिया है यह एक बहुत ही सराहनीय कदम है। 1600 करोड़ रुपये के कर्जे माफ करने की बात बार–बार यहां पर आती रही है। अध्यक्ष महोदय, इस समय विपक्ष के भाई यहां पर मौजूद नहीं हैं। इनैलो के सुप्रीमो ने सफीदों के साथ लगते हुए असंध कस्बे में एक बात कही थी। एक शादी में हम भी वहां पर गए हुए थे। असंध के बीच में बहुत बड़ा सैंटर है वहां पर वे एक सभा कर रहे थे। मैंने अपने कानों से इस बात को सुना है कि वे लोगों से यह बात कह रहे थे कि किसान भाईयो बिजली के बिल मत भरना हमारी सरकार आएगी तो मैं सारे कर्जे माफ कर दूँगा। लेकिन अब वे किस मुँह से इस बात से इंकार करते हैं? किसानों के लिए यह एक बहुत बड़ी समस्या बन गई थी लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी दरियादिली दिखा कर एक पुरानी बीमारी का निवारण किया है। एक विशेष बात मैं कहना चाहता हूँ जिसका यहां पर जिक्र नहीं हुआ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के दिल में एक बात थी। जिसके शरीर में स्वतन्त्रता सेनानियों का रक्त संचार कर रहा हो वही व्यक्ति ऐसी बात सोचकर कर सकता है। अध्यक्ष महोदय, शहीदे आजम भगत सिंह और उसके चाचा अजीत सिंह जी का चौपाड के अंदर इतिहास के पन्नों पर पीछे जाएंगे तो अंग्रेजों का

वह समय याद आ जाता है। किसान गरीबी की हालत में कर्जा वापिस नहीं दे सकता। अपनी रिकवरी की अदायगी अगर नहीं कर सकता तो उसको गिरफ्तार करने के लिए कानून बना हुआ था और वे लोग अपनी गाडी या जीप में डालकर किसान को ले जाते थे। शहीद भगत सिंह के गांव में रिकवरी के लिए आते हैं तो वहां के लोग पुलिस अधिकारियों और रिकवरी करने वाले अधिकारियों के कदमों में अपनी पगड़ी डालते हैं और वे अधिकारी उनकी पगड़ी को ठोकर मारता है और उनको गिरफ्तार करके ले जाने की बात करते हैं। कर्जों की अदायगी न कर पाने के कारण बेबसी में किसान की आखों में आँसू आ जाते है। उस काले कानून को खत्म करके आदरणीय चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने जो किसानों की गिरफ्तारी पर रोक लगाई है यह सराहनीय कदम है। भले ही समय के हिसाब से वह रिकवरी होगी। अगर किसान की एक फसल खराब हो जाती थी तो वह कर्ज की अदायगी नहीं कर पाता था लेकिन दूसरी फसल पर रिकवरी की रकम दे देगा। किसान ईमानदार होता है और वह कभी किसी का हक नहीं रखता है। गिरफ्तारी से रू देकर सरकार ने किसान की इज्जत रखी है इसके लिए मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र हैं। औद्योगिक क्रांति भी अपने आप में एक विशेष बात है हरियाणा की जमीन का जो बम्पर रेट किसान को दिया गया है उससे किसान के अंदर बड़ी भारी खुशी की लहर दौड़ गई है। अध्यक्ष महोदय, नहरी पानी का समान वितरण एवं नियोजित वितरण किया है जो कि एक ऐतिहासिक कदम है। हरियाणा सरकार ने और मुख्यमंत्री जी

ने एक बड़ा भारी साहस दिखाकर 18 फरवरी को मेरे विधान सभा क्षेत्र सफीदों में बी०एम०एल० हांसी–बुटाना ब्रांच का शिलान्यास किया था। बड़ी भारी संख्या में वहां पर विशेषतौर से किसान और आसपास के दूसरे लोग इकट्ठे हुए थे। जिस दिन से यह शिलान्यास हो कर काम शुरू हुआ है मैं रोजाना वहां से गुजरता हूँ। इतने समय में यहां पर ऐसा काम होते हुए कभी भी दिखाई नही दिया। कई किलोमीटर नहर बनकर तैयार हो चुकी है और यहां पर कार्य बड़े जोर शोर से चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, जिस दिन इस नहर का पानी आएगा जैसे कि सर छोटू राम जी को किसानों का मसीहा कहा जाता है आने वाले समय में हरियाणा प्रदेश के किसान आदरणीय चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा को भागीरथ का दर्जा देंगे और उनको भागीरथ कहेंगे। जैसे देश की आजादी के लिए भामाशाह का नाम लिया जाता है उन्होंने महाराणा प्रताप की मदद की थी। आज भामाशाह के नाम से हरियाणा में कथा चल रही है। अध्यक्ष महोदय, यहां पर राईस शूट्स की बात चल रही थी। इसकी वजह से हमारे हल्के में किसानों के चेहरे खिल गए थे कि हांसी ब्रांच में सईस शट्स स्वीकृत होंगे। कैप्टन साहब की देखरेख में नहर की खुदाई का काम चल रहा है। मैं यहां पर जिक्र करना चाहूँगा कि वहां पर नहर की खुदाई 17– 18 फुट की गहराई पर चल रही है।। मैं मंत्री जी से पूछना चाहूँगा किं ये वहां पर किस तरह से राईस शट देंगे इस बारे में भी ध्यान दिया जाए। इसके साथ ही मैं मंत्री जी को बताना चाहूँगा कि उसके आसपास के इलाके के पानी का स्तर बहुत नीचे चला गया है और

वहां का पानी खारा है। मुझे पता चला है कि उस नहर को नीचे से कच्चा ही छोड़ा जाएगा। मेरा निवेदन है कि उसको नीचे से भी पक्का कर दिया जाये ताकि लोगों तक मीठा पानी पहुँच सके और वहां के लोगों को फायदा हो। अध्यक्ष महोदय, यहां पर बहुत सी बातों का जिक्र किया गया है और यहां तक कहा गया है कि गन्ने का भाव 135 रुपये होना चाहिए। इसके साथ श्रम नीति, रेणुका और किसाऊ डैम का जिक्र किया गया है। शिक्षा योजना पर बहुत जोर दिया गया है हरिजनों के कल्याण के लिए प्रोग्राम चलाया जा रहा है। बिजली और पानी के समान बंटवारे की बात कही गई है। सड्कों और पुलों के निर्माण एवं रिपेयर आदि के काम किए जाएंगे। इस बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि जब मुख्यमंत्री जी हमारे यहां पर गए थे तो सड्कों के बारे में हमने अपने माँग पत्र में भी जिक्र किया था कृपया मंत्री जी उन सड्कों को बनवाने का कष्ट करें। वे सड़कें इस प्रकार से हैं गोली से मुसलाना, निमनाबाद से मलकपुर, अफताबगढ से रोड़, मुलकपुर से डेराबधावा सिंह, रोड़ से मुआना, अफताबगढ से पाजु खेड़ा, खेमावती से रामपुरा, टोडी खेड़ी से सानपुर और रजानाखुर्द से कालवाट। मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि ये छोटी–छोटी सड़कें हैं इनको जल्दी से बनवाया जाए ताकि किसान मण्डी में अनाज समय पर ले जा सकें। स्पीकर सर, यहां पर पेयजल आपूर्ति में भी वृद्धि का जिक्र किया गया है, मैं आदरणीय पब्लिक हैल्थ मिनिस्टर जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि मेरे हल्के सफीदों में जहां पर 50 सालों से पीने के पानी की समस्या थी वहां पर इन्होंने साढ़े आठ

करोड़ रुपये देकर पीने के पानी की समस्या को दूर करने का प्रावधान किया है। इसके अलावा मुआना और सिंघना गाँव में जहाँ पीने का पानी कडुवा था वहां पर डेढ़ करोड रुपये की योजना चालू करवायी है। इसके साथ ही निमनावाद गाँव है जहां पर टयूबवैल से पीने के पानी की आवश्यकता है उस बारे में काम करने के लिए भी मंत्री जी की मंजूरी की आवश्यकता है। इसी तरह से गरीब लोग। के लिए योजना, महिलाओं के लिए शिक्षा की योजना बनाई गई है। एक आई०एम०टी० भी स्थापित की गई है। इसके साथ ही मैं यहां पर पशुधन के बारे में जिक्र करना चाहूँगा। हमारे बजट में मुर्रा नस्ल की भैंसों के लिए और साहिबा गायों के लिये प्रावधान रखा गया है। अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने जो वृद्ध आश्रम बनाए थे जिनका सदन में भी जिक्र आया है, उन आश्रामों में आप देखेंगे कि गधे, कुत्ते और दूसरे पशु वहां पर बैठते हैं। मेरा इस बारे में यह कहना है कि वहां पर गऊशालाएँ खोल दी जाएं। जो गऊएं गाँवों में अवारा घूमती हैं उनके लिए शरणस्थली बना दी जाए उनके लिए भी बजट में प्रावधान किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं यहा पर पर्यावरण के बारे में कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने पर रोक लगाई हुई है। उसी तरह से हरियाणा सरकार को सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने पर रोक लगानी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आज हम हरियाणा में जगह–जगह पर जब सड्कों और खेतों के पास से गुजरते हैं, पोल्ट्री फार्म बहुत ज्यादा दुर्गंध फैलाते हैं उन पर भी कोई रोक लगनी चाहिए जिससे प्रदूषण से

राहत मिले। जो इस तरह से प्रदूषण फैला रहे हैं उन पर टैक्स लगाया जाना चाहिए क्योंकि ये लोगों की सेहत खराब कर रहे हैं। स्पीकर सर, जिन गऊओं के दूध से लोगों की सेहत बनती है जिनके दूध से, हवा से, पानी से, मूत्र से, लोग ठीक होते हैं उन अवारा गऊओं की देखभाल की तरफ ध्यान देना चाहिए। स्पीकर सर, मैं सदन से और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी प्रार्थना करूँगा कि मार्केटिंग बोर्ड का दस परसैंट मुनाफा इन गऊओं की देखभाल के लिए मदद के लिए रखा जाना चाहिए। कल सदन में स्वास्थ्य संबंधी बातें चल रही थीं। अध्यक्ष महोदय, आप अस्पताल बनाकर बीमारी को रोक तो सकते हैं लेकिन बीमारी को पैदा होने से नहीं रोक सकते। बीमारी पैदा होने से तभी रुकेंगी जब हम अपनी संस्कृति पर, ऋषियों की खोज अपनी गऊ माता पर ध्यान देंगे। अगर हम ऐसा करेंगे तो इस तरह की बीमारी तो अपने आप ही समाप्त हो जाएंगी। स्पीकर सर, आपने मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए आपका बहुत– बहुत धन्यवाद।

श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मान (पाई): स्पीकर सर, वित्त मंत्री जी ने बड़े शायराना अंदाज में महत्वपूर्ण बजट पेश किया है। मैं उसकी सराहना करते हुए कुछ बातों पर सरकार का ध्यान दिलाना चाहूँगा। बिजली जैनरेशन के ऊपर बजट में बड़ी भारी ऐलोकेशन की गयी है और सभी लोग इससे बड़े खुश भी हैं। मुख्यमंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं मेरा उनको एक सुझाव है कि हमारा जो ट्रांसमिशन सिस्टम है वह बहुत पुराना हो गया है। यह ठीक है कि

राजीव गांधी ग्रामीण योजना के अंदर 700 करोड़ रुपये हमें भारत सरकार से मिलने जा रहे हैं लेकिन जो अलग–अलग एरियाज हैं, बैकवर्ड एरियाज हैं जिनमें मेरा हल्का पाई भी शामिल है उनमें सभी ताते, सभी बिजली के खम्भों की बहुत बुरी हालत है। स्पीकर सर, मैं धन्यवादी हूँ सरकार का कि उसने मेरे हल्के में तीन सब–स्टेशन बनाने की अनुमति दी है लेकिन मैं यह सुझाव भी दूँगा कि ऐसा न हो कि हम जैनरेशन तो कर दें लेकिन उसको कैरी करने के लिए हमारे पास ट्रांसमिशन लाईन पुअर हों। इसलिए इससे पहले कि हमारी पावर जैनरेट हो, सारे सिस्टम को ओवरहाल करके इस काबिल बनाया जाए कि जो पावर जैनरेट हो उसका हम अपने क्षेंत्रों में, अपने, सोर हरियाणा प्रदेश के अंदर ठीक ढंग से पूरी तरह से सजाई कर नफे। इसी तरह से एक सामूहिक समस्या सारे सर्विस सैक्टर की है। चाहे पब्लिक हैल्थ हो, चाहे बिजली हो या कोई दूसरा सैक्टर हो, हर जगह यह दिक्कत है। एक तरफ सरकार करोड़ों रुपये खर्च करके अपनी योजनाएं चला रही है, अपने स्ट्रक्चर को मजबूत कर रही है वहीं दूसरी तरफ क्लास फोर्थ या दूसरे इम्पलाईज हैं जो इनको आपरेट करते हैं उनकी बड़ी कमी है। जब–जब भी कभी किसी काम के लिए स्थानीय अधिकारियों को कहते हैं तो उनका यही कहना होता है कि सरकार ने इनकी भर्ती पर रोक लगायी हुई है इसलिये इन कर्मचारियों की कमी है। सरकार अपनी योजनाओं पर करोड़ों रुपये खर्च करें लेकिन उनको निचले लेवल पर चलाने के लिए स्टाफ न हो तो फिर समस्या ही बनी रहेगी। पब्लिक हैल्थ

डिपार्टमैंट की वाटर वर्क्स स्कीम के लिए जब बिजली ही तीन घंटे आये तो तीन–तीन जगह पर जाकर आपरेटर कैसे उसको आपरेट कर सकता है यह संभव ही नहीं है। बहुत अच्छी स्कीम्स सरकार ने बनायी हैं। गैस्ट टीचर लगाने की स्कीम सरकार ने बनायी और सारे स्कूलों के अंदर 15– 15 दिन के लिये टीचर भेज दिये लेकिन इससे बात नहीं बन पायी 1 मेरा सुझाव है कि सरकार की नियुक्तियों में तो बड़ी भारी परेशानी है क्योंकि कभी कोर्ट का स्टे आ जाता है या कभी कोई और दिक्कत आ जाती है। जब तक नियुक्ति न हों तब तक लोकल ऐडमिनिस्ट्रेशन को इजाजत दे दी जाये कि जो महत्त्वपूर्ण सर्विस सैक्टर्ज हैं उनके अंदर क्लास फोर्थ इम्पलाईज वे रख लें। स्पीकर सर, राजौंद सब–स्टेशन में एक एस०डी०ओ० है हम उसको किसी काम के लिए कहते हैं तो वह कह देता है कि यह काम होना बड़ा मुश्किल है हम उससे कहते हैं कि क्यों तो वह कहता है कि मेरे पास सिर्फ 18 आदमी हैं और उनमें से भी 14 आदमी अत्यन्त शराबी हैं। वे बिजली के पोल पर नहीं चढ़ सकते हैं और मुझे नये आदमी लगाने का अधिकार नहीं है इसलिए आपके काम करवाने बड़े मुश्किल हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि जब तक सरकार की तरफ से नियुक्तियां नहीं हो जाती तब तक छोटे स्तर पर जो कर्मचारी हैं जोकि सरकारी योजनाओं को आम आदमी तक पहुँचाते हैं, उनकी भर्ती का अधिकार लोकल अधिकारियों को दिया जाये ताकि सर्विस सैक्टर के अंदर एफीशिएंसी आए और सरकार की जो इतनी भयंकर इन्वेस्टमेंट हैं उनका लाभ गरीब आदमी को

मिले। स्पीकर सर, हरियाणा में सड्कों का इन्फ्रास्ट्रकचर बहुत बढ़िया तरीके से तैयार हुआ है। बजट में भी सड्कों को रिपेयर करने का, नई सड़क बनाने का प्रावधान किया गया है। लेकिन हमारे जो पाँच–छः जिले हैं जिनको मन हरियाणा कहते हैं wherever there are more producing areas and wherever there are intensive producing areas. इन एरियाज में हरियाणा की अधिकतर 60–70 प्रतिशत पैडी, गेहूँ और गन्ने की पैदावार होती है। वहां पर शुगर मिल भी लगी हुई हैं। हमारे इलाके कैथल, जींद में ज्यादातर जो सॉयल की क्यालिटी है वह इस प्रकार की है कि कच्चे रास्ते से ज्यादा वजन के साथ बुग्गी और ट्रक नहीं चल सकता और यही कारण है कि कैथल की जो शूगर मिल है वह आज तक फेल है क्योंकि जितना गन्ना उस मिल को चाहिये उतना गन्ना वहां नहीं पहुँचता। वे ही किसान जिनके खेत पक्की सड़क से जुड़े हुये हैं उस मिल को गन्ना पहुँचाते हैं। छोटे–छोटे किसान जिनके पास थोड़ा गन्ना होता है वही उस मिल में गन्ना पहुँचाते हैं। जिन खेतों के कच्चे रास्ते होते हैं उन खेतों में किसान गन्ना नहीं लगा पाते। मेरा सुझाव है कि बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर आपके पास है सरकार के कोफर्स भरे पड़े हुये हैं, इसलिए सरकार को चाहिये कि जो सड़कें एक गा।व से दूसरे गाँव को जोड़ती हैं और किसानों के लिये हर प्रकार से इस्तेमाल होती हैं उन सड्कों की हालत ठीक की जाये। जिन जगहों पर प्रोड्यूस ही बहुत कम है वहां सड्कों की इतनी जरूरत नहीं है जितनी हमारे इलाके में हैं। कई सड़कों को ठीक करने की माँग

मैंने मुख्यमंत्री महोदय के माध्यम से मार्किटिंग बोर्ड को भेजी है और मुझे पूरी आशा है कि उनको पूरा करने पर गार किया जायेगा और उन सड्कों को बनाया जायेगा। मुख्यमंत्री महोदय, 3–4 प्रकार के वाहन सड्कों पर चलते हैं इनमें थी व्हीलर, जीप, प्राईवेट बसिंज और परिवहन की बसें होती हैं। आज हरियाणा परिवहन की बसिज हिन्दुस्तान में नम्बर एक पर हैं इसके लिए हरियाणा सरकार बधाई की पात्र है। लेकिन जो दूसरे प्राईवेट वाहन जैसे जीप या प्राईवेट बसिज हैं उनकी तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिये। जीपों की या थी व्हीलर्ज की वायबिलिटी देखनी चाहिये क्योंकि यह एक सोशल प्रोब्लम है। गाँव–गाँव में बेशुमार गाड़ियां खड़ी हैं, बेशुमार थी व्हीलर्ज खड़े हैं, इनके लिए कोई न कोई नीति सरकार द्वारा बनाई जाये ताकि बड़ी सरलता के साथ, थोड़े टैक्स के साथ वे वाहन वायेबल भी हों और गरीब बच्चों को तथा गाँव के बच्चों को एक रोजगार का अवसर भी प्राप्त हो। मेरे पाई हल्के के लिए पब्लिक हेल्थ के बजट में सरकार ने काफी एलोकेशन की है।

Mr. Speaker: Mann Sahib, you may please conclude.

श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मानः अध्यक्ष महोदय, ऐसा तो न करो, पब्लिक हैल्थ के कई इन्फ्रास्ट्रक्चर बहुत खराब हैं उनको ठीक करने की इजाजत दी जाये। स्पीकर सर, मुख्यमंत्री जी बैठे हुये हैं जैसा कि सुरजेवाला जी ने भी मांग की थी और मैं

समझता हूँ कि परमेश्वर की कृपा से बारिश होने के कारण अब तो गेहूँ की फसल की पैदावार बढ़ेगी लेकिन पिछले सालों से बहुत कम ही रहेगी क्योंकि पूरी फसल के समय में मौसम की कोई बारिश नहीं हुई। हरियाणा सरकार के कोफर भरे पड़े हैं और हरियाणा सरकार की वित्तीय स्थिति भी काफी अच्छी है इसलिये यदि मुख्यमंत्री जी चाहें तो वे गेहूँ की फसल का किसानों –को अच्छा भाव दिला सकते हैं। सरकार की कोशिश होनी चाहिये कि गेहूँ का भाव 700–750 रुपये प्रति क्विंटल दिलाया जाये। अगर ऐसा नहीं होगा तो किसान के खर्चे की भरपाई नहीं होगी। अगर केन्द्र सरकार इतना भाव तय नहीं करती है तो हरियाणा सरकार की अपनी वित्तीय स्थिति अच्छी है, वह अपनी तरफ से कोई न कोई बोनस किसान को दे सकती है। स्पीकर सर, ऐसा मेरा सरकार से आग्रह है। अब मैं एनीमिल हैस्वैण्डरी के बारे में कहना चाहूँगा। गाँवों में आधे किसान जानवरों का पालन–पोषण करते हैं इसलिए मेरा अनुरोध है कि इसके लिये वहां पर इनका नेटवर्क अच्छा बनाया जाये। डिसपैंसरी के अन्दर डॉक्टर से नीचे का स्टाफ उपलब्ध नहीं है इसलिए मेरा कहना है कि उनकी भर्ती जल्दी से जल्दी की जाए। जब तक इनकी भर्ती नहीं हो जाती तब तक टैम्परेरी स्टाफ लगवाने का प्रावधान किया जाये क्योंकि इससे सरकार की एफिशिएसी भी बढ़ेगी और किसानों में तथा गरीब आदमियों में सरकार की गुडविल भी अच्छी होगी। बी०ओ०टी० बेसिस पर यमुना के बराबर–बराबर सड़क बनाने की सरकार द्वारा योजना बनाई गई थी। उसके टैंडर भी लिये गये थे। अध्यक्ष

महोदय, यमुनानगर से वाया करनाल होते हुये दिल्ली रोड पर बहुत बड़ा ट्रेफिक जाम लगा रहता है। यदि हमारी सरकार उसको पुराने मसौदे पर बी०ओ०टी० बेसिज पर बनायेगी तो उससे प्रदेश को बहुत फायदा होगा। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा कल यहां सदने में सुनने को मिला कि गुड़गांव के अंदर नाईट्रोजन गैस का लैवल बहुत अधिक हो गया है। मैं समझता हूं कि यह अभी तो हमारे लिये एक चेतावनी है, अभी इससे ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन इसकी तरफ समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में यह समस्या हमारे लिये बहुत बड़ी समस्या हो जायेगी। यदि हम गुड़गांव और इसी तरह के दूसरे शहरों की तरफ ध्यान देते रह कि कालोनाईजेशन, माल्ट, इण्डस्ट्रीज आदि इन्हीं शहरों में लगाते रहे तो यह समस्या बहुत गम्भीर हो जायेगी। इस बारे में मेरा सरकार से अनुरोध है कि जो दिल्ली से दूर–दराज के एरियाज हैं उनकी तरफ भी सरकार ध्यान दे और वहां इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवैल्प किया जाये ताकि लोग अपने आप वहां आयें। जींद और कैथल आदि शहरों में हम जो चाहें वह बना सकते है। वहां जमीन भी सस्ती मिलेगी। यदि वहां इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करवा देंगे तो लोग अपने आप वहां आयेंगे।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं शिक्षा के बारे में कुछ बातें कहना चाहूँगा कि हमारी सरकार ने स्कूलों में पढ़ाई का माहौल ठीक करने के लिये बहुत पैसा खर्च किया है इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को और शिक्षा मंत्री जी को मुबारकबाद देता हूँ।

बच्चों की पढ़ाई बेहतर हो उसके लिये सरकार ने गैस्ट टीचर्स लगाये और टीचर्स की कमी को पूरा किया। इसके अतिरिक्त चौटाला जी की सरकार के समय जो टीचरों की भर्ती गलत तरीके से की गई थी मैं चाहूँगा कि उन पर जल्दी से जल्दी कार्यवाही की जाये। अध्यक्ष महोदय, हैल्थ के बारे में भी काफी चर्चा हुई है और बजट में भी काफी प्रावधान किये गये हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से और हैल्थ मंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि मेरे हल्के के अंदर तीन पी०एच०सी० बनायी जानी हैं, वे जल्दी से जल्दी बनवायी जायें।

अब मैं सोशल वैलफेयर के बारे में कहना चाहूँगा कि सोशल वैलफेयर के लिये 40 करोड़ रुपये बढ़ाया गया है, यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसमें सोचने वाली बात यह है कि इनकी मोनीटरिंग सही नहीं है। जो हमारे फील्ड के अंदर वैलफेयर आफिसर हैं हम उनको नहीं जानते। सच कहूं तो हमारे डी०सीज० को भी बहुत से अधिकारियों की शक्ल नहीं मालूम। मौत होने के बाद जो एक लाख रुपये अनुदान का मिलता है मेरे हल्के की मार्किट कमेटी में तीन–तीन साल से ऐसे केस पड़े हैं कि मौत होने के बाद संबंधित परिवारों को एक लाख रुपये की राशि अभी तक नहीं मिली है। इसके अतिरिक्त लाडली स्कीम या कोई इस तरह की जो दूसरी स्कीम्स हैं उनका लाभ भी सही ढंग से नहीं मिल रहा है। जो वहां पर अधिकारी लगे हुये हैं वे किसी की बात सुनते नहीं हैं। इसलिये मेरी मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना है कि इसका स्ट्रैक्चर अच्छा बनाया जाये और किसी सीनियर अधिकारी के जिम्मे

ये कार्य अलग से लगाये जायें। जो चौटाला ने अपनी सरकार के समय में अपने नाम के बोर्ड जगह–जगह पर प्रदेश में लगाये थे वे बोर्ड अब ऐसे ही पड़े हुये हैं। उन पर जो भी सोशल वैलफेयर की स्कीम हैं, लिखी जायें और लोगों को इनकी पूरी जानकारी दी जाये। (विघन)

श्री अध्यक्षः मान साहब, प्लीज अब आप बैठें।

श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मानः अध्यक्ष महोदय, मैंने एक दो बातें बहुत जरूरी कहनी हैं कि बेरोजगारी भत्ते में भी बहुत नौंकझोंक हैं। बहुत अधिक पैरामीटर बनाये हुये हैं। मैं सरकार से अनुरोध करूँगा कि जब तक हम बेरोजगारों को नौकरियां नहीं दे सकते तब तक उनको बेरोजगारी भत्ता उदारता के साथ दिया जायेगा तो बहुत अच्छा होगा। (विघन)

श्री अध्यक्षः मान साहब, प्लीज, अब आप बैठें। अब भूपेन्द्र सिंह चौधरी जी बोलेंगे।

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी (पटौदी, एस०सी०): अध्यक्ष महोदय आपने मुझे चर्चा में भाग लेने के लिये समय दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। लेकिन मैंने एक शोर्ट डिस्कशन नोटिस दिया था वह आपने रद्द कर दिया।

श्री अध्यक्षः आपका क्या नोटिस था? उसके बारे में आप अब बात कर लें।

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी: अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के के गाँव बाँस पदमका में पशुओं में एक बहुत भयंकर बीमारी फैल गया थी। वह बीमारी इस कदर फैली कि गाँव में तकरीबन 50 भैंसे मर गई और वहां पर काफी हा—हा कार मचा 1 स्टेट से भी टीम वहां पर गई और सैंटर से भी टीम गई थी। मैं चाहता था कि उस विषय पर डिस्कशन हो कि वह क्या बीमारी थी, सरकार ने क्या प्रिवैंटिव मैयर्ज लिये हैं और डेयरी के ऊपर जो लोग निर्भर थे उनको सरकार क्या कम्पनशेसन दे रही है? मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ और सरकार का ध्यान इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूँ कि इसके बारे में जो रिपोर्ट आई है उस पर सरकार जरूर गौर करे। जिन ग्रामीण लोगों ने इसके कारण सफर किया है उन प्रभावित लोगों को कम्पनशेसन भी दिया जाये। यह बीमारी आगे न फैले इस बात का खासतौर पर ध्यान रखें क्योंकि बर्ड क्यू ने पहले ही लोगों में काफी आतंक मचाया हुआ है। अगर इस तरह की बीमारी पशुओं में और फैल गई तो आप समझ सकते हैं कि क्या पोजीशन हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ हमें सरकार का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूँ कि गुड़गांव के अंदर जमीनों के भाव काफी बढ़ चुके हैं और लैण्ड माफिया वहां पर काफी सक्रिय हो चुका है। पचातयों की जो लैण्ड हैं और उसकी खरीद फरोख्त चल रही है। यह मुद्दा मीडिया ने भी उठाया कि मेरी कांस्टीच्यूएंसी के अंदर बास मुसेदपुर एक विलेज है जिसकी 110 एकड लैण्ड की मुटेशन चेंज हुई और जब हमने उसका प्रोटैस्ट किया, ज्ञापन दिया तो उसमें नायब तहसीलदार

और पटवारी सस्पेंड हुए। इसी तरह से एक पटवारी बाबूपुर जहाजगढ की जमीन के मामले में भी सस्पैंड हुआ था लेकिन जो भी अधिकारी सस्पैंड हो जाते हैं इन्क्वायरी होने से पहले ही वे बहाल हो जाते हैं और इस तरह की साजिश फिर आगे चलती रहती है। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान इस बात की तरफ जरूर दिलाना चाहता हूँ कि कई गाँवों मे पंचायती लैंड 200 एकड़ है और कई गाँवों में 100 एकड़ है लेकिन एक ओर लैण्ड माफिया इतना सक्रिय है कि उस लैण्ड को हड़पने के लिये गाँवों में दहशत का माहौल पैदा कर देता है और लोग समझते हैं कि सरकार इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि इस बात पर सरकार सदन में भी आश्वासन दे कि पंचायती लैण्ड की किसी भी तरह से खरीद फरोख्त नहीं होगी।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि सरकार जो पैसा पब्लिक हैल्थ के जरिये सीवर तथा ऐमिनिटीज पर खर्च करती है उस फण्ड के बारे में वहां के लोकल एम०एल०ए० को भी यह पता नहीं होता कि वहां पर कितना पैसा मिला है और कितना काम हुआ है। होस्पीटल की बिल्डिंग की रिपेयर के लिये और दूसरी चीजों पर कितना पैसा खर्च हुआ। उसमें से काफी पैसा ऐसे ही खुर्द–बुर्द हो जाता है और एम०एल०ए० देखता है कि वहां पर कोई रिपेयर हुई ही नहीं और बिल तकरीबन बनते जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, काफी जगह पर यह बात नोटिस में आई है।

होस्पीटल्ज के अंदर स्टाफ की बहुत ज्यादा शर्टिज है। कई जगह ऐसी हालत हैं कि कहना मुश्किल है। एक इन्सपैक्शन में मैं होस्पीटल में चला गया वहां पर सिर्फ एक ही डॉक्टर ड्यूटी पर मिला बाकी सारे डॉक्टर्ज नदारद थे। वे लोग हाजरी लगाते हैं और सुबह ही चले जाते हैं। सरकार द्वारा हैल्थ डिपार्टमैंट के बारे में काफी विचार हुआ है लेकिन सरकार को इस मामले में सक्रिय होना चाहिए। हैल्थ कैं मामले में जो भी डॉक्टर्ज ड्यूटी पर हों कम से कम वे परमानैंट ड्यूटी दें। मैं सरकार का ध्यान इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूँ कि एक पार्टी में मैं गया था और उस पार्टी में कई डाक्टर्ज मौजूद थे। पार्टी के बाद चलते–चलते यह बात आई तो डॉक्टर कहने लगे कि आजकल बहुत मन्दा चल रहा है। इस किस्म के जो डॉक्टर्ज हैं इनको बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। जब वे इस पेशे में आये हैं तो कम से कम सेवा करने की भावना उनमें जरूर होनी चाहिये। इस प्रकार का माहौल होस्पीटल्ज में बनाया जाये कि वे बीमारों की सेवा के लिये काम कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, सरकार से मेरा निवेदन है कि उनको कहा जाये कि सेवा की भावना हर डॉक्टर के अन्दर होनी चाहिये। अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता था। आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री सोमवीर सिंह (लोहारू): स्पीकर सर, आपने मुझे बोलने के लिये मौका दिया आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। हरियाणा के अन्दर कांग्रेस पार्टी की सरकार बने तकरीबन एक साल ही

हुआ है और जिन हालात में सरकार को यह स्टेट मिली थी उसको सुधारने के लिये एक साल का समय कोई बहुत ज्यादा नहीं है। स्टेट की हालत में जिस तरह से सुधार किया गया है वह बहुत ही सराहनीय और काबिले तारीफ है। जो बजट 17 तारीख को पेश किया गया उसमें सिर्फ 65 करोड रुपये का घाटा दिखाया गया है जो कि कण्ट्रोलेबल कण्डीशन के अंदर है। अध्यक्ष महोदय मै आपसे यह अर्ज करना चाहूँगा कि हर वर्ग की भलाई के लिये चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे एजूकेशन की बात हो, सरकार ने काफी पैसे का प्रावधान किया है और सुधार भी सरकार ने बहुत किये हैं। स्पीकर सर, सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है, वह कानून व्यवस्था को सुधारने की है। पिछले पाँच–छः साल के अंदर कानून व्यवस्था की जो हालत थी, डर का जो माहौल था, उसको सरकार ने सुधारा है। आज दूसरे प्रदेशों में भी इसका उदहारण पेश किया जाता है। किसानों की भलाई के लिये सरकार ने जो काम किये हैं वह सराहना के काबिल हैं। इससे हमारे डिस्ट्रिक्ट में बहुत फायदा हुआ है। हमारे यहां सिवानी में सबसे बड़ी समस्या बिजली की थी। पिछली सरकार के समय में और उससे पहले भी चौटाला सरकार यह कहती थी कि लोगों हमें मौका दो हम आपको 24 घंटे बिजली देंगे। उस वक्त उन्होंने लोगों को गुमराह किया था और जब उनका राज आ गया तो इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया था। इन सब चीजों के बावजूद जब कि हमने कोई वायदा नहीं करा था हमारी सरकार ने किसानों के बिजली के बिलों के 1600 करोड़ रुपये माफ कर दिये हैं।

सरकार की इस घोषणा के मुताबिक मेरे हल्के के कम से कम 90 प्रतिशत किसान बिजली का बिल ईमानदारी से भर रहे हैं। जो किसान अभी भी बिल नहीं भर रहे हैं उनको सरकार बार–बार मौका दे रही है। इस सरकार ने गन्ने के और जमीनों के भाव निश्चित करे हैं। किसानों के लिये सोसाईटी के माध्यम से एक प्रतिशत ऋण की माफी दी है, रजिस्ट्रेशन फीस भी माफ की गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी ने पाँच तारीख को घोषणा की है कि जिन किसानों की गिरफ्तारी रिकवरी के लिये की जाती थी वह नहीं की जायेगी। जहां तक नहरों में पानी के समान बंटवारे की बात है तो इसमें हमारे क्षेत्र को बहुत फायदा हुआ है। मंत्री जी ने कहा था कि हम दक्षिणी हरियाणा को भी पानी देंगे 1 इस बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि मेरी कांस्टीचूएंसी में जहां पहले पानी नहीं आता था अब की बार वहां पर पहले से बहुत ज्यादा पानी आया है। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि जिन नहरों के आखिरी छोरों पर सफाई नहीं हुई है वहां पर सफाई करवाई जाए जिसकी वजह से टेलों पर पानी पहुँच सके। मंत्री जी स्वयं वहां पर जाकर देखकर आए हैं कि लोग वहां पर पाने के पानी के आने का इंताजर कर रहे हैं। अगर मंत्री जी वहां पर नहरों की टेल तक पानो पहुँचाएंगे तो लोगों की इस सरकार से जो उम्मीद थी वह उनकी उम्मीद पूरी हो जाएगी। अध्यक्ष महोदय, यह जो दक्षिणी हरियाणा के लिये 260 करोड़ रुपये की लागत से नहर बनाई जा रही है इससे हमें बहुत फायदा होगा। इस सरकार द्वारा टैम्परेरी गैस्ट टीचर्ज भर्ती किए गए हैं, शिक्षा का स्तर ऊँचा उठाने के

लिये राजीव गांधी एजुकेशन सिटी कुण्डली में स्थापित कर रहे हैं। इसके अलावा जींद में कालेज स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा स्वतन्त्रता सेनानियों के लिये पैंशन योजना शुरू की गयी है। परिवहन में और ज्यादा सुविधाएं देने की बात कही गई है। पिछले साल 500 बसें नई चलाई गईं थीं और इस साल और नई बसें चलाई जाएंगी। अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष को बालिका दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, औरतों को सुविधाएं देने के लिए प्रोग्राम बनाए गए हैं और यह जो लिंग अनुपात में गिरावट आई है उसको कम करने के लिए भी इस सरकार की तरफ से काम किया जा रहा है। मैं तो यह कहता हूँ कि यह बहुत ही अच्छा कदम सरकार का है और इससे लड़कियों की संख्या में कमी आ गई थी वह ठीक हो जाएगी।

इसी तरह से मैं कृषि के बारे में कहना चाहूँगा कि कृषि के क्षेत्र में सरसों और चने की फसलों को बीमा योजना में शामिल करके किसानों को बहुत प्रोत्साहन दिया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं खेती के बारे में जिक्र करना चाहूंगा कि मेरी कांस्टीचूएंसी लौहारू और जिला भिवानी तथा महेन्द्रगढ़ में चने और सरसों की फसल बोई जाती थी लेकिन वहां पर सरसों के पौधे में जहां से उसकी जड़ शुरू होती है वहां पर से एक पौधा और निकलना शुरू हो जाता है। इस पौधे को दूसरी जगह किसी और नाम से पुकारा जाता है लेकिन हमारे यहां पर उसे मरमौदा कहते हैं। अगर उस पौधे को जड़ से उखाडो तो वहां पर उसके

ज्यादा संख्या में पौधे पैदा हो जाते हैं। मुख्यमंत्री जी, आप अपनी यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों से कहकर इस बारे में कोई प्रबंध करें ताकि इस बीमारी से लोगों को छुटकारा मिल सके। अध्यक्ष महोदय, जहां पर एक एकड में 25 मन फसल पैदा होती थी वहा पर अब सिर्फ 8 मन फसल ही पैदा होती है। आज वहां पर अगर किसान गेहूँ की फसल बोते हैं तो वह फसल इतनी अच्छी नहीं होती है। मेरा निवेदन है कि इस बात पर भी ध्यान दिया जाए कि सरसों की फसल के अंदर जो उस पौधे से नुकसान हो रहा है उसको कैसे खत्म किया जाये?

श्री अध्यक्षः सोमवीर जी, आप कच्छ करें।

श्री सोमवीर सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं अब अपनी कांस्टीच्यूएंसी की बात कहना चाहता हूँ। हमारा एरिया बिलकुल लास्ट में बोर्डर का एरिया है वहां पर सबसे बड़ी प्राब्लम स्टाफ की है। चाहे कोई भी महकमा हो, सबमें स्टाफ की बड़ी भारी कमी है। चाहे एजुकेशन का महकमा हो, चाहे पब्लिक हैल्थ का महकमा हो, चाहे हैल्थ का महकमा हो, सबमें स्टाफ की कमी है। चाहे लोहारू का कॉलेज हो, चाहे पोलिटैक्निक कॉलेज हो, इनमें स्टाफ की बहुत कमी है। मैं सरकार से निवेदन करूँगा कि अगले महीने जब ट्रांसफर की जाएं तो वहां पर स्टाफ की कमी को पूरा किया जाए। इसी तरह से बहल के अंदर सब तहसील की बिल्डिंग की कमी है इसलिए मेरा निवेदन है कि वहां तहसील ओफिस का निर्माण करवाया जाये। इसके लिये वहां पर पंचायत जमीन देने के लिये

तैयार भी है। इसी तरह से पब्लिक हैल्थ विभाग की बात मैं कहना चाहता हूँ। हमारे यहां पर दो सब डिवीजन बहल और लोहारू पड़ती हैं वहां पर तीन—तीन जे०ईज० की पोस्टस हैं लेकिन वहां पर एक ही जे०ई० रहता है। मेरा सरकार से निवेदन है कि हमारे इलाके में गाँवों के अंदर जो ट्यूबवैल्ज हैं उनको चलाने वाले कर्मचारियों की बहुत कमी है इसलिए अधिकारियों को वहां पर इस तरह का सिस्टम करना चाहिये कि गाँवों के लोगों को ही या दूसरे लोगों को ठेके पर यह काम देने का सिस्टम किया जाये ताकि यह दिक्कत न रहे। अगर यह ट्यूबवैल एक आम आदमी चलाता है तो वह इनको ठीक नहीं चला सकता है और इनके जलने का खतरा रहता है उसको पता ही नहीं होता कि बिजली दौ फेज की आ रहीं हें या तीन फेज की आ रही है। इसलिए मैं चाहूँगा कि इस काम के लिए ठेका सिस्टम दिया जाए या कोई और सिस्टम दिया जाए ताकि इन ट्यूबवैल्ज को चलाने के लिये सही आदमी मिल सकें।

स्पीकर सर, इसी तरह हैल्थ डिपार्टमैंट का भी मैं जिक्र करना चाहूँगा। मेरी कांस्टीच्यूएंसी के अंदर 5—6 जगहों पर पी०एच०सीज० हैं और एक लोहारू में सी०एच०सी० है लेकिन किसी भी जगह पर सैक्यशड में से आधा स्टाफ भी नहीं है इसलिये मेरा निवेदन है कि उनमें भी स्टाफ की भर्ती की जाये। स्पीकर सर, मेरे क्षेत्र में ढिगाणा एक बहुत बड़ा गाँव है वहां पर भी एक पी०एच०सी० का निर्माण करवाया जाये क्योंकि वहां पर

आसपास तक कोई भी पी०एच०सी० नहीं है। इसी तरह से सिवानी के एरिया का भी मैं जिक्र करना चाहूँगा। जैसे हमारी सरकार ने बिजली के 1600 करोड़ रुपये माफ कर दिये यह बहुत अच्छी बात है लेकिन मैं एक और निवेदन करना चाहूँगा कि उस एरिया में पिछले सात–आठ साल से लगातार अकाल पड़ रहा है इसलिये वहां पर पशुओं के चारे की बहुत कमी है हालांकि चारा दिया गया है लेकिन फिर भी बड़ी भारी कमी है। इसलिये मेरा निवेदन है कि वहां पर पशुओं के चारे की आपूर्ति की जाये। इसी तरह से वहां पर कोई और उद्योग लगाया जाये ताकि वहां के लोगों को काम मिल सके। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया, इसके लिये आपका धन्यवाद।

प्रो० दिनेश कौशिक (पुण्डरी): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने हमें बोलने के लिये समय दिया। वैसे तो मैं बजट पर बोलना चाहता था लेकिन उस समय शायद इतना समय नहीं था।

श्री अध्यक्ष: कौशिक साहब, यह भी बजट ही है ऐप्रोप्रिएशन बिल भी बजट ही होता है आप इस पर अपनी बात कह सकते हैं।

12.00 बजे

प्रो० दिनेश कौशिक: ठीक है सर। स्पीकर सर, मैं मुख्यमंत्री जी का और वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा

कि उन्होंने इतना अच्छा बजट पेश किया है। आप चाहे कहीं जाएं पूरे स्टेट के अंदर विकास के कार्यो की झड़ी लगी हुई है। चारों तरफ विकास के कार्य हो रहे हैं। चाहे वह कालोनार्ईजेशन हो, चाहे उद्योग हो या चाहे कोई दूसरा सैक्टर हो, हर जगह पर विकास के कार्य हो रहे हैं। आज अगर हम गाँवों में जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहां पर नालियां बन रही हैं, सड़कें चौडी हो रही हैं यानी हर तरफ कार्य हो रहे हैं। पिछले एक साल से मुख्यमंत्री जी ने विकास के कार्यों की झड़ी लगायी है। मुख्यमंत्री जी ने इस वर्ष को बालिका वर्ष के रूप में मनाने की बात कही है जोकि निःसंदेह बहुत ही सराहनीय है। हम बालिका वर्ष के रूप में जो इस साल को मना रहे हैं तो निश्चित रूप से इसमें गरीब लोगों को बहुत फायदा होने जा रहा है। इसके लिये जो कंडीशन है पीले कार्ड की। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूँगा कि पीले कार्ड का लाभ जो गरीब आदमी को मिलना चाहिये वह नहीं मिल रहा है। जब तक ये पीले कार्ड बनेंगे तब तक यह वर्ष बीत जायेगा। मैं सरकार सै अनुरोध करना चाहूँगा कि इस वर्ष के लिये पीले कार्ड से छूट दे दी जाये। इसी प्रकार से यह वर्ष बालिका वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है और लाडली नाम की जो स्कीम है इससे सबको लाभ मिलेगा। जो भी हमारी प्राईवेट संस्थाएं हैं उनको भी इस बारे में एनक्रेज किया जाये ताकि जो हमारी बेटियां 18 साल से ऊपर हो चुकी हैं, उनकी शादियों में वे संस्थाएं मदद कर सकें। इसके लिए पीले कार्ड की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैंने देखा है कि कई प्राईवेट संस्थाए सामूहिक शादियां

करवाता हैं, 100–200 शादियां इकट्ठी होती हैं, ये संस्थाएं उनमें 11 – 11 हजार रुपये का कन्यादान करती हैं। अगर ऐसा प्रावधान सरकार की तरफ से हो जाये कि किसी भी गरीब आदमी की बेटी जो 18 साल से ऊपर की हो गई है उनकी सामूहिक शादियां हों और सरकार की तरफ से उनका कन्यादान किया जाये तो बहुत अच्छा रहेगा। नगरपालिकाओं की स्थिति के बारे में कई साथी बोल चुके हैं इसलिए मैं इस बात को दोहराना नहीं चाहता। अर्बनाईजेशन पूरे स्टेट में जोरों पर है। उद्योग बड़े–बड़े शहरों की तरफ बढ रहे हैं 1 मैं वित्त मंत्री जी से इस बारे में एक चिन्ता जताना चाहता हूँ कि सभी कॉलोनाईजर्स हमारे कैथल, कुरुक्षेत्र और जीन्द के शहरों की तरफ सस्ती जमीन खरीदने में लगे हुए हैं क्योंकि गुड़गांव और फरीदाबाद में तो एक एकड़ जमीन का भाव एक करोड़ 23 लाख के करीब पहुँच गया है जबकि हमारे क्षेत्र में अभी जमीन के भाव कम हैं 1 किसान लालच में आकर जमीन को बेच रहे हैं जिसके कारण किसान भूमिहीन होते जा रहे हैं। इसलिये इसके लिये भी सरकार को कुछ सोचना चाहिये।

इसी प्रकार से जो एस०ई०जैड० की योजना सरकार की है और इसकी जो लिस्ट है उसमें यह स्कीम बड़े–बड़े शहरों में लगाने का प्रावधान दिखाया गया है। गुड़गांव, फरीदाबाद और जी०टी० रोड के साथ लगते जो शहर हैं वे तो पहले से ही औद्योगिक नगर हैं। कैथल, कुरुक्षेत्र और जीन्द में एस०ई०जैड० की योजना को नहीं रखा गया है। इस प्रकार का

इण्डस्ट्रलाईजेशन यदि जिस इलाके में होता है तो नौकरियां भी उसी इलाके के लोगों को मिलती हैं। यह एक महत्त्वपूर्ण योजना है। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री जी से अनुरोध है हमारे इलाके कैथल, कुरुक्षेत्र और जीन्द में भी एस०ई ०जैड० की योजना में कुछ प्रावधान रखा जाये।

अब मैं स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में अपनी बात कहना चाहूँगा। डिलीवरी हट्स की योजना बुहत बढ़िया योजना है। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि रूरल एरिया में जहां 1 ०– 15 गाँव इकट्ठे लगते हैं वहां पर डिलीवरी हट्स बनाई जाएं ताकि रूरल एरिया को इसका ज्यादा लाभ मिल सके। शिक्षा के बारे में मैं जरूर कुछ कहना चाहूँगा क्योंकि मैंने भी कॉलेज में पढ़ाया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि ऐसी यूनिफोर्म योजना बनाई जाये कि जो सिलेबस कैथल डिस्ट्रिक्ट में पढ़ाया जा रहा हो वही सिलेबस रिवाड़ी और महेन्द्रगढ़ जिलों में भी पढ़ाया जाए ताकि इन्सपैक्टर या डी०ई०ओ० वहां पर जाकर चौक कर सकें। इससे शिक्षा के स्तर में सुधार भी आयेगा और शिक्षा का वातावरण सारे स्टेट में बढ़िया भी हो सकेगा। फण्ड अवेलेबल करवाकर इस प्रकार की यूनीफोर्म योजना बनाई जाए ताकि प्रदेश में शिक्षा का सुधार अच्छा हो सके। चूंकि समय कम है, इसलिये मैं अपने हल्के की कुछ माँगों के बारे में भी बोलना चाहूँगा। माननीय मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री जी मेरे हल्के पुण्डरी में सड्कों की बहुत दुर्दशा

है। कोई भी ऐसी सड़क नहीं है जिस पर पिछले एक साल से कोई काम हुआ हो। मेरा माननीय पी०डब्ल्यू०डी० मिनिस्टर से अनुरोध है कि मेरे हल्के की सड्कों के लिये फण्ड उपलब्ध करवाकर जल्दी से जल्दी इनको बनवाया जाये। वहां के लिये दो–तीन स्कीमें आई थीं जिनको पिछली सरकार ने वापिस ले लिया। एक तो पोलटैकिंक के लिये लैंड एक्वीजिशन हो चुकी थी और बुल फार्म के लिए भी लैंड एक्वीजिशन हो चुकी थी लेकिन ये दोनों स्कीमें पिछली सरकार द्वारा कहीं ट्रांसफर कर दी गई। . अध्यक्ष महोदय, मैं अभी सड़कों का जिक्र कर रहा था मेरे हल्के की लांकडा से लेकर सीरसल तक की सड़क के लिये पी०एम० आर०वाई० स्कीम के तहत पैसा आया था। वह पैसा वापिस चला गया और वह सड़क आधी बन चुकी है, आधी रहती है 1 मेरी सरकार से प्रार्थना है कि वह पैसा दोबारा वहां भिजवाया जाये और वह सड़क बनवाई जाये। अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के में चार ऐसे कॉलेज हैं जहां पर जमा दो की क्लासिज पिछली सरकार के समय से बंद कर दी गई। ये कॉलेज इस प्रकार हैं डी०ए०वी० कॉलेज, पुण्डरी, कन्या महाविद्यालय पुण्डरी, जनता कॉलेज कौल और कन्या महाविद्यालय, डांढ। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इन कॉलेजों में जमा दो की कक्षाएं फिर से शुरु की जायें। स्पीकर सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपको धन्यवाद करता हूँ।

Mr. Speaker: Question is—

That the Haryana Appropriation (No.1) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause-2

Mr. Speaker: Question is—

That clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-3

Mr. Speaker: Question is—

That clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Schedule

Mr. Speaker: Question is—

That Schedule be the Schedule of the Bill.

The motion was carried.

Clause-1

Mr. Speaker: Question is—

That clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the Finance Minister will move that the Bill be passed.

Finance Minister (Sh. Birender Singh): Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (नं० 2) बिल, 2006

Mr. Speaker: Now, the Finance Minister will introduce the Haryana Appropriation (No.2) Bill, 2006 and will also move the motion for its consideration.

Finance Minister (Sh. Birender Singh): Sir, I beg to introduce the Haryana Appropriation (No.2) Bill, 2006.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Appropriation (No.2) Bill be taken into consideratrion at once.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Haryana Appropriation (No.2) Bill be taken into consideratrion at once.

श्री ए०सी०चौधरी (फरीदाबाद): स्पीकर साहब, धन्यवाद। वैसे तो बजट अपने आप में एक इतना ऐतिहासिक है कि दोस्त तो दोस्त दुश्मन भी इसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सकते। कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनकी तरफ मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा और इसमें मैं डिमाण्ड नम्बर 9,10,11, 14,15 और 16 पर बोलूंगा। सबसे पहले मैं शिक्षा विभाग की तारीफ किये बगैर नहीं रहूँगा। उन्होंने एक साल के कार्यकाल में स्कूलों की बिल्डिंग की मुरम्मत करने में इतनी तेजी दिखाई है कि आज स्कूल स्कूल नजर आते हैं और वह कबाडीखाने वाला नजारा खत्म हुआ है। शिक्षा मंत्री जी ने जिस तरह से अपने वायदे में कहा है कि अच्छे स्कूल बनाएंगे और वे मॉडल स्कूल भी बना रहे हैं। मैं उनकी जानकारी

के लिये बताना चाहूँगा और उनसे विनम्र आग्रह भी करूँगा कि महज बिल्डिंगें बनाने से स्कूल नहीं बना करते वहां पर स्कूल का वातावरण होना भी बहुत जरूरी है। आज Commercialization to the extreme है और प्राईवेट अदायरे इतनी तेजी से फैल रहे हैं कि ईवन रिक्शापुलर भी कान्वैंट और इंगलिश मीडियम स्कूल की तरफ अपने बच्चों को ले जाना पसन्द करता है जो कि फाईनैंशियली उनके सामर्थ्य में नहीं है। उसका कारण सिर्फ इतना है कि जहां हमारे पास योग्य अध्यापक हैं और हम कमरे बना देंगे लेकिन वहां का वातावरण पढ़ाई का होना चाहिये ताकि लोग उसमें कांफिडेंस रिपोज करें। अगर आप प्राईवेट स्कूलों के साथ सरकारी स्कूलों की गिनती करें तो निम्न से निम्न वर्ग वाले लोग भी सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को भेजना नहीं चाहते लेकिन वे अपने बच्चों को वहां पढ़ाने के लिये बाध्य हैं वरना दिन–ब– दिन सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या लगातार कम हो रही है। (इस समय सभापतियों की सूची में से एक माननीय सदस्य श्री आनन्द सिंह डांगी पदासीन हुए) दूसरी तरफ opportunists professional उस पर थराइव कर रहे हैं और इसका नतीजा यह है कि डिस्पैरिटी बढ़ती जा रही है। ऐसा लगता है कि आज आजादी के बाद फिर हिन्दुस्तान में गोरे और काले वाली बात हो जाएगी। जो गरीब का बच्चा है वह काला हिन्दुस्तानी बन कर रह जाएगा और पैसे वाले सामर्थ्यवान का बच्चा आगे बढ़कर अंग्रेज की भांति बन जाएगा और सारे साधन इकट्ठे कर लेगा। सभापति महोदय, यह बहुत जरूरी है कि ऐसी कोई स्कीम बना ली

जाए कि जिसमें बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ें। आज 200–250 बच्चों की संख्या पर हायर सैकेंडरी स्कूल चल रहे हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि अंग्रेजियत की प्रवृति पर रोक लगाएं। चेयरमैन सर, हमने वर्ष 2006 गर्ल्ज चाईल्ड ईयर के तौर पर घोषित किया है। मैंने एक छोटी सी प्रार्थना इसी हाउस के माध्यम से मुख्यमंत्री जी तथा शिक्षा मंत्री जी से की थी 1 मेरा एक गाँव सीकरी है जोकि हल्के के सैंटर में पड़ता है। वहां पर लोगों के पास पैसा भी है, जमीन भी है और उसके इर्द–गिर्द 15–20 गांव बड़े नजदीक में हैं। वहां के लोग एक कॉलेज के लिये प्रार्थना कर चुके हैं और मैंने भी उनका समर्थन किया है।

अगर वहां के लिये सरकार द्वारा कॉलेज की मंजूरी दे दी जाए तो मेरा विश्वास है कि फरीदाबाद, बल्लभगढ़ और पलवल के बीच समाया हुआ छोटा सा पॉकेट ग्रामीण अंचल है वहां के बच्चे अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे और इसका नतीजा यह होगा कि हम जिस सपने को देखकर आगे हरियाणा को देश का नम्बर वन राज्य बनाना चाहते हैं वह सपना साकार होगा। चेयरमैन सर, टैक्नीकल ऐजुकेशन के हमारे पास सिर्फ दो ही कॉलेज हैं एक सोनीपत में और दूसरा फरीदाबाद में वाई०एम०सी०ए०। फरीदाबाद वाले कॉलेज की अपग्रेडेशन तो हुई है लेकिन आज भी वाई०एम०सी०ए० में पढ़ाई का खर्च 6000 रुपये से कम नहीं है और सोनीपत हमारा एकमात्र टैक्नीकल कॉलेज है जहां पर हमारे बच्चों के लिए अट्रैक्शन है। गरीब अंचल से किसान का बच्चा,

मजदूर का बच्चा, फैक्टरी के गरीब मुलाजिम का बच्चा भी वहां पर अपना भविष्य देख रहा है। लेकिन उस कॉलेज के बारे में तरह–तरह की अफवाहें आ रही हैं कि उसको प्राईवेट किया जा रहा है। सभापति महोदय, प्राईवेटाईजेशन से मुझे कभी नफरत नहीं थी लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जहां दुकानदारी की प्रवृति होगी वहां पर गरीब आदमी की बात नहीं हो पाएगी। इसलिए विनम्रतापूर्वक सरकार से मेरा आग्रह है कि न सिर्फ सरकार इन कॉलेजों को अपने माध्यम से अपने जरिये चलाए बल्कि ज्यादा से ज्यादा टैक्नीकल इन्स्पीच्यूशन्ज और हायर एजुकेशन के संस्थान सरकारी फंडिंग से चालू हों ताकि गरीब से गरीब आदमी अपने बच्चों को उन संस्थाओं में पड़ा कर उनका भविष्य बनाने में सफल हो सके। चेयरमैन सर, फरीदाबाद में हमारी सरकार के पिछले कार्यकाल में करीब 10 साल पहले हमने एक मैडिकल कॉलेज मंजूर करवाया था। एक करोड़ की एक पार्टी बी०एम०एस० शिक्षण संस्थान था उनका कोई आपसी झगड़ा हो गया और उस कॉलेज की मंजूरी आज भी रुकी हुई है। मैं चाहूँगा कि उससे जो नुकसान होना था वह तो हो चुका लेकिन अब स्टेट का और ज्यादा नुकसान न हो और अगर उसकी जगह उसको कोई और संस्था लेना चाहती है तो उसकी मंजूरी के लिए भी सरकार आश्वस्त करे ताकि हम किसी और पार्टी को डिवैल्प करके फरीदाबाद तथा हरियाणा को मैडिकल ऐजुकेशन के मामले में आगे ले जा सकें।

चेयरमैन सर, आईटम नं० 10 हैल्थ के बारे में है। हैल्थ के मामले में मैं कहना चाहूँगा कि अस्पतालों की भी वही हालत है जो शिक्षण संस्थानों की है। हमारे अस्पतालों की हालत बहुत ही खराब थी लेकिन मैं धन्यवाद करूँगा हैल्थ मिनिस्टर साहिबा का कि उन्होंने पीछे बिल्डिंगों के लिए बड़े खुले दिल से पैसा दिया। दस साल पहले के शुरू किए हुए अस्पताल जहां एक पैसा खर्च नहीं हुआ था उन अस्पतालों को दो–दो फेसिज में मुकम्मल करने का वायदा ही नहीं किया गया बल्कि उसका कार्यान्वयन करके उनका कार्य भी शुरू करवा दिया है। लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि आज हैल्थ भी अपने आप में कामर्शियलाईज हो चुकी है। प्राईवेट होस्पिटल और नर्सिंग होम गरीब लोगों का खून निचोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। प्रायः आपकी नॉलेज में यह आया होगा कि मरीज अपनी जान बचाने के लिए नर्सिंग होम में गया और उसकी जान भी बच गई लेकिन जब बिल बना तो उस बिल को चुकाने के लिए उसको अपना घर ही गिरवी रखना पड़ा था। इसके अलावा कई जगहों पर जब तक मरीज बिल चुकता नहीं करते हैं तब तक उन मरीजों को छुट्टी नहीं दी जाती है। इसके लिये हमें चाहिए कि हमारे होस्पिटल्ज की जो बिल्डिंग्ज हैं उनको ठीक किया जाए और वहां पर जो टैस्टिंग और डाइगनोस्टिक जितने भी इक्यीपमैंट्स हैं वे पूरे करके वहां पर गरीब लोगों को पूरी सुविधाएं देने का प्रावधान जल्दी से जल्दी किया जाए। अगर सरकार ऐसा करती है तो जो

इस सरकार की गरीबों की मदद करने की भावना है वह पूरी हो सकेगी।

चेयरमैन सर, आज गाँवों के लोग शहरों की तरफ इसलिए अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि अच्छे होस्पिटल्ज और अच्छी शिक्षा शहरों में ही है। इसलिए वे अपनी गाँवों की जमीनें औने–पौने भावों पर बेचकर शहरों में बसने शुरू हो गए हैं और इससे सारे का सारा बैलेंस बिगड़ता जा रहा है। इस बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए।

इसके साथ ही मैं अर्बन डिवैल्पमैंट की डिमांड नं० 11 के बारे में कहना चाहता हूँ । पिछली सरकार के नेता का नाम लेकर मैं अपना मुँह गन्दा नहीं करना चाहता हूँ। चेयरमैन सर, आपने भी देखा होगा कि जैसे गाँव की गली–गली में नींबू की सिकंजवी बनाने वाला रेहडी लगाकर घूमता रहता है और वह नींबू को इस तरह से सिकंजवी बनाने के लिए निचोड़ देता है कि उसमें एक बूंद रस भी नहीं रह जाता है। तभी तो किसी ने कहावत बनाई हुई है कि नींबू की तरह निचोड़ दिया। लेकिन पिछली सरकार के मुखिया ने हरियाणा के लोगों को और हरियाणा के औद्योगिक नगरों को इस तरह से निचोड़ा है कि आज यहां पर उद्योग तो हैं लेकिन जिसको ये कहा जा सकता है कि Industrial area sans industries, आज हरियाणा में ये हालात हैं। चेयरमैन महोदय, इसका जिन्दा सबूत फरीदाबाद है। फरीदाबाद इतना बड़ा इडस्ट्रीयल काम्पलैक्स था, जो दुनिया में

10वें नम्बर पर था। लेकिन आज वहां पर हालात यह है कि उद्योगों के ढाचे तो खड़े हैं लेकिन उनमें कोई भी चीज अवेलेबल नहीं है। इसी तरह से फरीदाबाद में मजदूरों की दशा बहुत बुरी है। मजदूर अपने मकानों को बेचकर नालों के किनारे छोटे–छोटे स्लग्ज पॉकेट्स में रहने पर विवश हैं क्योंकि उन्होंने पेट की आग को भी बुझाना है। मेरा सरकार से आग्रह है कि शहरों के सुधार के साथ–साथ जिस तरह से नागरिक सुविधा प्लैंड कॉलोनीज में नागरिकों को देते हैं वही सुविधाएं अनप्लैंड कॉलोनीज और स्लग्ज एरिया में भी देनी चाहिएं। वहां पर भी बेसिक सुविधाएं जैसे पानी, बिजली और सफाई आदि दिए जाने चाहिएं और उन पर सभी का अधिकार होना चाहिए। चेयरमैन महोदय, आज आम आदमी और सरकार भी इस बात को मान्यता देगी कि मजदूर अपने खून पसीने से इण्डस्ट्रीज का बिजनैस बढ़ाकर प्रदेश और उस इण्डस्ट्री की उन्नति करता है। इसलिए उन सभी सुविधाओं पर उसका भी तो कुछ अधिकार बनता है। चेयरमैन महोदय, फरीदाबाद में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है और उसने तीन बार सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया कि जब तक सिविक बाडिज की अपनी आमदन नहीं होगी तब तक सिर्फ सरकार की ग्रांटों पर शहर का सही विकास नहीं हो पाएगा। सर, उस नाते से हरियाणा में चुंगी को खत्म किया गया था। सर, वह इन्डायरैक्ट टैक्स था। टैक्सेशन में डायरैक्ट टैक्स अनवाटिड होगा, इनडायरैक्ट टैक्स में किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि आप इस मामले को एग्जामिन करें। पंजाब ने भी चुंगी बंद की थी और

उनको चुंगी दोबारा से चालू करनी पड़ी है और तभी जाकर शहरों का विकास होना शुरू हो पाया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार का ध्यान इस तरफ आकर्षित होगा।

इसी तरह से आज शहरों में पोल्यूशन के बारे में कहना चाहूँगा कि दिल्ली से सभी स्कैप फोर व्हीलरज और थ्री व्हीलरज जो कि कोर्ट ने दिल्ली में चलने के लिए अनफिट कर दिए थे वे हमारे फरीदाबाद, गुड़गांव, सोनीपत, बहादुरगढ़ और रोहतक में सबसे ज्यादा पोल्यूशन कर रहे हैं। मेरा सरकार से आग्रह है कि फौरी तौर पर इस बात को सुनिश्चित करें कि राटन और बर्नआउट व्हीकल्ज हरियाणा में बैन हों। जो व्हीकल्ज डीजल का धुआ फैंक-फैंककर इन्वायरनमैंट को खत्म कर रहे हैं उन पर रोक लगे। सरकार ने अपनी तरफ से प्रोग्रेसिव पोलिसी दी है लेकिन पिछली सरकार ने ऐसा नहीं किया। चेयरमैन सर, मैं आपको यमुनानगर की मिसाल देना चाहूँगा। गरीब आदमियों को रेहडी खड़ी करने के लिए तहेबाजारी में जगह दी जाती है। पहले इसका चार्ज दस पैसे प्रति स्कवायर फुट होता था लेकिन बाद में यह बढ़ते-बढ़ते एक रुपया प्रति स्कवायर फुट हुआ। मैं इस बार नाम लेते हुए कहूँगा कि पिछली सरकार के समय में ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि अगर मेरे पास उन लोगों का डैपुटेशन आए तो मैं उनको वहां रेहडी लगाने के लिए जगह दे दूंगा। इस तरह से उनका आर्गेनाईजेशन का कंसैप्ट था कि लोगों को मल्कियत का हक इस तरह से मिलेगा। उन्होंने मीटिंग में वहां पर कहा कि

अगर उनके आनर में पार्टी दी जाए तो मैं उनको जगह दे दूंगा। चेयरमैन सर, वहां के दुकानदारों ने उस समय पैसा इकट्ठा किया। यह मैं आपको मीना बाजार, यमुनानगर की मिसाल बता रहा हूँ। जब दुकानदारों ने पैसा इकट्ठा कर लिया और जब वे इस पैसे से पार्टी करने लगे तो सी० आई०डी० ने चौटाला से जाकर कह दिया कि आपके लिए वे लोग चंदा इकट्ठा करके खाना देने जा रहे हैं। इसके बाद चौटाला साहब इतने भड़क गये कि उन्होंने गरीबों की गरीबी की भावनाओं का ख्याल नहीं किया और उसका प्रतिकार करते हुए उन्होंने कहा कि तुम मेरे लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हो जाओ, तुम्हारे लिए एक रुपये प्रति स्कवायर फुट से दस पैसे प्रति फुट करना तो दूर अब तो मैं दस रुपये प्रति स्कवयार फुट करूँगा। चेयरमैन सर, इतनी बड़ी डिक्टेटरशिप, इतना बड़ा जुल्म कि दस पैसे स्कवायर फुट के बजाए दस रुपये प्रति फुट तक रेट पहुँचा दिया जाये और वह भी इसलिए क्योंकि गरीब आदमी सी०एम० का खाना नहीं दे सकते थे। चेयरमैन सर, मैं अपनी अर्बन डिवैल्पमैंट मिनिस्टर से विनम्रतापूर्वक कहना चाहूँगा कि यह जायज केस है इसलिए इसको अगर आप देखेंगे तो . आपका मन भर आएगा। चेयरमैन सर, जब हम बिजली के मामले में प्रताड़ित गरीबों की मदद कर सकते हैं और उन्हें सुविधाएं दे रहे हैं तो इस मामले में भी ध्यान दिया जाना चाहिए। अर्बन एरियाज में पिछली सरकार ने हाउस टैक्स पचास गुणा कर दिया। इसके बाद हजारों लोग कोर्टस में जा चुके हैं। इनमें से मैं भी एक लिटीगेट हूँ। मेरे नाम से भी 900 आदमियों की अपील चल

रही है। मेरी प्रार्थना है कि जब हम बिजली की समस्या को देख रहे हैं तो शहरों में हाउस टैक्स की समस्या का भी निदान किया जाये। यह निदान एक ही बात पर होगा कि हाउस टैक्स पहले की तरह ही कर दिया जाए या सैल्फ आकुपाईड का वही पुराना स्टेट्स कर दिया जाए जिसमें विडोज को कसेशन, आर्मी सर्विस पर्सनल को कसैशन हालांकि पहले था, अगर अब भी दे दिया जाए तो शहर के लोग भी इस बात का अहसास करेंगे कि वाकई हमारी सरकार आई है। चेयरमैन सर, डिवैल्पमैंट चार्जिज की भी प्रथा बनी है। पहले 15 रुपये गज डिवैल्पमैंट चार्जिज दिया गया और उसके बाद जब मैं लोकल गवर्नमैंट मिनिस्टर बना तो उस समय 15 रुपये गज यह चार्जिज थे। फिर 15 रुपये से पचास रुपये गज और फिर 90 रुपये गज के हिसाब से डिवैल्पमैंट चार्जिज कर दिए गए जोकि आम आदमी की पहुँच से बाहर हैं। जिस गरीब आदमी ने 15,20 या 25 गज जमीन का टुकड़ा लेकर अपनी झुग्गी बनाई है वह कहां से ये डिवैल्पमैंट चार्जिज देगा? पिछली सरकार ने इस हद तक अन्याय बढ़ाया कि डिवैल्पमैंट चार्जिज लेने का नोटिस तक नहीं दिया गया और उस गरीब आदमी के ऊपर ब्याज लगाना शुरू कर दिया। देहली या दूसरी जगहों पर जितने प्रोग्रेसिव कॉरपोरेशज हैं, सिविक बाडीज हैं जहां–जहां पर डिफाल्टर्ज हुए हैं उन्होंने कंसैशन देकर इस खाते को पूरा किया है। इसलिये मैं भी सरकार से आग्रह करूँगा कि डिवैल्पमैंट चार्जिज पुराने रेट पर ही लगाए जाएं और दो,तीन, चार किश्तों में जैसा मुनासिब समझें इनको पेमेंट देने का टाईम फिक्स कर दिया जाए और तब तक के

लिए उस पर ब्याज लगाना भी खत्म कर दिया जाए। चेयरमैन सर, कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करते हुए कहा है कि अब बी०पी०एल० लोगों को और ज्यादा सहूलियतें दी जाएंगी। मैं फिर से जिम्मेवारी से कह रहा हूँ कि पिछली सरकार ने जितने भी बी०पी०एल० के पीले और लाल कार्ड दिए थे वे सब के सब अपने हमवारियों को, अपने एजेंटों को या उन लोगों को दिए हैं जो अपने आप में सक्षम थे और जो आज भी एक–एक हजार रुपये अपनी शराब पर खर्च करते हैं। जिनका हक बनता था उनको ये कार्ड नहीं मिले हैं। आज अगर यह कंसैशन हमारी सरकार दे तो मेहनत का, सोचा समझा प्लांड पैसा फलोआउट भी नहीं होगा और उन लोगों के घरों में जिनका कभी भी इस पर अधिकार नहीं रहा है, उनको उसका फायदा नहीं होगा। तो मैं प्रार्थना करूँगा कि जो सहूलियत आपने अनाऊंस की हैं उनको लागू करने से पहले बी०पी०एल० कार्ड बनाने के लिए दोबारा से सर्वे करवाया जाए ताकि हकदार को इसका हक मिल जाए और इस पैसे का सदुपयोग भी हो सके। मैं बड़ी रिजर्वेशन के साथ कह सकता हूँ कि अगर सही मायने में सर्वे करवाया जाए तो कम से कम 90–95 प्रतिशत लोगों के ये कार्ड कैन्सिल करने पड़ेंगे क्योंकि वे क्राईटेरिया को फुलफिल नहीं करते। वो सिर्फ हन्ट्समैन थे, सरकार के दल्ले थे और लोगों की कास्ट पर श्राईव कर रहे थे। जहां तक पानी की समस्या की बात है उसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि पानी की समस्या चाहे किसान की हो या चाहे लोगों को पीने के पानी की समस्या हो दोनों हालात में ये दोनों तबके

पानी की कमी से मर रहे हैं। मेरे हल्के का काफी हिस्सा अरावली हिल्ज की तलहटी में हैं। यह जी०टी० रोड और रेलवे लाईन के घेरे में आता है। वहां दोनों तरफ से कोई एसैस नहीं है। मेरे हल्कों के कुछ गाँव जैसे बीजोपुर, जैकोपुर की जमीन बंजर होती जा रही है। कबुलपुर डांगर की हजारों एकड़ जमीन में अनाज का एक भी दाना नहीं बोया जा रहा है क्योंकि सिंचाई की कमी है। लोग पम्पों के द्वारा पानी निकालने की कोशिश करते हैं तो उनके खिलाफ केस दर्ज हो रहे हैं और उनके ऊपर वाटर थैपट के केस बन रहे हैं। इसका नतीजा यह निकलता है कि उन लोगों का जीवन दूभर हो रहा है। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि उस इलाके को नहर का पानी दिया जाये। गुड़गांव नहर जोकि पास ही है सरकार चाहे तो उससे भी पानी दिया जा सकता है।

श्री सभापतिः चौधरी साहब, वाईंड अप कीजिए।

श्री ए०सी० चौधरीः चेयरपर्सन महोदय, आखिर में मैं फरीदाबाद के बारे में जिक्र करना चाहूँगा। फरीदाबाद जो हैवी और लार्ज इण्डस्ट्रीज के मामले में वर्ल्ड में नम्बर 10 का इण्डस्ट्रीयल कम्पलैक्स माना गया है, आज वहां पर उद्योग नही रहे हैं जबकि नोएडा और राजस्थान में जहां आम हालात कन्जीनिएल थे और जहाँ कोई जाना पसंद नहीं करता था और वहां आज उद्योग लग रहे हैं नोएडा तो पहले शिकागो से भी बदतर हो चुका था और आज भी वहां पर क्राइम हैं। लेकिन फिर भी वहां पर उद्योग जा रहे हैं। पिछली सरकार के जुल्मों से, पिछली सरकार

के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सिज प्रैशर की वजह से और पिछली सरकार की स्कवीजिंग की वजह से सारे कारखाने फरीदाबाद से पलायन कर चुके हैं। मैं सरकार से आग्रह करना चाहूँगा कि मेहरबानी करके फरीदाबाद को फिर से बसाये। (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुये)

श्री अध्यक्षः चौधरी साहब, आपको बोलते हुये 18 मिनट हो गये हैं जबकि आपने 15 मिनट के लिये कहा था इसलिये अब आप वाइंड अप कीजिए।

श्री ए०सी० चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मुझे थोड़ा टाईम और दीजिए।

श्री अध्यक्षः चौधरी साहब, अब आप वाइंड अप कीजिए। आपकी जो बातें रह गई हैं वे आप लिखकर भिजवा दें।

श्री ए०सी० चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ कम्प्यूटर पार्क, कामर्शिएल जोन, टैक्सटाईल पार्क, आटोमोबाईल पार्क का प्रावधान करने के लिए सरकार से आग्रह करूँगा ताकि फरीदाबाद में जो वर्कशॉप हैं वे दोबारा से पनप जाएं। धन्यवाद।

श्री नरेश कुमार प्रधान (बादली): स्पीकर महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। हर वर्ग के भविष्य का ध्यान रखते हुए और 36 बिरादरी को साथ लेकर बजट में जो कल्याणकारी नीति सुचारु रुप से लागू की गई हैं उसके लिए मैं

माननीय मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूँ। लेकिन स्पीकर सर, पिछली सरकार के समय में चंगेजखान, सद्दाम हुसैन और रावण जैसी मनोवृति के व्यक्ति किसानों के साथ झूठ बोलकर राज हथियाने में कामयाब हुए थे। उन्होंने जनता पर जुल्म और सितम ढाए। इसके अलावा वे बेरोजगारों के रोजगार को अपने इलाके में ले गये और हमारे किसानों कैं हिस्से का पानी भी लूटकर अपने इलाके में ले गये। इसके बारे में जनता पूछती है कि उनके जुल्मों और सितमों का हिसाब कब होगा? स्पीकर सर, वे लोग सत्ता में विराजमान होने के बाद कहते थे कि हम जब तक जिंदा रहेंगे राज करेंगे लेकिन उनका हश्र आप सबके सामने है, आज वे होस्पिटल में मोधे मुँह पड़े हैं। स्पीकर सर, सभी विधायक भाईयों से, आपसे और खासकर माँ समान बहन करतार देवी जी से मेरी प्रार्थना है कि जब भी वह जल्लाद जो कि बीमारी का बहाना बनाये पडा है, विधान सभा में घुसने की कोशिश करे तो उस समय घातक बैक्टिरिया ओर कीटाणु विधान सभा में प्रवश न कर सके इसके लिए जब तक पहले उसका फिटनैस सर्टिफिकेट और रि—मेडिकल दोबारा से न हो जाए तब तक उसको विधान सभा में घुसने नहीं दिया जाए। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि मेरी इस प्रार्थना पर जरूर ध्यान दिया जाए। स्पीकर सर, उस जल्लाद के काले कारनामों से तंग आकर हरियाणा प्रदेश से उद्योगपति अपने उद्योग कहीं दूसरे प्रदेशों में ले गये और उसने लाखों कर्मचारियों को भी घर से बेघर किया। उन कर्मचारियों की भूखी आत्माएं जब हम अपने हल्कों में जाते हैं तो हमारे से पूछती

हैं कि उनको न्याय कब मिलेगा। जो उनके साथ उस जल्लाद ने जुल्म किए हैं उसके लिए उस जल्लाद को सलाखों के पीछे कब डाला जाएगा। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि उस जल्लाद को जल्दी से जल्दी सलाखों के पीछे भेजा जाये ताकि हरियाणा की जनता को न्याय मिल सके। अध्यक्ष महोदय, उसने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को और नेताओं को भी नहीं छोड़ा 1 जिन पार्टियों ने उनका साथ दिया था उनके खिलाफ भी उसने झूठे मुकद्में बनवाये। मैं गौतम चाचा से पूछना चाहता हूँ कि जिन्होंने कांग्रेस की सरकार पर टिप्पणियां कीं, जिस समय चौटाला की ससकार थी और उनके काले कारनामे चल रहे थे उस समय वे कहाँ गये थे। उनकी पार्टी वाले एक शब्द उस समय नहीं बोल पाते थे। उस समय ये छिप–छिप कर रहते थे। अध्यक्ष महोदय, सिंचाई मंत्री जी बैठे हुए हैं मैं कहना चाहूँगा कि मेरे आधे बादली हल्के में लिफ्ट कैनाल सिस्टम से सिंचाई के लिए पानी दिया जाता है। कभी बिजली नहीं रहती, कभी इनका जरनेटर खराब रहता है इसलिए मैं मंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि अब वहां पर लिफ्ट कैनाल सिस्टम खत्म कर दिया जाये और सीधा फलैट पानी दिया जाये। ऐसा करने से सरकार के पैसे भी बचेंगे। अब वहां फलैट पानी जा सकता है क्योंकि भट्‌ठे वालों ने जमीन चार–चार फिट तक खोदकर इटे बना ली हैं और अब जमीन का लैवल ठीक हो गया है। इस पर मंत्री जी अवश्य ध्यान दें। जयहिन्द।

श्री सतविन्द्र सिंह राणा (राजौंद): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अपने विचार रखने के लिए मौका दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार को बने हुए एक साल का समय हुआ है। इस एक साल के दौरान हमारे मुख्यमंत्री जी की अच्छी नीतियों के कारण हर वर्ग को फायदा पहुंचा है इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ। इसके अतिरिक्त मैं वित्तमंत्री जी को भी बधाई देता हूँ कि वित्तमंत्री जी 2006–07 के लिए बहुत अच्छा बजट लेकर आये हैं। वितमंत्री जी ने इस बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस एक साल के दौरान जिस तरह से किसानों के हित्तार्थ जो कार्य किए हैं वे अपने आप में एक मिसाल है। चाहे 1600 करोड़ रुपये के बिजली के बिल माफ करने की बात है, चाहे पानी के समान बंटवारे की बात है। मुख्यमंत्री जी ने किसानों की हर समस्या की तरफ ध्यान दिया है। अध्यक्ष महोदय, पानी के समान बंटवारे के लिए मैं सिंचाई मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव जी को भी मुबारकबाद देता हूँ। पानी के समान बंटवारे का सरकार का फैसला बहुत अहम् फैसला है। हमारा इलाका टेल पर पड़ता है और हमारे वहां के किसान पानी की एक– एक बूंद के लिए तरसते थे। हम बहुत दिनों से पानी के समान बंटवारे की बात कर रहे थे लेकिन किसी ने हमारी नहीं सुनी। अब हमारी सरकार आने के बाद पानी का समान बंटवारा किया गया है। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के साथी वाक आऊट कर गये। उनके पास आज सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है। वे किसी न किसी बहाने से

वाक–आउट कर जाते हैं। वै लागों को फेस नहीं कर सकते। उनको भी मालूम है कि हमारी सरकार किसानों और प्रदेश की जनता के हितार्थ बहुत अच्छे कार्य कर रही है। चाहे ट्रैक्टर की रजिस्ट्रेशन फी की बात है, चाहे ब्याज दर घटाई गई है हर तरह की सुविधा हमारी सरकार ने किसानों को दी है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक उद्योगों की बात है पिछली सरकार के समय में उद्योगों का प्रदेश से पलायन हो रहा था। हरियाणा के अन्दर दोबारा से आज जो भारी उद्योग लग रहे हैं उनसे हरियाणा की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और नौजवानों को रोजगार मिलेगा। इसी तरह से स्वास्थ्य और शिक्षा में जिस तरह से बजट के अन्दर पैसे का प्रावधान किया गया है जिस तरह से शिक्षा के ऊपर इतना पैसा खर्च किया जा रहा है इससे निश्चित रूप से हरियाणा का विकास होगा। स्कूलों के लिए नये कमरे बनाए जा रहे हैं और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हर देहात के अन्दर नई–नई योजनाएं चलाई जा रही हैं। महिलाओं के लिए डिलिवरी हट्स की और टीकाकरण जैसी सारी सुविधाएं इस सरकार ने प्रदेश के अन्दर दी हैं। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से लड़कियों के प्राईमरी स्कूलों की 1500 बिल्डिंगों में बिजली के कनैक्शज देना, लड़कियों के सरकारी प्राईमरी स्कूलों में 4500 शौचालयों का निर्माण और ऐसी ग्राम पंचायतों को एक लाख रुपये देने की घोषणा की है जो अपने गांव में 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को सरकारी स्कूलों में ऐडमिशन दिलवायेंगी, ये कार्य सरकार ने इसलिए किए हैं ताकि यहां पर अच्छी ऐजूकेशन देने के लिए बढ़ावा मिले और लड़कियां

अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कर सकें। टैक्नीकल कोर्सिज में लड़कियों को 25% आरक्षण दिया गया है। अध्यक्ष महोदय बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनके बारे में मेरे से पहले बोलने वाले साथियों ने जिक्र किया। मेरे विपक्ष के आदरणीय साथी जो अभी बोल रहे थे कि सरकार ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या वे उस समय को भूल गए हैं जब उनके प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, वे यह कहा करते थे कि देखो भई यह जो फसल है इसे छोड़ो और फूलों की खेती किया करो। मैं उनसे यह पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने किसानों को कौन सी ऐसी सुविधा दे रखी थी जिससे उसका कोई भला हुआ हो। उस समय जो गेहूँ थी वह समुद्र में फिंकवाई गई थी और उस समय उससे मछलियों को खतरा हो गया था जो लोग मछलियां खाते थे उनकी तरफ से भी उसका विरोध हुआ था। भाई राम कुमार गौतम जी शहीदों का नाम ले रहे थे। मैं मानता हूँ कि आजादी से पहले हमारे बहुत से शहीद थे जिन्होंने हँसते–हँसते अपने प्राणों की कुर्बानी देकर देश को आजाद करवाया। अध्यक्ष महोदय, आजादी के बाद अगर किसी ने कुर्बानी दी है तो वे तीन नेता थे, महात्मा गांधी जी, इन्दिरा गांधी जी तथा श्री राजीव गांधी जी, जिन्होंने आजादी के बाद देश की एकता और अखण्डता के लिए अपने आपको कुर्बान कर दिया 1 आज ये कहां की बात करते हैं क्योंकि इनको तो जो पढ़ाया जाता है जो पीछे से लिखकर आता है कि यह बोलना है ये यहां आकर वही बोल देते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूँ कि आज इस सदन के अन्दर कोई

भी विपक्ष का आदमी इस बात को नहीं कह सकता कि इस सरकार के अन्दर यह कमियां हैं। जैसे बिजली के बारे में ये लोग कहते हैं मैं पूछना चाहता हूँ कि बिजली की जो कमी है वह किस की देन है। ये क्षेत्रीय छोटे–छोटे दल जो झूठ बोल कर राजनीति करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं और जब सत्ता में आते हैं तो लोगों का शोषण करते हैं 1 .अध्यक्ष महोदय, इनकी वजह से ही इस प्रदेश की अर्थ– व्यवस्था बिगड़ी हुई थी जिसको आज मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्‌डा तथा हमारी सरकार एक साल के अन्दर–अन्दर पटरी पर लाए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने इलाके के अन्दर कुछ बातों की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। वैसे तो मुख्यमंत्री जी और बिजली मंत्री जी को मैं मुबारिकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे इलाके राजौन्द के अन्दर, नगरा के अन्दर 132 के०वी०ए० के सब–स्टेशन शुरू कर दिए हैं और उसके बाद हमारे गंगा टेड़ी और बारी में 33 के०वीए० के ऐस्टिमेट्‌स आए हुए हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इनको जल्दी से जल्दी बनवाने की कृपा करें। इसी तरह से किठाना गांव कैथल जिले का लास्ट गांव है उसके अन्दर 33 के०वी०ए० का सब–स्टेशन बनाया जाए। राजौन्द और अलेवा हमारे यहां पर बहुत बड़े कस्बे हैं वहां पर मण्डियों का कोई प्रावधान नहीं था लेकिन अब सरकार ने वहां पर मण्डियों के लिए जमीन ले ली है। मैं यह निवेदन करता हूँ कि वहां पर जल्दी से जल्दी मण्डी बनवाई जाए। इसी तरह से गांव अलेवा ने पी०एच०सी० के लिए जमीन दी हुई है वहां पर जल्दी से

जल्दी पी०एच०सी० का कार्य शुरू करवाया जाए। अध्यक्ष महोदय, मेरा जो राजौन्द का इलाका है यह सारा नहरों की टेल पर है और यहां पर नहरों का एंड पड़ता है जिसमें राजौन्द का एरिया बरानी है और सिंचाई विभाग की कोई भी योजना इस एरिया के लिए नहीं बनी है। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मण्डवाल माईनर और मुहम्मद खेड़ा माईनर का निर्माण कार्य किया जाना भी अनिवार्य है। इसके साथ ही राजौंद क्षेत्र के गांव कोकोपडा, अहलान जोगी खेड़ा और मण्डीखुर्द के लिए भी एक माइनर की स्कीम पहले बनाई गई थी लेकिन उस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मैं आपके माध्यम से इरीगेशन मिनिस्टर जी से अनुरोध करूंगा कि उस स्कीम के बारे में विचार करके जल्दी से उसको बनवाया गए। स्पीकर सर, सरकार द्वारा खालों की मरम्मत करने की योजना है और उस योजना के अन्तर्गत राजौंद इलाके के लिए एक करोड़ रुपये के एस्टीमेटस सरकार को स्वीकृति के लिए भेजे हुए हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि उन एस्टीमेटस को सरकार द्वारा जल्दी से स्वीकृति दी जाए। अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा बाढ़ के पानी की निकासी के लिए एक ड्रेन स्कीम बनाई गई थी जिससे बाढ़ का पानी ड्रेन के माध्यम से घग्गर में डलवाया जाना था लेकिन इस स्कीम पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध है कि इस बारे में जल्दी–से–जल्दी कार्यवाही की जाए।

स्पीकर सर, आज शहरों के अन्दर डवैल्पमैंट हो रही है उसकी वजह से देहात के लोग शहरों की ओर भाग रहे हैं। अगर हम आज देहातों और कस्बों का अच्छी तरह से सौंदर्यीकरण कर दें तो लोग शहरों की तरफ जाना बंद कर देंगे। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूँगा कि मेरे गांव में तीन तालाब हैं। उस गांव में जो बरसाती नाला है उसमें गांव का जो गंदा पानी होता है वह उन तालाबों में जाता है, जिसकी वजह से उन तालाबों का पानी बहुत ही गंदा हो गया है। गांव के लोग उन तालाबों में पशुओं को नहलाते हैं और उनको पानी भी पिलाते हैं, जिसकी वजह से उन पशुओं में बीमारी फैल रही है। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि मेरे गांव के गंदे पानी को ड्रेन बनाकर वहां से बाहर किया जाए। जिस तरह से शहरों में ट्रीटमैंट प्लांट लगाकर पानी को साफ किया जाता है, उसी तरह से मेरे गांव में भी ट्रीटमैंट प्लांट लगाकर उस पानी को साफ करवाने का इंतजाम करवाया जाए और उस पानी को खेतों में देने के लायक बनाया जाए। इसी तरह से यहां पर बिजली की बात आई है। मैं मानता हूँ कि पिछली सरकार की कमियों की वजह से आज हमें बिजली की कमी को भुगतना पड़ रहा है। आज हमारे मुख्यमंत्री जी की बिजली की कमी को पूरा करने की जो मंशा है वह बहुत ही अच्छी है। उस कमी को पूरा करने के लिए जो पावर प्लांट बनाने के लिए व्यवस्था की है मैं उम्मीद करता हूँ कि वह प्लांट दो तीन साल में पूरा हो जाएगा। इसके अलावा आदरणीय मान साहब ने बताया है कि राजौंद के अन्दर बिजली

विभाग की स्टाफ की बहुत कमी है। (विघन) यह बिलकुल सही है कि वहां पर जो पिछले 10– 15 साल से बिजली विभाग में स्टाफ लगा हुआ है वह सारे का सारा शराबियों से भरा हुआ है। इस बारे में जब हम एक्सियन और एस०डी०ओ० को कहते हैं तो वे कहते हैं कि सर, हम क्या करें ये मानते ही नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार के वक्त में वहां पर जो लाईन मैन भर्ती किए गए हैं वे सभी के सभी के हो गए हैं और वे खम्बों पर चढ़ ही नहीं सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने सिर्फ एक ही काम कूर रखा था कि वे पुलिस की ही भर्ती करते थे और दूसरे महकमों को खाली ही छोड़ रखा था। उन्होंने पुलिस की भर्ती पर ही जोर दिया हुआ था कि हम यह सेना बनाएंगे और पता नहीं यह सेना उनका क्या काम करेगी। मैं मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि हमारे यहां पर बिजली का जो बिगड़ा हुआ स्टाफ है वही आधे से ज्यादा समस्या खड़ी करके रखता है। जब लोग उनके पास जाते हैं, यदि उसी समय वे लोगों की बातों को ध्यान से सुन लें तो लोगों की समस्या हल हो सकती है। मंत्री जी हमें उस बिगड़े हुए स्टाफ पर कंट्रोल करने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, ज्यादा न कहते हुए मैं अपना स्थान लेता हूँ। धन्यवाद।

श्री राम किशन फौजी (बवानी खेडा–एस०सी०): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। अध्यक्ष महोदय, वित्तमंत्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी ने 2006–07 का जो बजट रखा है वह बहुत ही सराहनीय है। अध्यक्ष

महोदय, मैं बड़ी ही साफ नीयत से और ईमानदारी से इनका इसके लिए धन्यवाद करूंगा। हम पिछली बार विपक्ष में भी रहे। उस समय हमें बोलने तक का टाइम नहीं दिया जाता था जबकि आपने हर सदस्य को बोलने का पूरा समय दिया है जो कि एक बहुत ही सराहनीय कार्य है। अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूँ कि विपक्ष का काम छींटाकशी करना है, विरोध करना है लेकिन इसकी सीमा लांघ देना, हद पार कर देना बिलकुल ठीक नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी के आदेश से वित्तमंत्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी ने हर चीज के बारे में ध्यान दिया है। ओम प्रकाश चौटाला जी की पार्टी के सदस्य कह रहे थे कि शिक्षा का बजट थोड़ा है, इसका बजट थोड़ा है उसका बजट थोड़ा है। मैं उनको बताना चाहूँगा कि उनके समय में इनके लिए जो बजट होता था वह बहुत कम होता था। चाहे वह ट्रांसपोर्ट के लिए हो या चाहे वह पब्लिक हैल्थ के लिए हो, उसका आधा बजट हमेशा उनके परिवार में चला जाता था। लेकिन हमारी सरकार की नीयत साफ है कि जो भी बजट है उसमें दलाली न हो, कोई एजेंट न हो। यह बजट सीधा गांवों के अंदर, पंचायतों के अंदर या शहरों के अंदर जाए और वहां पर काम हों। हमारे अधिकारी ईमानदारी से काम करते हैं यह एक बहुत ही सराहनीय कार्य है। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने तो विरोध ही करना था चाहे आप पूरे वर्ल्ड का बजट लाकर दे दो। उन्होंने तो एक ही बात कहनी है कि बजट थोड़ा है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने 1600 करोड़ रुपये बिजली के बिलों के माफ करके एक बहुत ही अच्छा फैसला किया है। किसान बहुत दिनों से कर्जे के

नीचे दब गये थे उनको इसकी चिन्ता रहती थी इसलिए उनको रात को नींद नहीं आती थी। ओम प्रकाश चौटाला की पिछली सरकार ने लोगों को गुमराह किया था और कहा था कि बिजली के बिल न भरी। किसानों को एक ही चिन्ता रहती थी कि अगर बिल नहीं भरे तो उनकी जमीन कुड़क हो जाएगी 1 लेकिन हमारी सरकार ने जो यह फैसला लिया है इससे किसान खुश है। हमारी सरकार ने हिन्दुस्तान के अंदर ही नहीं बल्कि वर्ल्ड के अंदर इस तरह का फैसला करके अच्छा काम किया है। अब किसान के घरों में दोबारा दीवा जलने लगा है। इसी तरह से हमारी सरकार ने 600 मेगावाट का प्रोजैक्ट यमुनानगर में कोयले पर आधारित लगाने का फैसला किया है, 1065 मेगावाट का प्रोजेक्ट फरीदाबाद में, एक हजार मेगावाट का गैस पर आधारित झजर में, 1080 मेगावाट का हिसार में और 600 मेगावाट का पानीपत में लगाने का फैसला किया है। इसी तरह से हमारी सरकार ने 17 नये सब–स्टेशन स्थापित किए हैं और 80 सब–स्टेशंज की कैपेसिटी बढ़ायी गयी है तथा 65 नये ट्रांसफामर्ज लगाये गये है। स्पीकर साहब इन्दौरा जी इस समय यहां पर नहीं हैं उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रोजैक्ट तो तैयार कर लिए और इनके लिए स्कीम भी बना ली लेकिन इनके लिए गैस कहां से मिलेगी। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि इनको इसके लिए क्यों चिंता है। चिंता होनी चाहिए तो हमें होनी चाहिए। जब हमारे मुख्यमंत्री जी ने फैसला कर दिया कि नये पावर प्लांटस चलाएंगे तो यह हमारी सरकार ने सोचकर ही फैसला लिया है यह चिन्ता उनको है कि वे कहां से इनके लिए

गैस लाएंगे, कहां से इनके लिए कोयला लाएंगे। इसका प्रबन्ध तो हमारी सरकार ने करना है। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष का एक ही मकसद है कि उन्हें तो केवल विरोध ही करना है लेकिन उनके पास विरोध करने के लिए भी कुछ नहीं था। अध्यक्ष महोदय, जहां तक शिक्षा की बात है। शिक्षा के बारे में मैं यह कहना चाहूँगा कि इसमें अब बहुत सुधार हुआ है। हमारी सरकार आने के बाद मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से शिक्षा मंत्री जी ने शिक्षा में बहुत काम किए हैं। अभी स्कूलों में जो घटना घटी हैं तो यह घटना भी इसलिए घटी हैं क्योंकि पिछली सरकार ने ऐसे शिक्षक भर्ती कर लिए थे जोकि दिन में भी शराब पीकर स्कूलों में जाते थे। उनको कुछ आता जाता नहीं था। वह स्कूलों में न जाकर सरपंच के घर में या एजेंट के घर में जाकर सो जाते थे। उनकी नीयत खराब थी। इसलिए मेरा सुझाव है कि हम अच्छे शिक्षक भर्ती करें। हमारी सरकार ने महिलाओं की तरफ बहुत ध्यान दिया है। अगर लड़कियों के स्कूलों के लिए जैंटस टीचर न भर्ती करके लेडी टीचर भर्ती किए जाएं तो यह उनके लिए ठीक रहेगा। लड़की–लड़की की बात मानती है। इस बारे में मेरा सुझाव है कि छठी कक्षा से दसवीं और बारहवीं कक्षा के स्कूलों में सिर्फ महिलाएं ही टीचर होनी चाहिएँ। अगर स्कूलों में महिलाएं ही टीचर होंगी तो इससे मां–बाप का विश्वास और ज्यादा बढ़ेगा और वे अपनी बेटियों को स्कूलों में ज्यादा से ज्यादा भेजेंगे। इससे स्कूलों में लड़कियों के पढ़ने का सरकार का ग्राफ भी बढ़ेगा और शिक्षा के प्रति लोगों की भावना भी बढ़ेगी। चौटाला साहब के

समय तो स्कूलों में ऐसे हालात पैदा कर दिए गए थे कि उनकी वजह से आज सारे सदन का सिर शर्म से झुक जाता है। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस बारे में जरूर विचार किया जाए। सरकार ने बच्चों को पड़ाने के लिए स्कूलों में जो ज्यों और डैस्क का इन्तजाम किया है इसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहूँगा क्योंकि पहले तो फर्श भी नहीं मिलते थे। मैं इसके लिए शिक्षा मंत्री जी से एक आग्रह भी करना चाहूँगा कि इसके लिए ऐसा फर्नीचर खरीदा जाए जो कि दस– पंद्रह साल तक चल सके क्योंकि पिछली सरकार के समय में इस काम को ठेके पर दे दिया गया था। उस समय बीच में जो दलाल होते हैं, वे कमीशन खा गये और इन सामानों के मैटीरियल में गड़बड़ करके ऐसे स्कूल और डैस्क सप्लाई किए गए कि दो बच्चों से ज्यादा अगर एक भी बच्चा उस पर बैठ जाता है तो वह स्कूल टूट जाता है। इसलिए इस बारे में सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए जहां आप 3000 रुपये खर्च कर रहे हैं अगर वहां पर 100 रुपये और ज्यादा खर्च कर देंगे तो चीज अच्छी आ सकती है। इसलिए सरकार को मेरी इस प्रार्थना पर विचार करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा टाईम नहीं लूंगा। अब मैं सिंचाई के बारे में कहना चाहूँगा। मैं माननीय सिंचाई मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने कोशिश की है कि जहां पर पिछले 40 साल से पीने का पानी और नहर का पानी नहीं पहुँचता था वहाँ पर हमारी सरकार बनने के बाद आज आखिरी टेल तक

पानी पहुँचा है। पिछली सरकार के समय जहाँ ३ दिन भी नहरों में पानी नहीं चलता था वहीं आज महीने में 14 दिन तक नहर का पानी चलता है। लोगों के अन्दर एक खुशी है लोग कहते हैं कि श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने मुख्यमंत्री बनने के बाद इस धरती पर पानी पहुंचाया है पहले तो ऐसा हम सोच भी नहीं सकते थे। सिंचाई मंत्री महोदय ने सुन्दर नहर की लम्बाई ज्यादा करने का एक सराहनीय कार्य किया है। इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि सुन्दर नहर 30–35 साल पुरानी है उस समय इसको 600 क्यूसिक पानी मिलता था। लेकिन उसके बाद इस नहर में से कई माईनर बन गये, कई पीने के पानी की डिग्गिया बन गई और कई मौधे सिंचाई के लिए लगा दिए गए लेकिन इस नहर की पानी की कैपेसिटी आज भी 600 क्यूसिक ही है जिसके कारण टेल तक पानी नहीं पहुँच पाता। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूँगा कि इस नहर की कैपेसिटी कम से कम 950 क्यूसिक की जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूँ कि इस नहर पर अब सरकार ने अच्छे तरीके से नए मौधे लगाए हैं लेकिन पिछली सरकारी के समय लोगों ने इस नहर पर खाल बनाकर मनमर्जी के मौधे लगा लिये थे और कई मौधों के बारे में अधिकारियों ने गलत रिपोर्ट देकर सरकार को गुमराह किया था। मैं यह मानता हूँ कि जमीन के हिसाब से कमाण्ड एरिया को पानी मिलता है। अगर किसी कमाण्ड एरिया के मौधे का साईज 6 इंच है तो जमीन के हिसाब से पानी मिलता है कि इतनी जमीन होगी तो इतना पानी मिलेगा।

Mr. Speaker: Fauji Sahib, you may please conclude your speech.

श्री रामकिशन फौजीः अध्यक्ष महोदय, मौधा तो नहर पर 6 ईच का लगा दिया लेकिन किसानों को 6 इंच के साईज के हिसाब से पानी नहीं मिला। किसान तो वह पानी मानता है जो उसको डिसचार्ज पर मिलता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री महोदय को बताना चाहूँगा कि जो 8 –8 फिट लंबे मौधे लगाये हैं उनमें से एक घंटे से ज्यादा पानी नहीं चलता। क्योंकि आधी या हवा चलने से छोटी लकड़ी आदि नहरों में गिर जाती हैं और मौधों से पानी भवरी बनकर निकलता है जिसके कारण लकड़ी मौघों में फंस जाती है और पानी निकलना बंद हो जाता है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूँगा कि जो वे मौघे लगाए गए हैं वे कामयाब नहीं हैं, उन पर दोबारा से विचार किया जाये। अध्यक्ष महोदय, अब मैं पीने के पानी के बारे में कहना चाहूँगा कि हमारी सरकार ने पीने के पानी के लिए अच्छे सुधार किए हैं। हमारे मुख्यमंत्री महोदय की नियत और नीति साफ है और वे ईमानदार आदमी हैं। हमारी सरकार के समय में पीने के पानी की सप्लाई करने के लिए 18 बड़ी–बड़ी डिग्गियाा बनाई गई हैं। जिसके कारण 674 गांवों में और 22 शहरों में पेयजल आपूर्ति बढ़ाई गई है और 421 हरिजन बस्तियों में पेयजल आपूर्ति में सुधार किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के के भौजराज और धवाना गांवों में भी पानी की डिग्गिया बनाई गई हैं जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री महोदय

को धन्यवाद करता हूँ। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमंत्री महोदय, के ध्यान में लाना चाहूँगा कि मेरे हल्के के खानक कंवारी, नलवा, रतेरा आदि गांवों में पीने के पानी की अभी भी दिक्कत है। खानक के पहाड़ों में 15 से 20 हजार आदमी काम करते हैं जिनके लिए पीने के पानी की अभी कोई व्यवस्था नहीं है। हमारी सरकार ने कोशिश की है लेकिन वहां अभी भी पीने के पानी की दिक्कत है इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करूँगा कि वहां पीने के पानी की उचित व्यवस्थ की जाये। अध्यक्ष महोदय, मुझे मालूम है कि समय बहुत कम है मैं अपनी बातें लिखकर भेज दूंगा लेकिन एक दो बातें जरूर कहना चाहूँगा कि कल शहीदी दिवस था और यह बड़े गौरव की बात है कि हमने शहीदों को याद किया। जो देश शहीदों को याद नहीं करता वह देश आगे नहीं बढ़ सकता। मुख्यमंत्री जी अभी सदन में नहीं बैठे, दूसरे सभी साथी और मंत्रीगण बैठे हुए हैं और मुख्यमंत्री जी अपने कैबिन में मेरी बात सुन रहे होंगे कि शहीदों और सैनिकों की पैंशन और तनख्वाह आदि हमारे मुख्यमंत्री जी ने बढ़ाई हैं और उनको पूरा मान सम्मान दिया है। लेकिन एक फौजी होने के नाते मैं मांग करता हूँ कि हर सरकारी आफिस के अंदर जो हमारे शहीद भगत सिंह जी हैं या जो दूसरे शहीद हैं जिन्होंने देश की आजादी के लिए फांसी के फंदे को हँसते– हँसते चूम लिया उनकी फोटो जरूर लगनी चाहिए जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी की, प्रधानमंत्री जी और गवर्नर साहब आदि की तस्वीरें लगी हुई हैं। यदि हम ऐसा करेंगे तो लोगों का मनोबल बढ़ेगा। क्योंकि यदि कोई अधिकारी गलत

काम करता है तो उसको जनता कहेगी कि तुम गलत काम कर रहे हो, तुम इन शहीदों को याद करो जिन्होंने निस्वार्थ भावना से देश के लिए लड़ाई लड़ी थी और देश को आजादी दिलवाई थी 1 यदि तुम गलत काम करोगे तो उनकी आत्मा दुःखी होगी। उनकी आत्मा को शांत करने के लिए देश को आगे बढ़ाने के लिए तुम ठीक काम करो। **श्री अध्यक्षः** फौजी साहब, प्लीज अब आप बैठें। दूसरे सदस्यों को भी समय देना है। श्री राम किशन फौजी अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट और लूँगा कि हमारे सिवानी के क्षेत्र में पिछले 5–6 साल से सूखा पड़ता रहा है। हमारी सरकार ने द्या खरीदने के लिए पैसा दिया है लेकिन कम रह गया। वह टीब्बे का एरिया है और उस एरिया में ग्राउंड वाटर ठीक नहीं है और बरसात न होने के कारण वहां के किसानों की चने की फसल बिलकुल बरबाद हो गई है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि वहां गिरदावरी करवाकर किसानों को उचित मुआवजा दिया जाये ताकि किसानों को राहत मिल सके और किसान खुश होकर हमारी सरकार को दुआ देंगे तथा भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमारी सरकार आगे 20 साल तक चले। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

13.00 बजे

सरदार परमवीर सिंह (टोहाना): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं मुख्यमंत्री जी को और वित्तमंत्री जी को भी बधाई

देता हूँ कि प्रदेश की जनता के लिए हमारी सरकार बहुत अच्छा बजट लेकर आयी है। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने जो इम्पोर्टेंट सैक्टर हैं जैसे शिक्षा, हैल्थ और रोड्ज आदि के लिए बजट में जिस हिसाब से पैसे का प्रावधान किया है वह काबिले तारीफ है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि अर्बन एरियाज में, गरीब बस्तियों में और कालोनियों में और अधिक पैसा देने की जरूरत है। जो गरीब बस्तियों हैं वहां –पर बेसिक एमिनिटीज देने के लिए कार्यवाही की जानी चाहिए। वहां पर भी सीवरेज, स्ट्रीटलाइटस तथा रोड्ज बनाई जानी चाहिएं। अध्यक्ष महोदय, मैं टोहाना शहर की भी बात कर रहा हूँ। दूसरे गौतम साहब की बात का भी मैं थोड़ा सा जवाब देना चाहता हूँ। उन्होंने यह कहा कि इस सरकार ने किसानों के गिद्दा कुछ नहीं किया, किसानों की हालत खराब कर टी है। स्पीकर सर, किसानों के लिए इस सरकार ने इतने थोड़े से टाइम में जो कार्य किए हैं कोई भी सरकार कर ही नहीं सकती। किसानों के 16०० करोड़ रुपये के बिजली के बिल मुआफ करके पिछली गवर्नमैंट के झूठ का बोझ किसान के कंधे से उतारा था यह किसानों की भलाई के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है। अध्यक्ष महोदय, जो किसान अपने लोन की रिकवरी नहीं दे पाते थे वे अरेस्ट हो जाते थे उन किसानों को रिकवरी अदा न कर सकने की सूरत में अरैस्ट करगे से रोकना किसान के हित में बहुत बड़ा कदम है। अध्यक्ष महोदय, इससे पिछली सरकार जो खुद को किसानों की सरकार कहलाती थी वह किसानों की ट्रैक्टर की रजिस्ट्रेशन की फीस तक मुआफ नहीं कर सकी। इस सरकार

द्वारा किसानों के ट्रैक्टर की रजिस्ट्रेशन फीस मुआफ करना किसान के हित की बात है। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से पिछली सरकार ने कुछ शुगर मिलों को बन्द करवाने का जो फैसला किया था हमारी सरकार ने किसानों के इन्ट्रस्ट में उन शुगर मिलों को चलवाने का निर्णय किया है जो कि किसान के हित में बहुत बड़ा कदम है। अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलते हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। यहां पर राजीव गांधी और इन्दिरा गांधी जी का नाम लिया गया है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि राजीव गांधी जी, इन्दिरा गांधी जी और सरदार बेअन्त सिंह जी कांग्रेस के वे लीडर्ज हैं जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियां दीं। बी०जे०पी० के लोगों की तरह नहीं जिन्होंने सत्ता प्राप्त करने के लिए लोगों की कुर्बानियां लीं 1 बी०जे०पी० के नेताओं ने गुजरात और अयोध्या में कॉम्युनल टैंशन पैदा करके खून खराबा करवाया। बहुत सारे लोगों की कुर्बानियां लेकर, अनेकों सिर लेकर इन्होंने सरकारें बनाई। दूसरी तरफ कांग्रेस के लीडर्ज हैं जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही बोलना चाहता था आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री राम कुमार गौतमः अध्यक्ष महोदय, ...

श्री अध्यक्षः गौतम साहब, आप अपनी सीट पर बैठें। (विघ्न) नहीं, आप कोई भी जवाब न दें और अपनी सीट पर बैठें। (विघ्न) आपको बोलने के लिए पूरा टाइम मिला है इसलिए अब आप बैठें। (विघ्न) गौतम साहब बिना परमिशन के बोल रहे हैं

इसलिए इनका कुछ भी रिकॉर्ड न करें। (विघ्न एवं शोर) गौतम साहब, आप बैठें। ऑनरेबल मैम्बर्ज, अब मेरे पास ऐसी कोई पर्ची नहीं है जो मैम्बर्ज बजट पर या डिमाण्ड पर या ऐप्रोप्रियेशन बिल पर न बोले हों। एक भी मैम्बर ऐसा नहीं है। कुछ मैम्बर्ज दोबारा बोलना चाहते हैं लेकिन मैं उनसे मुआफी चाहूँगा। अमीर चन्द मक्कड जी, गीता भुक्कल जी, रमेश गुप्ता जी, रणधीर सिंह जी, भारद्वाज साहब, यादव साहब, निरपेन्द्र सांगवान जी, जौनपुरिया जी ऐसे मैम्बर्ज हैं जो दोबारा बोलना चाहते हें लेकिन समय को देखते हुए मैं उनसे मुआफी चाहूँगा। Now I will request honorable Finance Minister to please give the reply.

वित्त मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह) अध्यक्ष महोदय, मैं सभी ऑनरेबल मैम्बर्ज का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बजट पर और फिर ऐप्रोप्रियेशन बिल पर अपने विचार रखे और अपने सुझाव भी दिए। स्पीकर साहब, मैं आपको एक बात जरूर कहूँगा कि यह ठीक है कि आपने सभी बोलने वाले मैम्बर्ज को बोलने का टाईम दिया लेकिन परम्परा के मुताबिक डिमाण्ड्ज पर बोलना उतना ही आवश्यक है। जिस तरह से आज जनरल डिस्कशन हुई है और मैम्बर साहेबान बजट पर और ऐप्रोप्रियेशन बिल पर बोले। लोकसभा में भी ऐसी प्रॉब्लम आई थी जो आपको भी फेस करनी पड़ रही थी। टाईम की कमी की वजह से लोक सभा में तो पिछले 10– 12 साल से यह प्रथा अपनाई गई है कि हाउस की रिसैस हो जाती है और 20–22 दिनों की छुट्टी हो जाती है। जो स्टैंडिंग कमेटीज हैं वे डिमांड पर फिर अपनी मीटिंग्ज करके हाउस और

स्पीकर को अपनी रिक्यैंडेशन्ज देते हैं। उसमें जब अपनी– अपनी मीटिंग्ज में अपनी–अपनी डिमांडज पर जवाब देते हैं तो मैम्बर्ज को बहुत समय मिल जाता है। लेकिन यहां पर मैम्बर्ज अपनी कांस्टीचुएंसी के बारे में बात करते हैं। उनको भी अगर डिमांडज पर बोलने का मौका मिल जाए तो वे अपनी बात को वहीं तक कन्फाईन करेंगे। अध्यक्ष महोदय, आपने तो सुधार करने के प्रयास किए हैं, जैसे आपने औरियंटेशन प्रोग्राम शुरू किया है। स्पीकर सर, मेरे हिसाब से तो अभी और औरियंटेशन प्रोग्राम शुरू करने की जरूरत है। स्पीकर सर, ग्रैजुअली अगर यह सिस्टम सुधर जाए तो आज जो हरियाणा का नाम इस बारे में लिया जाता है कि यहां पर हाउस की सबसे कम सीटिंग्ज होती हैं अध्यक्ष महोदय, इस बारे में मैं कहना चाहूँगा हमने इसमें सुधार किया है और पिछले एक साल में हमने पांच बार सैशन बुलाया है और यह एक अच्छी परम्परा पड़ी है। लेकिन फिर भी कुछ एब्रेशन हैं, कुछ कमियां हैं और वे भी आपके निर्देशन पर और आपके आदेश पर दूर हो सकती हैं। हम तो सिर्फ उस पर प्वायंट आउट ही कर सकते हैं ताकि मैम्बर्ज का जो बोलने का अधिकार है वह सुरक्षित रह सके। स्पीकर साहब आपने एप्रोप्रिएशन बिल पर 12 या 13 मैम्बर्ज को बोलने का मौका दिया है और हमारे साथियों ने उस पर भी सुझाव दिए हैं। रामकुमार गौतम जी को दो बार बोलने का मौका मिला है और इनकी जो बोलने की शैली है उसमें इतना सुधार है कि मुख्यमंत्री और मेरी तरफ इशारा करके हमारी पार्टी के ऊपर आक्षेप करने की कोशिश करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना

चाहूँगा कि आज हम जो कुछ भी हैं वह अपनी पार्टी की वजह से हैं। अपने नेता की वजह से ही हैं किसी और की वजह से नहीं हैं। स्पीकर सर, अगर आप कल की ही घटना को ही लें तो यह अपने आप में एक अनप्रैसिडैंट बात है। स्पीकर सर, जिस प्रकार से अखबारों में और इलैक्ट्रानिक मीडिया में यह बात आई कि श्रीमती सोनिया गांधी के खिलाफ एक आरडिनैंस आ रहा है हाउस को प्रोरोग करने की बात की जा रही है तो हाउस को एकदम से एडजर्न कर दिया गया। उस महान नेता ने उसी वक्त अपने पद से अपनी लोकसभा की सीट से इस्तीफा दे दिया। अध्यक्ष महोदय, इतिहास में इससे पहले कोई घटना ऐसी हो नहीं सकती है। हमें गर्व है तभी हम चाहते हैं कि हमारे नेता का नाम जो भी ले श्रद्धा से ले। अध्यक्ष महोदय, वैचारिक मतभेद किसी के भी हो सकते हैं, आपके भी हो सकते हैं और हमारे भी हो सकते हैं क्योंकि सब अलग– अलग पार्टीज के हैं। लेकिन हमारे मन में चाहे कोई भी नेता हो जो हमारी पार्टी से संबंधित नहीं है उनके प्रति भी कोई दूर्भाव नहीं है। हम उनको भी अपना आदर्श मानते हैं क्योंकि देश के लिए वे अपने दृष्टिकोण से काम करते हैं। उनकी बात को हम कभी इसलिए नहीं झुठलाते हैं कि हम सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करते हैं। हमारे दोस्तों ने सही कहा है, कैप्टन साहब ने कहा, सतविन्द्र राणा ने कहा है कि कल की घटना स्वतंत्रता के बाद का इतिहास है। अगर इसमें हम झांक कर देखें तो पाएंगे कि जहां देश की रक्षा करने के लिए हजारों सैनिकों का बलिदान हुआ है, वह चाहे पाकिस्तान से युद्ध हुआ है, चाहे पीस कीपिंग फोर्स

लंका में गई हो या दूसरी आतंकवादी घटनाओं में हमारे सैनिकों को बलिदान देना पड़ा है। लेकिन अगर राजनीति में, और राजनीति में भी राष्ट्रीय स्तर का कम्पैरीजन करें तो आपको आभास होगा कि 1964 में कैनेडी की दुर्घटना हुई थी, उनकी असेसिनेशन अमेरिका में हुई थी और उसके बाद में श्रीमती इन्दिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ था। उन्होंने राष्ट्र की एकता के लिए अपना बलिदान दिया है। अध्यक्ष महोदय, राजीव गांधी जी का जो असैसिनेशन हुआ था वह भी इसलिए हुआ था क्योंकि उन्होंने पीस कीपिंग फोर्स श्री लंका में भेजी थी और इसी वजह से उन्हें बहुत सी थेंट्स भी दी गई थीं कि अगर आप श्रीलंका को नहतईं संभाल सकते तो हम वहां पर अपने अड्डे बना सकते हैं। उस समय इजरायल और दूसरे कंट्रीज ने इस तरह की बातें की थीं। राष्ट्र के स्ट्रेटिजिकल इन्वौयरर्नमैंट को स्वस्थ रखने के लिए राजीव गाधी को अपना बलिदान देना पड़ा। ये दोनों घटनाएं कोई साधारण घटनाएं नहीं हैं बल्कि असाधारण घटनाएं हैं। एक्ट्रा आर्डीनरी सिचुएशन में इतना बड़ा बलिदान हमारे नेताओं ने दिया और यही बात है जो हमारे नेताओं को आज भी प्रेरित करती है, स्पीकर सर, एक समय में श्रीमती सोनिया गांधी को यू०पी०ए० का यूनानीमसली अध्यक्ष चुन लिया गया था लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री पद स्वीकारा नहीं था। इसी प्रकार से कल जब मीडिया में थोड़ी सी बातें आयीं तो उन्होंनें अपने पद से इस्तीफा दे दिया और साथ ही यह भी कह दिया कि मैं रायबरेली से चुनाव भी लड़ूगी। इस तरह से राजनीति के अंदर हमारी पार्टी ने मान्यताओं को

निभाया है और हमेशा हम उनको आगे भी निभाते रहेंगे। हम ऐसा नहीं करते जिस तरह से बी०जे०पी० के नेता करते हैं। अयोध्या के केस में बी०जे०पी० के बड़े–बड़े नेता चार्जशीट हुए लेकिन फिर भी वे मंत्रिमंडल में बने रहे। इसी तरह से जार्ज फर्नांडीज के बारे में उस समय के प्रधानमंत्री ने यह कहा कि जब तक वे इंक्वायरी में साफ नहीं होंगे तब तक हम उनको मंत्रिमंडल में नहीं लेंगे लेकिन उनको मंत्रिमंडल में लिया गया। रिपोर्ट आने तक एक डेढ़ साल तक वे मंत्रिमंडल में रहे। इसी तरह से आडवाणी जी तो चार्जशीट होने के बावजूद भी होम मिनिस्टर तक रहे। स्पीकर साहब, मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि किसी के बारे में कुछ कहने से पहले अगर हम अपने गिरेबान में झांककर देखें तौ फिर दूसरों की इज्जत करना सीखेंगे। हमारी पार्टी का इतिहास राजनीतिक परम्पराओं का निर्वहन करने में रहा है। अगर मैं यह कहूं कि कोई और राजनीतिक पार्टी ऐसी नहीं हो सकती जैसा हमारा राजनीतिक दल है और जैसे हमारे नेता हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है। हमें इन पर गर्व है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहूँगा कि सुभाष चौधरी जी ने बोलते समय एक मांग रखी थी जिसके बारे में शायद आपको पता भी होगा कि जो पोपूलर और यूकेलिप्टस है उसको ऐग्रीकल्चर प्रोड्यूस टूटि किया जाए। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने सही कहा कि 6 परसैंट जो बिचौलिये कमीशन लेते हैं वह न तो सरकार को जाता है और न ही मार्किटिंग बोर्ड को जाता है यानी उसका किसी को लाभ नहीं है। मैं उनको इस बारे में कहना चाहूँगा कि We are already of the matter. इस बारे

में उचित कार्रवाही चल रही है और उसके अच्छे ही परिणाम होंगे। हम खुद मानते हैं कि अगर प्लाइवुड इंडस्ट्रीज को बचाना है तो हमें पोपूलर और यूकेलिप्टस को ऐग्रीकल्चर प्रोड्यूस मानकर चलना ही पड़ेगा। इसके लिए हमारी सरकार प्रयासरत है और हम यह मानते भी हैं कि अगर प्लाईवूड इंडस्ट्रीज का कोई सबसे बड़ा केन्द्र है तो वह यमुनानगर है। इसको बचाने के लिए और इसको आगे बढ़ाने के लिए हमारे पूरे प्रयास रहेंगे। यह हमारी सरकार की वचनबद्धता है। हम ऐसा नहीं करते जैसा पिछली सरकार के समय मे हुआ। जैसा मुझे इस बारे में बताया गया है उसको सुनकर मुझे शर्म आती है। उस समय के वहाँ के एम०एल०ए० ने खुद चंदा इकट्ठा करके और बैग में पैसे डालकर कार से यहां पर ऐग्रीमेंट करने आये कि कि हमारे से लमसम ऐग्रीमैंट कर लें हम तैयार हैं। बाद में जब पता चला कि जितनी राशि मंगायी गयी थी उससे यह तीस लाख रुपये कम है तो उस समय उस कार को इंटरसैप्ट कराया गया।

अति विशिष्ट व्यक्ति का स्वागत

श्री अध्यक्ष: ऑनरेबल मैम्बर्ज, केन्द्रीय सरकार के यूनियन लॉ मिनिस्टर और अभी जो हरियाणा प्रदेश से राज्य सभा के सदस्य चुने गये हैं, माननीय श्री एच०आर० भारद्वाज, वे वी०आई०पी० गैलरी में हमारे बीच में हैं। मैं अपनी तरफ से और सदन की तरफ से उनका स्वागत करता हूँ। (मेजे थपथपाई गईं)

दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (नं० 2) बिल, 2006 (पुनरारम्भ)

वित्त मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह): सर, मैं किस्सा बता रहा था। यानि इस किस्म की घटनाएं हुई हैं और फिर ये कहा कि वे दोबारा सत्ता में आने की बात सोच सकते हैं कोई भी आ सकता है। लेकिन ऐसे लोगों को हरियाणा की जनता समझ गई हैं वह कभी उनको माफ नहीं करेगी. जिस प्रकार सै उन्होने हर वग को लूटा, सताया है, बे–इजती की हैं इस तरह से तो कुख्यात अपराधी भी नहीं करते। ऐसी प्रवृत्ति तो वे भी नहीं रख्ते जिस प्रवृत्ति के ये लोग धनी थे। हमें कई बार राजनीति में ऐसी बातें सुनकर शर्म आती है। मैं कह रहा था कि उद्योगों को बचाने के लिए भरसक प्रयास किए जाएंगे। इसके साथ–साथ श्री सुभाष चौधरी जी ने कहा कि म्यूनिसिपल कमेटी, जगाधरी का हरियाणा पुलिस को एक करोड़ 82 लाख रुपया देना है। इसके बारे में मैंने होम डिपार्टमेंट से पता किया है। उन्होंने बताया है कि पुलिस डिपार्टमेंट ने यह कहा है कि चूंकि एक्सटर्नल डिवैल्पमैंट का कार्य उन्होंने खुद किया है इसलिए एक करोड़ 82 लाख रुपये म्यूनिसिपल कमेटी को देने का उनका हक नहीं बनता। इसलिए इस स्थिति से मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूँ। ऐसे ही इन्होंने 56 एकड़ जगह के लिए जो अढ़ाई करोड़ की राशि से भी ज्यादा राशि का जिक्र किया उसके बारे में लेटैस्ट पोजीशन यह है कि पुलिस महकमा इस बात को नहीं मानता कि म्यूनिस्पिल कमेटी को एक्सटर्नल डिवैल्पमैंट चार्जिज दिए जाएं। दूसरी बात श्री बचन

सिंह आर्य जी ने यह कही कि पूरे प्रदेश में विकास के कार्य चल रहे हैं। खासतौर से उन्होंने अपने इलाके के बारे में कहा। श्री आर्य जी ने अपने इलाके में पानी की रिचार्जिंग के बारे में कहा है। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जो नई नहर आयेगी उससे उनके इलाके को फायदा होगा क्योंकि रिचार्जिंग के हिसाब से वहां का इरीगेशन का एरिया भी बढ़ेगा और डैनसिटी भी बढ़ेगी। इसी प्रकार से श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मान जी ने कई मुद्दे उठाये। उन्होंने मूलभूत ढांचें की बात कही। चाहे वह पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंट की बात हो चाहे इलैक्ट्रिसिटी की बात हो, इन विभागों में अधिकारी तो शायद पूरे होंगे लेकिन जो लोअर स्टाफ है वह फील्ड में काफी कम है। इस बारे में सरकार ध्यान दे रही है। गौतम जी कहेंगे कि जो रिट्रेंचमैंट किए हुए इम्प्लाइज हैं उनके लिए भी कुछ कीजिए उनको भी न्याय दिलायें। दूसरी तरफ इन्होंने कहा कि बजट का नॉन प्लान एक्सपैंडीचर बढ़ गया है और घाटे का बजट पेश किया गया है। मैं यह बात खुद मानता हूँ कि जो सरकार यह निर्णय लेती है कि छोटे कर्मचारियों की छंटनी करके, उनका साइज थोडा करके या सिर्फ कर्मचारियों को हटाकर अगर उस सरकार की ऐफीशिएसी बढ़ जाएगी या सरकार का घाटा कम हो जाएगा तो यह बात मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। ऐसा करने से तो उन लोगों के साथ बेइन्साफी होगी। रिट्रेंचमैंट के नाम से नौकरी पर ताला लगाकर जो आप अपना सुधार करना चाहते हैं मैं उसको सुधार नहीं मानता। आपको याद होगा कि वर्ष 1993 से बिजली बोर्ड जिसकी अब चार यूटीलिटीज बना दी हैं

उसमें आज तक कोई भर्ती नहीं हुई है। जब हम अधिकारियों और इंजीनियर्स से बात करते हैं तो वे कहते हैं कि आज तीन ए०एल०एम० की जगह एक ए०एल०एम० काम कर रहा है। इस प्रकार की स्थिति में सरकार के काम में ऐफीशिएसी आए मैं नहीं समझता कि आ सकती है। This myth is being created by the bureaucracy. We must admit it. वे कहते हैं कि साहब आप छंटनी कर दें, कर्मचारियों को घटा दो तो बड़ा रिलीफ मिलेगा। लेकिन हम इस बात से सहमत नहीं हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है कि भर्ती के मामले में ये बातें हैं इनको हम अपना बैच मार्क नहीं मानेंगे और हम लोगों को रोजगार देंगे। ऐसा हमने वादा भी किया था और यह हमारा कर्त्तव्य भी है।

श्री रामकुमार गौतमः स्पीकर सर, मैं केवल चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी की एक बात का जवाब देना चाहता हूँ। ....

श्री अध्यक्षः गौतम जी, प्लीज आप बैठें। आपकी कोई बात रिकॉर्ड नहीं की जायेगी। गौतम जी, चेयर की परमिशन के बगैर जो भी बोल रहे हैं वह रिकॉर्ड न किया जाये। (शोर एवं व्यवधान) Gautam Sahib, please have patience. This is not the way. गौतम जी, प्लीज आप बैठें यह सदन की गरिमा नहीं है।

शिक्षा मंत्री (श्री फूल चन्द मुलाना): अध्यक्ष महोदय, राम के ठेकेदार केवल ये लोग नहीं हैं। (शोर एवं व्यवधान) जब मस्जिद गिराई गई थी उस समय एक शायर ने लिखा था कि–

अपने पौसीदा इरादों को यों न नंगा करो,

ये कहीं बदनाम न कर दें, हमारे राम को।

अध्यक्ष महोदय, राम केवल इनका नहीं है। हम सबका है और जो भी इन्होंने ये गलत वर्ल्ड यूज किए हैं वे हाउस की कायवाही से निकलवा दिये जाएं।

श्री अध्यक्षः मुलाना जी, वह तो रिकॉर्ड ही नहीं किया गया। (शोर एवं व्यवधान)

राव दान सिंहः अध्यक्ष महोदय, मेरे सम्मानित साथी तो चले गये। यें ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। मेरे साथी यह सुन नहीं पाये कि आज हिन्दुस्तान के प्रजातंत्र के अंदर कितने उच्च आदर्शों को सोनिया गांधी जी ने प्रतिपादित किया है। इनके बारे में मैं इनता ही कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने कफन पर कमीशन खाई हो, जिन्होंने आतंकवादियों को हवाई जहाज पर घुमाया हो। इस देश की ओर प्रदेश की जनता ने यह सब अपनी आंखों से देखा है। उस समय किसी शायर ने इनके बारे में कहा है जो बात इन पर लागू होती है कि—

जमीं बेच देंगे, जमा बेच देंगे,

मुर्दा सिरों का कफन बेच देंगे,

ऊपर बैठे कलम के सिपाहियों से कहना चाहता हूँ कि—

अगर कलम के सिपाहियों तुमने नहीं देखा तो,

भाजपा व एन०डी०ए० के लोग वतन बेच देंगे।

श्री बीरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी ने जिस भाषा का प्रयोग किया उसको आपने कार्यवाही से निकाल दिया लेकिन इससे इनकी मानसिकता का पता लगता है। हमारे दिल बहुत बड़े हैं इसी पर मैं एक शेर सुनाना चाहता हूँ–

वो तो झलकी थी किसी कन्तर्फ के पैमाने से,

मेरे पैमाने में तो महखाने समां जाते हैं।

मेरे ये साथी तो छोटी सोच के प्रतीक हैं।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा): अध्यक्ष महोदय, चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी ने और साथी राव दान सिंह जी ने उनके लिए ठीक ही कहा है। ये राम के पुजारी हैं इसमें कोई दो राय नहीं लेकिन ये कौन से राम के पुजारी है, यह देखने वाली बात है। जब केन्द्र में उनकी सरकार नहीं बनी थी तब वहीं पर मंदिर बनाने का उनका मुद्दा था। उनकी सरकार बन गई, मंत्री बन गये लेकिन मंदिर नहीं बना पाये। इससे पता लगता है कि वे केवल एक ही राम के पुजारी हैं, कुर्सी राम के पुजारी हे। (हंसी)

श्री बीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, मान साहब ने एक मुद्दा उठाया जिसका हमने अपने बजट में जिक्र किया है। वह मुद्दा है अन–इम्पलॉयमैंट एलाउंस देना तथा अन–इम्पलॉयड लोगों को

रोजगार देना। इसके साथ ही इन्होंने सबसिस्टैंस एलाउंस के लिए भी कहा है कि उनको मिले। यह हमारी सोच है और आप इस बात को ठीक मानेंगे कि 100 रुपये देना अपने नौजवान के साथ मजाक था। इसलिए हमने इस एलाउस को बढ़ाकर 300 और 500 रुपये किया है। (इस समय मेजें थपथपाई गईं) स्पीकर सर, मैं तो यहां तक कहता हूँ कि रूरल इम्पलॉयमैंट गारन्टी एक्ट जब पूरे देश के 600 के 600 जिलों में लागू हो जाएगा तो हमारे भी 20 के 20 जिले इसमें कवर हो जाएंगे। मैं आपको इस बात से यकीन दिला सकता हूँ कि उस वक्त आप देखेंगे कि हमारा जो एलाउंस है वह भी उसके लिए एक साधन बनेगा एक बैंच–मार्क बनेगा। इसमें हम यह चाहते हैं कि एलाउंस लेने वालों का सिर्फ नम्बर ही न बड़े बल्कि राशि भी बढ़नी चाहिए। स्पीकर सर, जब ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार ने यह ऐलान किया था कि हम यूथ को 100 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे तो उस वक्त सिर्फ 26 हजार लोग रोजगार कार्यालयों में अनएम्पलॉयड के तौर पर रजिस्टर्ड थे। बेरोजगारी भत्ते की एनाउसमैंट होने के बाद एक लाख से ज्यादा लोगों ने अपने नाम बेरोजगारों के रूप में रोजगार कार्यालयों में रजिस्टर्ड करवा दिए थे। उसके बाद फिर यह हुआ कि आखिरी एक साल तक सिर्फ चार करोड़ रुपये की पेमैंट ही उस वक्त की सरकार कर पाई थी। वह सरकार कोई और पेमैंट नहीं कर पाई और हमारी सरकार ने आकर उस सरकार की स्कीम को रैशनेलाईज किया है। हमारी सरकार द्वारा उसको रैशनेलाईज करने का केवल एक ही निशाना था कि जिसको भी यह एलाउंस

मिले कम से कम उसको यह महसूस तो हो कि मुझे यह पैसा सबसिस्टैंस के लिए दिया गया है, मुझे जीने के लिए दिया गया है, मुझे कोई खैरात नहीं दी गई है। इस एलाउंस के लिए मेरा हक बनता है। स्पीकर सर, हम यह मानते हैं कि जिसके पास रोजगार नहीं है उसका हक है उसको कहीं न कहीं रोजगार का साधन दिलवाया जाए। रूरल इम्पलॉयमैंट गारन्टी एक्ट में यह लिखा है कि या तो उसको पूरा अनइम्पलॉयमैंट एलाउस मिले या उसे कोई रोजगार मिले। हमारी कोशिश यही है कि जब तक उसको कोई रोजगार न मिले तब तक उसको पूरा एलाउस दिया जाए।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्षः ऑनरेबल मैम्बर्ज, यदि हाउस की सहमति हो तो हाउस का समय आधे घण्टे के लिए बढ़ा दिया जाए।

आवाजेंः ठीक है, हाउस का समय आधा घण्टा बढ़ा दिया जाए।

श्री अध्यक्षः ठीक है, हाउस का समय आधा घण्टा बढ़ाया जाता है।

दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (नं० 2) बिल, 2006 (पुनरारम्भ)

श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मानः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय फाईनैंस मिनिस्टर साहब के ध्यान में यह लाना चाहूँगा कि इस स्कीम के अन्दर बहुत से Ifs and buts हैं। जितने लोग बी०ए०

तथा मैट्रिक पास रोजगार कार्यालयों में रजिस्टर्ड हैं उन सबके लिए इस एलाउंस का प्रावधान होना चाहिए न कि कुछ चूजन वन्ज को यह एलाउंस दिया जाए।

Finance Minister (Shri Birender Singh): But the duration of the registration with one Employment Exchange should be at least 3 years. It should not be at the will of the unemployed that he should go and register himself with the Employment Exchange. We have identified those people who are waiting for their wings for the last 3 years and who are hopeful to get the employment. That is our intention. And I think-that the most corrective and genuine people would be coming forward, if this method is applied. स्पीकर सर, चौधरी भूपेन्द्र हमारे माननीय सदस्य हैं और उन्होंने भी कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं। उन्होंने भू माफिया के बारे में मुद्दा उठाया। मैं इस बात के लिए उनकी तारीफ करूँगा कि वे गुड़गांव में रहते हैं by and large, he is also M.L.A. from Gurgaon और वे रहते भी वहीं पर हैं जहां विकास हो रहा है उसमें उनका अपना इलाका भी आता है। उन्होंने कई मुद्दे उठाए हैं जिनकी जनता में भरपूर सराहना हुई है तथा लोगों ने हमारी पार्टी के बारे में कहा है कि गुडगांव में एम०एल०एज० और कांग्रेस की सरकार माफिया के साथ नहीं है बल्कि आम जनता के साथ है। उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों की चर्चा मैंने भी सुनी है उन मुद्दों के बारे में हमारा व्यू साफ है। मैं इसमें यह कहूँगा कि इस तरह की टैंडैंसी में यह सम्भव है या नहीं है लेकिन उस पर सरकार की पैनी नजर है। हमारी

सरकार ऐसी सिचुएशन को कभी एलाउ नहीं करेगी जिससे गरीब किसान या किसी ऐसे आदमी की जिसकी जमीन हो किसी प्रकार से एक्सप्लायटेशन हो। स्पीकर सर, हमारे साथी सोमवीर सिंह जी और दिनेश कौशिक जी ने भी अपनी—अपनी बातें सदन में रखी हैं। ए०सी० चौधरी जी ने मुरथल इंजीनियरिंग कॉलेज की बात कही है। उसके बारे में मैं आपके माध्यम से सदन में कहूँगा कि इस बारे में हमारे विरोधियों के द्वारा प्रचार किया जा रहा है कि मुरथल इंजीनियरिंग कॉलेज को प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है यह बिलकुल गलत बात है। हमारी एक एक्सपर्ट्स की टीम वर्ल्ड बैंक गई थी और उनकी ओपिनियन है कि जहां पर 270 एकड़ जमीन है वहां पर उस कॉलेज को खोला जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, उस कालेज को कालेज न रखकर भविष्य में उसको साईस एंड टैक्नोलोजी की यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर देंगे। यह रिपोर्ट तो मेरे पास नहीं है लेकिन मुझे इस बारे में जुबानी बताया गया है। जहां पर यह साईट देखी गई है यह बहुत ही बढ़िया और उस यूनिवर्सिटी के लिए सूटेबल साईट है। इसके साथ ही मैं यह कहना चाहूँगा कि जो एम० आर०आई० की मशीन है वह 9 करोड़ रुपये की लागत से लगती है। यह मशीन अभी रोहतक में है लेकिन सीटी स्कैन की जो मशीन है वह हम फरीदाबाद, गुड़गांव और दूसरे शहरों में लगाएगे और खास करके ट्रॉमा सैटर्ज में यह सुविधा देंगे। इसके अलावा जो सिविक बाड़ी म्यूनिसिपल कमेटी में या दूसरी कमेटीज में है उस बारे में आपको जवाब में कहा है कि हम किसी भी म्यूनिसिपल कमेटी को फंड्ज

की कमी के कारण उसके सौन्दर्यकरण, उसकी डिवैल्पमैंट और उसके इकास्ट्रक्चर को स्ट्रैंग्थन करने के काम में कमी नहीं आने देंगे। हमने एल०ए०डी०टी० 50– 50 के हिसाब से डिवाइड किया है। हमने 2 करोड़ रुपए ग्रामीण क्षेत्र में और 11 करोड़ रुपए शहरी क्षेत्र में एल०ए०डी०टी० के दिए हैं। इसी तरह से नरेश शर्मा जी ने बोलते हुए सरकार के कार्यक्रमों की सराहना की है। उन्होंने बोलते हुए कहा है कि हरियाणा में इंडस्ट्री डैजरटिड लुक देती है। मैं इनको आपके माध्यम से यह कहना चाहूँगा कि अब समय बदल गया है। अब जो उद्योगपति और इन्टरप्रेन्योर हैं वे हरियाणा की तरफ चले आ रहे हैं। हमारे हरियाणा में रैपिड इंडस्ट्री डिवैल्पमैंट की बात है तो इस वजह से इंडस्ट्रीज को बल मिलेगा। इसी तरह से सतविन्द्र राणा जी ने राजौंद हल्के के अलेवा गांव में पी०एच०सी० बनाने के बारे में कहा है तो मैं इनको यह कहना चाहता हूँ कि इस बारे में मंत्री जी ने बजट पर बोलते हुए जवाब दे दिया था और मैंने भी बजट पर हुई बहस का जवाब देते हुए बता दिया था। इसके साथ ही श्री रामकिशन फौजी जी ने कहा है कि शहीदों की फोटोज हर दफ्तर में लगे तो इस बारे में मैं इनको कहना चाहता हूँ कि हर डिस्ट्रिक्ट में पहले ही शहीदों के स्मारक बने हुए हैं और रोहतक में एक सैंट्रल स्मारक बना हुआ है। शहीदों में वे ही शामिल नहीं होते हैं जिनको हम जानते हैं लेकिन उनमें कई ऐसे शहीद भी होते हैं जिनसे हम परिचित नहीं होते हैं लेकिन स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने में वे भी शामिल थे। हमने सभी की याद में हर डिस्ट्रिक्ट में स्मारक बनाए हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय, आखिर में मैं यह कहूँगा कि हमारा जो बजट है उसमें चाहे हमारा फिस्कल इन्फ्रास्ट्रक्चर हो या सोशल सैक्टर हो उसमें हम चाहते थे कि विकास हो। अध्यक्ष महोदय, विकास के अगर कोई पहिए हैं तो वह शिक्षा हो सकती है, इंडस्ट्रियल डिवैल्पमैंट हो सकती है, कृषि हो सकती है। अगर हमें अनइम्पलाइमैंट को दूर करना है तो उसके लिए नई लेबर पालिसी हो सकती है, नई इंडस्ट्रियल पालिसी हो सकती है। ये सब हम इस बजट में लेकर आए हैं। आज जितनी आस्था हरियाणा के आम आदमी की खास तौर से व्यापारी की, उद्योगपति की और किसानों की इस सरकार में जगी है उसी का परिणाम है कि आज हमारा टैक्स कलैक्शन भी बहुत आ रहा है हालांकि यह हमने रेशनेलाइजेशन भी किया है और जो यह सोच होती थी कि इंस्पैक्टर फ्री राज हो, वह सोच भी अपने आप ही अपना वजन बढ़ा रही है। इसलिए यह हमारे लिए बहुत अच्छे साईन्ज हैं। स्पीकर सर, हम समझते हैं कि अगले सालों में विकास की रफ्तार और तेज होगी। मैं सभी मैम्बर्ज से अनुरोध करूँगा कि आप इस ऐप्रोप्रिएशन बिल को सर्वसम्मति से पास करें। अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

राजस्व मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव): अध्यक्ष महोदय, मैं भी आपकी अनुमति से एक दो क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगा। बचन सिंह आर्य ने बी०एम०एल० हांसी बुटाना ब्रांच के बारे में जिक्र किया और सईस शट्स के बारे में बात की। मैं इस बारे में

इनको बताना चाहूँगा कि लिफ्ट सईस सूट्स वहां पर दिए जाएंगे Either through the channel or through the well typed structure. जो कैथल जींद का एरिया है उसमें भी राईस शट्स दिए जाएंगे। दूसरी बात यह है कि आजकल बी०एम०एल० हांसी बुटाना ब्रांच के बनाने के बारे में बयानात आ रहे हैं, मैं सदन को बताना चाहूँगा कि रूड़की से इसका बाकायदा स्ट्रक्चर पास हो चुका है और यह कैनाल बनकर रहेगी। जो भी प्रोसीजर है उसको हम अपनाएंगे और अगले एक साल में यह कैनाल बनकर रहेगी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा का समान पानी के बंटवारे का जो सपना था उसके तहत ही यह नहर बनवायी जा रही है। हमारे इनेलो के कुछ साथियों के इस बारे में सदन से बाहर भ्रामक बयान आ रहे हैं और वे इस बारे में सदन को गुमराह कर रहे हैं लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि वे इसके बनाने के हक में हैं या नहीं? उनके इस बारे में बयान आने चाहिए। दूसरा मुद्दा यह था कि सतविन्द्र सिंह राणा जी ने माडीवाल माईनर, मौहम्मदपुर खेड़ा माईनर और मांडी खुर्द माईनर स्कीम्स के बारे में जिक्र किया है। हम इस बारे में ऐग्जामिन करवा लेंगे। इसके अलावा रामकिशन फौजी ने नहरों के आउटलैट्स के बारे में बात की। मैं उनको भी बताना चाहूँगा कि जहां पर गलत किस्म से ये छोटे कर दिए गए हैं तो हम इनको भी ऐग्जामिन करवा लेंगे।

शिक्षा मंत्री (श्री फूल चन्द मुलाना): अध्यक्ष महोदय, रामकिशन फौजी जी ने एक खदसा जाहिर किया कि लड़कियों के

स्कूलों में कुछ मेल .अध्यापक लगे हुए हैं। मैं उनको बताना चाहूँगा कि भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने निर्णय कर लिया है कि जो भी लड़कियों के स्कूल होंगे उसमें टीचर लेडीज ही रहेंगी और अगर कहीं पर टीचर लगाने की आवश्यकता पड़ी तो 50 साल से ज्यादा आयु के ही मेल टीचर लगाए जाएंगे। इसी तरह से इन्होंने दूसरा खदसा यह भी जाहिर किया कि स्कूलों में कुछ बैंच ऐसी हैं जिन पर अगर दो बच्चे बैठ जाएं तो वे टूट जाती हैं। अध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने निर्णय लिया है कि हाई पावर परचेज कमेटी की बिना इजाजत के कोई डैस्क नहीं खरीदी जाएगी। हाई पावर परचेज कमेटी इस बारे में टैंडर्ज मांगती है और वही इस बारे में निर्णय करती है। बाकायदा स्पैसिफिकैशंज के मुताबिक मैटीरियल की खरीद की जाती है। अगर कोई टूटने वाला मैटीरियल होगा तो वह ओम प्रकाश चौटाला की खरीद वाला होगा, हमारा नहीं होगा।

Mr. Speaker: Question is—

That the Haryana Appropriation (No.2) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause-2

Mr. Speaker: Question is—

That clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-3

Mr. Speaker: Question is—

That clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Schedule

Mr. Speaker: Question is—

That Schedule be the Schedule of the Bill.

The motion was carried.

Clause-1

Mr. Speaker: Question is—

That clause I stand part of the Bill.

The motion was carried

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried

Mr. Speaker: Now, the Finance Minister will move that the Bill. be

passed.

Finance Minister (Shri Birender Singh): Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

श्रीमती सोनिया गांधी के त्याग–पत्र संबंधी संकल्प

Mr. Speaker: Now, the Chief Minister will move the resolution.

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, कल से पूरा देश जब से श्रीमती सोनिया गांधी ने लोक सभा की सदस्यता से और नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के चेयरपर्सन के पद से अपना इस्तीफा दिया है उसको पूरा देश देख रहा है। जब से देश

आजाद हुआ है तब से लेकर आज तक हमारी पब्लिक लाईफ के नैतिक मूल्यों में दिन–ब–दिन गिरावट आ रही है। लेकिन आज भी देश में श्रीमती सोनिया गांधी जैसे ऐसे नेता हैं ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने नैतिक मूल्यों के कारण अपने पद का त्याग कर दिया। हालांकि उनके ऊपर ऐसी कोई बात नहीं आई थी और न ही उनका पद आफिस ऑन प्रोफिट में शामिल था लेकिन कुछ ताकतों ने ऐसे हालात पैदा करने की शुरुआत की, कोशिश की जिसका जवाब श्रीमती सोनिया गांधी ने यह सिद्ध करके दे दिया कि वह उस परिवार की धरोहर लेकर चल रही हैं जिसने देश की आजादी से पहले कुर्बानियां और त्याग किए हैं। देश की आजादी के बाद भी चाहे श्रीमती इन्दिरा गांधी जी हों, चाहे श्री राजीव गांधी हो या चाहे श्रीमती सोनिया गांधी हो सबने कुर्बानियां दी हैं। जैसा कि पिछले पार्लियामैंट के चुनाव में हमने स्वयं देखा। मैं भी सांसद चुना गया था। हम चुनाव के समय लोगों से यह कहकर वोट लेकर आये थे कि हमारी पार्टी श्रीमती सोनिया गांधी जी को प्रधानमंत्री बनायेगी। सारे हिन्दुस्तान के लोगों ने चाहा था कि वह प्रधानमंत्री बनें। लेकिन जब उनका यूनानीमसली पार्टी लीडर का चुनाव हुआ तो उन्होंने इस पद को त्याग दिया। इसी प्रकार से कल उन्होंने जो फैसला लिया है उससे पूरे देश में उनका ऐसा व्यक्तित्व उभर कर आया है कि पूरा देश देख रहा है कि राजनीतिक नैतिकता के मूल्य कैसे होने चाहिएं। दूसरी पार्टियों का रोल भी आप देख रहे हैं। मैं एक प्रस्ताव सदन के सामने प्रस्तुत

करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि इस प्रस्ताव को पास किया जाए।

Sir, I beg to move-

Smt. Sonia Gandhi, Chairperson of United Progressive Alliance resigned yesterday from Parliament as also as Chairperson of National Advisory Council by setting highest standards of morality in public life.

This House notes with concern the gradual decline of probity, integrity and morality in public life in today's era.

This House is of the unanimous opinion that Smt. Sonia Gandhi's decision will pave the way for re-affirmation of cherished principles of political morality, unmatched integrity, selfless service and dedication to the cause of poor, downtrodden and common man and strengthen the foundation of democracy.

Mr. Speaker: Motion moved--

Smt. Sonia Gandhi, Chairperson of United Progressive Alliance resigned yesterday from Parliament as also as Chairperson of National Advisory Council by setting highest standards of morality in public life.

This House notes with concern the gradual decline of probity, integrity and morality in public life in today's era.

This House is of the unanimous opinion that Smt. Sonia Gandhi's decision will pave the way for re-affirmation of cherished principles of political morality, unmatched integrity,

selfless service and dedication to the cause of poor, downtrodden and common man and strengthen the foundation of democracy.

श्री एस० एस० सुरजेवाला (कैथल): अध्यक्ष महोदय, हाउस के नेता बहुत ही महत्वपूर्ण रैजोल्यूशन हाउस के सामने लाए हैं। मैं इसके अंदर यह ऐड करना चाहूँगा। अध्यक्ष महोदय, इससे पहले भी श्रीमती सोनिया गांधी जी को जब यू०पी०ए० सरकार बनी तो सभी पार्टियों ने सर्वसम्मति से उनको प्रधानमंत्री पद के लिए अपना नेता मान लिया था लेकिन जब भी उन्होंने ऐसा फैसला लेकर पूरी दुनिया को चकित कर दिया जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने प्रधानमंत्री के पद को ग्रहण नहीं किया। आपने देखा कि कितने दिनों तक हजारों कांग्रेसी कार्यकर्त्ताओं ने उनके घर पर धरने दिए जलूस निकाले और उनसे यह मांग की कि आप ऐसा मत करो। उसके बाद देश के लीडर उनसे मिले और संसद के सदस्य और दूसरे हाउस के मैम्बर उन पर दबाव देने के लिए मिले कि आप ऐसा मत करो। उसके बावजूद भी जो एक बहुत ही पतली सी, सादी सी महिला दिखती है वह शायद स्टील से भी ज्यादा मजबूत किसी मैटीरियल से बनी है क्योंकि वह अपने फैसले से बिलकुल टस से मस नहीं हुई। उन्होंने कहा कि मेरा यह फैसला है कि मैं प्रधानमंत्री का पद नहीं लूंगी। आपोजीशन पार्टियां खासतौर से बी०जे०पी० और दूसरी पार्टियों के नेताओं ने पूरे देश में इस विषय को लेकर जो गुब्बारा बना रखा था श्रीमती सोनिया गांधी जी ने उसमें एक

मिनट में पूरा पैंचर कर दिया, उसकी सारी हवा निकाल दी। आप देख रहे हैं कि डेढ़– दो साल से यू०पी०ए० की सरकार केन्द्र में चल रही है लेकिन उसमें किसी प्रकार का उनका कोई हस्तक्षेप नहीं है और कोई उनके खिलाफ एक भी सवाल नहीं कर सकता। आज श्रीमती सोनिया गांधी जी ने लोकसभा के सदस्य और एन०ए०सी० की चयरमैनशिप से त्याग–पत्र देकर राजनीति में बहुत ही आदर्श का मापदण्ड कायम किया है यह उनका हाई मौरल ग्राउंड है। वरना आज के गिरे हुए राजनीतिक वातावरण में, अद वातावरण में जिसमें कभी एम०पी०एल०ए०डी० कमीशन की बात आती है कभी सांसद में प्रश्न पूछने के लिए कमीशन लेने की बात पर इल्जाम लगते हैं जिसके कारण राजनीतिक लोगों पर आज जनता ने विश्वास करना बंद कर दिया है। उन लोगों का विश्वास राजनीतिक वातावरण में दोबारा से कायम करने के लिए और राजनीति को एक दिशा देने के लिए श्रीमती सोनिया गांधी ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसकी किसी भी व्यक्ति को उम्मीद नहीं थी। इसका एक कारण यह है कि एन०ए०सी० की जो श्रीमती सोनिया गांधी चेयरपर्सन थीं, वह पद आफिस ऑन प्रोफिट के लिए सैक्शन 103 के अण्डल फाल नहीं करता। उसके बावजूद भी वे मौका ही नहीं देना चाहती थी। उन्होंने इस्तीफा देकर भी एक प्रकार से विरोधी पार्टियों के गुब्बारे की हवा निकाल दी है और देश में राजनीतिक लोगों के सामने और देश की जनता के सामने एक नया रिकॉर्ड रखा है। अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय न लेते हुए सदन में यह कहना चाहूँगा जो नोट करने की बात है वह यह

है कि इनकी पार्टियों के नेता तो पूर्ण रूप से एक्सपोज हो चुके हैं। उनके पास सिवाय खुदगर्जी के कोई बात नहीं है। जबकि हमारी कांग्रेस पार्टी ने देश को दो–दो महान नेता दिए हैं, एक तो स्वर्गीय महात्मा गांधी जी थे और दूसरी श्रीमती सोनिया गांधी जी हैं जिन्होंने अपने त्याग– भावना का परिचय दिया है। इन दोनों नेताओं ने दुनियां में अपने त्याग की मिसाल कायम की है। इस बात का हमें भी गर्व है कि हम ऐसी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सदस्य हैं जिनमें ऐसे महान नेता हैं या रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने जो किया वह पूरे देश की राजनीति को आक्सीजन देगा और जो राजनीति मरने के कगार पर थी उसको जीवनदान मिलेगा।

श्री तेजेन्द्रपाल सिंह मान (पाई): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल के ऊपर रैजोल्यूशन मूव किया है और इसमें मुझे कोई सन्देह नहीं कि कल जब से यह खबर टी०वी० के ऊपर आई थी तो देश भर में एक सन्नाटा छाया हुआ है। नैतिकता के ऊपर चर्चा का विषय एक बार फिर से बना है। जैसेकि सुरजेवाला जी ने जो बताया है मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहूँगा। श्रीमती सोनिया गांधी जी ने पहले भी त्याग की एक मिसाल पैदा की और आज उन्होंने जब यह देखा कि विरोधी लोग जगह–जगह से उन पर दबाव बनाने के प्रयास कर रहे हैं तो उन्होंने अपने पद से त्याग–पत्र देकर उनकी

हवा वाकई ही निकाल दी है। उनका यह काम बड़ा सराहना का काम है। अध्यक्ष महोदय, कण्डक्ट ऑफ मैम्बर्ज, कण्डक्ट ऑफ गवर्नमैंट, कण्डक्ट ऑफ लीडर्ज की जहां तक बात है, उनके त्याग–पत्र से प्रेरणा लेते हुए हम सबको सोनिया जी को बहुत मुबारिकबाद देनी चाहिए। इस विषय के ऊपर मुख्यमंत्री जी ने जो रैजोल्यूशन पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूँ।

श्री नरेश यादव (अटेली): आदरणीय अध्यक्ष जी, सदन में जो प्रस्ताव सोनिया जी के त्याग के बारे में आज लाया गया है मैं उससे बहुत सहमत हूँ। विगत में उन्होंने प्रधान मंत्री पद का भी त्याग किया था। बार–बार ऐसा कहा जाता है कि सोनिया जी बहुत त्यागी हैं और उन्होंने त्याग किया है। लेकिन इस मौके पर मैं यहां पर एक बात कहना चाहूँगा। ....

श्री अध्यक्ष: यादव साहब, आप जानते हैं कि यह मामला सब जूडिस है। You cannot discuss it on the floor of the House. आप एक पढ़े लिखे आदमी हैं। आप अपनी सैंसिज और मैंटल फैक्लटी का प्रोपर इस्तेमाल करें। Please sit down, इनका यह वर्जन रिकॉर्ड न किया जाए।

श्री राधे श्याम शर्मा अमर (नारनौल): अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता माननीय श्रीमती सोनिया गांधी के बारे में जो प्रस्ताव ले कर आए हैं वह प्रस्ताव वाकई ही में लाने लायक प्रस्ताव है। उनके नाम पर ही सरकार ने पिछला चुनाव जीता था। जब विश्व

के सबसे बड़े प्रजातंत्र में प्रधानमंत्री का पद देने के लिए उनको चुन लिया गया था तो उनको इस पद से दूर रखने के लिंए उस वक्त खूब प्रचार हुआ था। यह पद प्राप्त करने के लिए लोग पता नहीं क्या–क्या हत्थकण्डे अपनाते हैं। आज राजनीति में इतनी गन्दगी है कि उससे हमारा सिर शर्म से झुक जाता है लेकिन उन्होंने उस राजनीति के अन्दर आज एक मिसाल कायम की है। आज लोग अगर राजनीति में किसी राजनेता का नाम लेते तो एक ही तस्वीर उभर कर सामने आती है। ऐसे राजनीतिक माहौल में सोनिया जी ने जो त्याग का आदर्श लोगों के सामने रखा है जो राजनीति में रह–रह कर गन्दगी फैलाते हैं, वे सोनिया जी के इस फैसले से एक सबक लेंगे। हम सोनिया जी को उनके त्याग के लिए और एक महान आदर्श प्रस्तुत करने के लिए बधाई देते हैं, मुबारिकवाद देते हैं। अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता को भी हम मुबारिकवाद देते हैं कि वे एक ऐसा प्रस्ताव लेकर आए हैं जो सदन के अन्दर लाने लायक था यहां पर सदन के अन्दर वे लेकर आए। धन्यवाद।

Mr. Speaker: Question is-

Smt.Sonia Gandhi, Chairperson of United Progressive Alliance resigned yesterday from Parliament as also as Chairperson of National Advisory Council by setting highest standards of morality in public life.

This House notes with concern the gradual decline of probity, integrity and morality in public life in today's era.

This House is of the unanimous opinion that Smt. Sonia Gandhi's decision will pave the way for reaffirmation of cherished principles of political morality, unmatched integrity, selfless service and dedication to the cause of poor, downtrodden and common man and strengthen the foundation of democracy.

The motion was carried.

विधान कार्य (पुनरारम्भ)

दि हरियाणा स्टेट लैजिस्लेचर (परिवैंशन ऑफ डिसक्तालिफिकेशन) अमैंडमैंट बिल, 2006

Mr. Speaker: Now, a Minister will introduce the Haryana State Legislature (Prevention of Disqualification) Amendment Bill, 2006 and will also move the motion for its consideration.

Transport Minister (Sh. Randeep Singh Su rjewala): Sir, **I** beg to introduce the Haryana State Legislature (Prevention of Disqualification) Amendment Bill, 2006.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana State Legislature (Prevention of Disqualification)

Amendment Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Haryana State Legislature (Prevention of

Disqualification)

Amendment Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is—

That the Haryana State Legislature (Prevention of Disqualification)

Amendment Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Hon'ble Members, I have received a notice of amendment from the Parliamentary Affairs Minister in Clause-1, Now, the Parliamentary Affairs Minister may move the amendment.

Transport Minister (Sh. Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to move—

That for the proposed Clause-1 of the Haryana State Legislature (Prevention of Disqualification) Amendment Bill, 2006, the following clause shall be substituted, namely ;

(1) Short title and commencement—(1) This Act may be called the Haryana State Legislature (Prevention of Disqualification) Amendment Act, 2006.

(2) It shall be deemed to have come into force at once w.e.f. 13th January, 2006."

Mr. Speaker: Motion moved—

That for the proposed Clause-1 of the Haryana State Legislature (Prevention of Disqualification) Amendment Bill, 2006, the following clause shall be substituted, namely ;

(1) Short title and commencement—(1) This Act may be called the Haryana State Legislature (Prevention of Disqualification) Amendment Act, 2006.

(2) It shall be deemed to have come into force at once w.e.f. 13th January, 2006."

Mr. Speaker: Question is—

That for the proposed Clause-1 of the Haryana State Legislature (Prevention ofDisqualification) Amendment Bill, 2006, the following clause shall be substituted, namely ;

(1) Short title and commencement—(1) This Act may be called the Haryana State Legislature (Prevention of Disqualification) Amendment Act, 2006.

(2) It shall be deemed to have come into force at once w.e.f. 13th January, 2006."

The motion was carried as amended

बैठक का समय बढ़ाना

Mr. Speaker: Is it the sense of the House that the time of the sitting be extended by 15 minutes ?

Voices: Yes.

Mr. Speaker: The time of the sitting is extended by 15 minutes.

विधान कार्य

दि हरियाणा स्टेट लैजिस्लेचर (परिवैशन ऑफ डिसक्वालिफिकेशन) अमैंडमैंट बिल, 2006 (पुनरारम्भ)

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Sub-Clause-2 of Clause-1

Mr. Speaker: Question is—

That Sub-Clause-2 of Clause-1 as amended stand part of the Bill.

The motion was carried as amended

Clause-2

Mr. Speaker: Question is—

That clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-3

Mr. Speaker: Question is—

That clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried

Sub-Clause-1 of Clause-1

Mr. Speaker: Question is—

That Sub-Clause-1 of Clause-1 as amended stand part of the Bill.

The motion was carried

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, a Minister will move that the Bill as amended be passed.

Transport Minister (Sh. Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to move--

That the Bill as amended be passed.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Bill as amended be passed.

Mr. Speaker: Question is—

That the Bill as amended be passed.

The motion was carried

14.00 बजे

दि हरियाणा म्यूनिसिपल कारपोरेशन (अमैंडमैंट) बिल, 2006

Mr. Speaker: Now, a Minister will introduce the Haryana Municipal Corporation (Amendment) Bill, 2006 and will also move the motion for its consideration.

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewaja): Sir, I beg to introduce the Haryana Municipal Corporation (Amendment) Bill, 2006.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Municipal Corporation (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Haryana Municipal Corporation (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is—

That the Haryana Municipal Corporation (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause-2

Mr. Speaker: Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried

Clause-3

Mr. Speaker: Question is—

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-4

Mr. Speaker: Question is—

That Clause 4 stand part of the Bill. The motion was carried

Clause-1

Mr. Speaker: Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, a Minister will move that the Bill be passed.

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to

move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

दि इंडियन स्टैम्प (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 2006

Mr. Speaker: Now, the Revenue Minister will

introduce the Indian Stamp (Haryana Amendment) Bill, 2006 and will also move the motion for its consideration.

Revenue Minister (Capt. Ajay Singh Yadav): Sir, I beg to introduce the Indian Stamp (Haryana Amendment) Bill, 2006

Sir, I also beg to move—

That the Indian Stamp (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Indian Stamp (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is—

That the Indian Stamp (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause-2

Mr. Speaker: Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-1

Mr. Speaker: Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried

Mr. Speaker: Now, the Revenue Minister will move that the Bill be passed.

Revenue Minister (Capt. Ajay Singh Yadav): Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried

दि हरियाणा म्यूनिसिपल (अमैंडमैंट) बिल, 2006

Mr. Speaker: Now, a Minister will introduce the Haryana Municipal (Amendment) Bill, 2006 and will also move the motion for its consideration.

Transport Minister (Sh. Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to introduce the Haryana Municipal (Amendment) Bill, 2006.

Sir, **I** also beg to move—

That the Haryana Municipal (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Haryana Municipal (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is—

That the Haryana Municipal (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motio was carried.

Mr. Speaker: Now, the Howse will consider the Bill clause by clause.

Mr. Speaker: Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-3

Mr. Speaker: Question

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-4

Mr. Speaker: Questio is—

That Clause 4 stand part of the Bill.

The notion was carried.

Clause-5

Mr. Speaker: Question is---

That Clause 5 stand part of the Bill.

The motion was carried

Clause-1

Mr. Speaker: Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now a Minister will move that the Bill be passed.

Transport Minister (Sh. Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार (अमैंडमैंट) बिल, 2006

Mr. Speaker: Now, the Education Minister will introduce Guru Jambheshwar University Hisar (Amendment) Bill, 2006 and will also move the motion for its consideration.

Education Minister (Sh. Phool Chand Mullana): Sir, I beg to introduce Guru Jambheshwar University Hisar (Amendment) Bill, 2006.

Sir, I also beg to move—

That Guru Jambheshwar University Hisar (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved—

That Guru Jambheshwar University Hisar (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is—

That Guru Jambheshwar University Hisar (Amendment) Bill be

taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause-2

Mr. Speaker: Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried

Clause-3

Mr. Speaker: Question is—

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-1

Mr. Speaker: Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, Education Minister will move that the Bill be passed.

Education Minister (Sh. Phool Chand Mullana): Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried

दि हरियाणा कोआप्रेटिव सोसायटीज (अमैंडमैंट) बिल, 2006

Mr. Speaker: Now, a Minister will introduce the Haryana Co-operative Societies (Amendment) Bill, 2006 and will also move the motion for its consideration.

Transport Minister (Sh. Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to introduce the Haryana Co-operative Societies (Amendment) Bill, 2006.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Co-operative Societies (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved -

That the Haryana Co-operative Societies (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is—

That the Haryana Co-operative Societies (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clauses 2 to 43

Mr. Speaker: Question is—

That Clauses 2 to 43 stand part of the Bill.

The motion was carried

Schedule

Mr. Speaker: Question is—

That Schedule be the Schedule of the Bill.

The motion was carried

Clause-1

Mr. Speaker: Question is—

That Clause I stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried

Mr. Speaker: Now, a Minister will move that the Bill be passed.

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to

move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Bill be passed.

श्री एस०एस० सुरजेवाला (कैथल): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को और पूरी कैबिनेट को बिल में यह अमैंडमैंट लाने के लिए बधाई देता हूँ। यह बहुत अच्छा काम सरकार करने जा रही है कि जो किसान लोन के पैसे समय पर नहीं दे पाते उनको अब गिरफ्तार नहीं किया जायेगा। इस काले कानून को हटाने की बहुत पुरानी मांग थी। हमने भी इसको हटवाने के लिए संघर्ष किया और जेलों में भी गये। चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की सरकार ने रिकवरी न देने पर किसानों को गिरफ्तारी का प्रोविजन बिल के स्टेचू सै निकाल कर बहुत अच्छा काय किया है और किसानों को मान सम्मान दिया है। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त किसानों की एक मांग यह भी है कि कर्जा न दे पाने पर किसानों की भूमि की नीलामी न की जाये। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी सरकार ऐसा भी करेगी। 50 प्रतिशत ठीक कार्य तो सरकार ने अभी कर दिया और 50 प्रतिशत ठीक कार्य

आने वाले समय में कर देगी। अध्यक्ष महोदय, सदन का ज्यादा समय न लेते हुए एक और महत्वपूर्ण बात मैं यह कहना चाहूँगा कि हमारे प्रदेश में इस समय 2000 से ज्यादा सोसायटीज हैं जिनको कम करके 800 के करीब सरकार करना चाहती है। अगर 5–5, 10–10 गांवों पर एक–एक सोसायटी होगी तो बैंक क्या काम करेंगे। ऐसा होने पर किसानों को पूरा लाभ नहीं मिलेगा। इस बारे में मेरी प्रार्थना है कि जो सोसायटीज वायबल नहीं हैं उनको दूसरी सोसायटीज के साथ जोड़ दिया जाये लेकिन इतनी भी कम न करें कि किसानों को दूर–दूर जाना पड़े। कोऑपरेटिव बैंक तो शहर में भी हैं। (विघन)

श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मान (पाई): अध्यक्ष महोदय, जैसा कि भाई सुरजेवाला जी ने कहा कि कर्जा न चुकाने पर किसानों को गिरफ्तार न करने के लिए सरकार बहुत अच्छा अमैंडमैंट लेकर आई है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी पहले ही हिसार में कहकर आये थे कि किसानों की कर्जे की वसूली के बारे में अब गिरफ्तारी नहीं की जायेगी। लेकिन इसमें अमलगामेशन करके नई रि–स्ट्रैक्चरिंग करने की सरकार की जो नई पालिसी है उसके बारे में मैं जरूर कहना चाहूँगा। कोआप्रेटिव का मुझे बहुत बड़ा अनुभव होने के कारण मैं बताना चाहूँगा कि कई सालों की मेहनत के बाद हम गांव–गांव तक सोसायटीज और मिनी बैंक पहुंचाने में कामयाब हुए हैं। हर जगह स्ट्रैक्चर है, आदमी हैं और अब हम वापिस हो रहे हैं। यदि

हम सोसायटीज को कम कर देंगे और 10– 15 कि०मी० की दूरी हो जायेगी तो इससे किसानों को कोई फायदा नहीं होगा। सरकार किसानों को जो रिलीफ देना चाहती है वह नहीं दे पायेगी। सोसायटीज के कम करने से गरीब किसानों का खर्चा बढ़ जायेगा। क्योंकि किसानो को सोसायटीज कम करने पर 15 कि०मी० का सफर करना पड़ेगा। इसलिए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि सरकार इस पर पुनर्विचार करे और सारे आसपैक्ट्स को देख ले।

बैठक का समय बढ़ाना

Mr. Speaker: Is it the sense of the House that the time of the House be extended by 5 minutes.

Voices: Yes, yes.

Mr. Speaker: Time of the House is extended by 5 minutes.

विधान कार्य

दि हरियाणा कोआप्रेटिव सोसायटीज (अमैंडमैंट) बिल, 2006
(पुनरारम्भ)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः स्पीकर सर, हरियाणा कोआप्रेटिव सोसायटीज (अमैंडमैंट) बिल, 2006 जो सरकार लाई है वह सही मायने में ऐसा कानून है जो हरियाणा के कोआप्रेटिव सैक्टर के इतिहास में एक मील पत्थर साबित होगा। स्पीकर

साहब, सैक्सन 104 से 110 जो हैं आप भी जानते हैं क्योंकि आप ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं और आप स्वयं भी कई बार इसके लिए आन्दोलनरत रहे हैं और अग्रणी भूमिका निभाते रहे हैं। बैंकों की जीप आया करती थी और छोटे–छोटे ऋण के लिए किसानों को पकड़ कर ले जाती थी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सरकार का एक साल का अरसा जब पूरा हुआ तो हरियाणा सरकार की नव–निर्माण रैली में पांच मार्च को यह वायदा किया था कि किसानों की इज्जत पर हमला बोलने वाले इस काले कानून को हम समाप्त करेंगे। इस कानून को हम लेकर आए हैं जिसके बाद किसी किसान, किसी मजदूर की इज्जत पर कोई व्यक्ति हमला नहीं करेगा। केवल इसलिए कि उसकी कुछ राशि डयू है इसलिए उसको गिरफ्तार किया जाए। उस कानून को खत्म करने का प्रावधान हम लेकर आए हैं। स्पीकर साहब, इसमें तीन महत्वपूर्ण बातें हैं। मैं इस बारे हाउस का ध्यान आकर्षित करूंगा। इससे पहले माननीय सुरजेवाला जी और मान साहब ने अमलगामेशन ऑफ सोसायटी की बात उठाई। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन को और माननीय साथियों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि ऐसा कोई प्रावधान इस बिल के अन्दर नहीं है। स्पीकर सर, अगर इस बिल की सैक्शन 13 को दोबारा देखें तो इससे यह बात बड़ी स्पष्ट हो जाएगी कि हमने सोसायटी की अमलगामेशन का प्रावधान इस बिल में नहीं किया। वे सोसाइटीज जो सरकार का हिस्सा हैं वहां दो सोसायटीज इकट्ठा होती रही हैं और ऐसा डायरैक्ट करके वे एक से दो बनाना चाहें यह उनकी मर्जी है।

स्पीकर साहब, सैक्शन 13 का प्रोवाइजो पढ़ें तो उसमें यह स्पष्ट लिखा है कि जिस सोसायटी में सरकार का हिस्सा है वहां पर अमलगामेशन के लिए आपको रजिस्ट्रार, कोआप्रेटिव सोसायटीज की परमीशन लेनी पडेगी इसलिए इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। माननीय साथियों द्वारा जो शंकाएं जाहिर की गई हैं हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। स्पीकर साहब, इस कानून के माध्यम से सरकार ने गरीब वर्गों खासतौर से दलितों और पिछड़े वर्गों के लिए एक विशेष प्रकार का आरक्षण दिया है। यह आरक्षण हरियाणा के गठन के बाद कभी भी नहीं हुआ है यह पहली बार किया गया है। स्पीकर साहब, आप जानते हैं कि अब से पहले सैक्शन 28 और 29 में दलित वर्ग के लोगों को नामिनेटिड मैम्बर के कॉम्पोनैंट में लेकर लाया जाता था और जो इलैक्टिड लोग थे उन्हें हीनभावना की दृष्टि से देखते थे। स्पीकर सर, हमने यह प्रावधान किया है कि एस०सी० का मैम्बर और एक महिला को अब सोसायटीज के अन्दर इलैक्टिड कोम्पोनैंट के अन्दर रखना अनिवार्य है, इसलिए उनके लिए पद आरक्षित कर दिये गये हैं। स्पीकर सर, इसी प्रकार से जिस सोसायटी में 10 परसैंट मैम्बर्ज बी०सीज० के होंगे वहां पर भी एक पद बी०सी० के लिए इलैक्टिड कॉम्पोनैंट के लोगों की तरह आरक्षित रखना पड़ेगा। चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की सरकार ने दलित भाइयों को, पिछड़े वर्ग के भाइयों को और हमारी बहनों को यह अधिकार दिया है कि वे इलैक्टिड कॉम्पोनैंट के अन्दर चुनकर आएंगे। स्पीकर सर, एक छोटी सी बात और है जो हमेशा कोआप्रेटिव सोसायटीज की फक्सनिंग में अड़चन डालती

थी। वह यह थी कि जो मैनेजिंग कमेटी है वह सोसायटी पर अपना प्रभुत्व मान लेती थीं और सदस्यों की राय नहीं ली जाती थी, लेकिन सैक्शन 25 और 26 में हम अमैंडमैंट करके प्रावधान लेकर आए हैं कि अगर मैनेजिंग कमेटी जनरल बॉडी की मीटिंग नहीं करेगी तो पांच साल के लिए उन्हीं को डिस्लालीफाई कर दिया जाएगा। सोसायटी के हर सदस्य को सोसायटी के कार्य के अन्दर अपनी राय जाहिर करने का मौका मिलेगा। स्पीकर सर, यह एक बहुत ही ऐतिहासिक कानून है जो इस सदन के सामने रखा गया है। मैं आपसे और सदन से अनुरोध करूँगा कि इस कानून को पारित कर दिया जाए।

Mr. Speaker: Question is—That the bill be passed.

The motion was carried.

धन्यवाद देना

श्री अध्यक्ष: ऑनरेबल मैम्बर्ज, इस हाउस को चलाने में आपने जो को – आप्रेशन और हैल्प दी है उसके लिए आप सभी का बहुत–बहुत धन्यवाद। Now, the House stands adjourned sine die.

11.00 बजे

(The Sabha then *adjourned sine die.)